राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

कोहली के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज से जीती सीरीज >>11

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 67

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 16 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 12

जनता ने काम करने भेजा है, काम करूंगा

मोदी बोले ▶ अनुच्छेद 370 व 35ए हटाने से 'एक देश, एक संविधान' का सपना साकार

कहा, जम्मू-कश्मीर पर फैसला नए भारत की सोच, 'एक देश एक चुनाव' पर चर्चा की है जरूरत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अभूतपूर्व जनमत के साथ सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 दिनों में उठाए गए बड़े कदमों का जिक्र करते हुए गुरुवार को यह घोषणा भी कर दी है कि अब समस्याओं को पालने और टालने का वक्त खत्म हो गया है। अब निराकरण के लिए कदम उठेंगे। जनता ने उन्हें जो काम करने के लिए भेजा है, वह काम पूरा करेंगे। संदेश साफ है कि आने वाले समय में भी बड़े साहसिक कदमों की आशा की जानी चाहिए। वहीं, राजनीतिक विरोधियों के लिए भी संदेश है कि वे जन आकांक्षाओं को समझें। उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35ए को सत्ता में वापसी के 70 दिन के अंदर खत्मकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को नए भारत की सोच का हिस्सा बताया। कहा-इस फैसले के बाद हर नागरिक कह सकता है कि अब 'एक देश एक संविधान' है। 'एक देश एक चुनाव' पर चर्चा की जरूरत बताते हुए मोदी ने कहा कि जीएसटी के जरिये 'एक देश एक टैक्स', 'एक देश एक ग्रिड' और 'एक देश एक मोबिलिटी कार्ड' की व्यवस्था शुरू हो चुकी है।

अपने दूसरे कार्यकाल में लाल किले की प्राचीर से पहले संबोधन में पीएम ने नए भारत के अपने वादे का रोडमैप देश के सामने पेश किया। जनभागीदारी से बड़ी अहम चुनौतियों का समाधान निकालने के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास को नए पायदान पर ले जाने का लक्ष्य तय करते हुए मोदी बोले, अब समय धीरे चलने का नहीं, लंबी छलांग लगाने का है। एक देश एक चुनाव की पैरोकारी, तीनों सेनाओं के संयुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बनाने, जनसंख्या विस्फोट रोकने, जल जीवन मिशन के साथ 100 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे की कार्ययोजना के साथ नए भारत की मंजिल को गति देने का एलान भी किया।

देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार छठी बार लाल किले पर तिरंगा लहराने के बाद प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर का स्वरूप बदलने को नए भारत का नजरिया करार दिया। सफेद कुर्ता-पायजामा पहने और सिर पर रंगीन साफा बांधे मोदी ने डेढ़ घंटे से अधिक के अपने संबोधन की शुरुआत कश्मीर के बड़े फैसले की चर्चा से की। उन्होंने कहा, 2014-19 का पहला कालखंड जरूरतों की पूर्ति का दौर था और 2019 के बाद का कालखंड देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का समय है। पीएम ने कहा, अब समस्याओं का समाधान टुकड़ों में नहीं सोचा जा सकता बल्कि इन्हें जड़ से मिटाना होगा। उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के कदम को जम्मू-कश्मीर की समस्या के हल की दिशा में निर्णायक कदम करार दिया। मोदी बोले, 'हम समस्याओं को टालते भी नहीं और पालते भी नहीं, अब समस्याओं को टालने और पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के 70 दिन के भीतर-भीतर हो गया। इसका मतलब साफ है कि हर किसी के दिल में यह बात थी मगर शुरुआत कौन करे, इसका इंतजार था। देशवासियों ने मुझे यह काम दिया तो मैं वही काम करने आया हूं। मेरा अपना कुछ नहीं है।' पीएम ने अनुच्छेद 370 हटाने के कदम को साहसिक फैसले लेने की अपनी सरकार की दृढ़ता का प्रमाण बताया, वहीं राजनीतिक दलों में इस पर जारी अंदरूनी घमासान को भी रेखांकित किया।

सती, दहेज प्रथा पर कानून बन सकता है तो तत्काल तीन तलाक पर क्यों नहीं : पीएम ने मुस्लिम महिलाओं को तत्काल तीन तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिलाने का कानून बनाने के फैसले को भी शासन के नए तेवर और कलेवर का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या रोकने के कानून बनाए जा सकते हैं तो मुस्लिम बहनों को समान अधिकार की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल तीन तलाक के खिलाफ कानून क्यों नहीं।

जल जीवन मिशन योजना का एलान पेज>>3

73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित समारोह में गॉर्ड ऑफ ऑनर लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

किस साल, कितना लंबा भाषण

साल	अवधि
2014	65 मिनट
2015	86 मिनट
2016	96 मिनट
2017	56 मिनट
2018	80 मिनट
2019	95 मिनट

...तो अनुच्छेद 370 को स्थायी क्यों नहीं बना दिया?

मोदी ने कहा कि जब देश इस पर पूरा समर्थन दे रहा है तो राजनीतिक दल भी अपवाद नहीं हैं। कोई खुला तो कोई मूक समर्थन कर रहा है। मगर चुनाव के तराजू से तौलने वाले कुछ लोग अब अनुच्छेद 370 की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, 'ये दोनों अनुच्छेद इतने महत्वपूर्ण थे तो इन्हें अस्थायी क्यों रखा, क्यों नहीं इन्हें संविधान का स्थायी हिस्सा बना दिया? इसका मतलब यह है कि वे भी मानते थे कि यह सही नहीं हुआ था, मगर सुधार करने की उनकी हिम्मत नहीं थी।'

पहली बार बनेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

सरकार की ओर से सीडीएस की व्यवस्था किए जाने से तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।

ऐतिहासिक सुधार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से किया यह बड़ा एलान
- 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद से ही सीडीएस व्यवस्था पर चल रहा है मंथन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नई व्यवस्था जल्द शुरू करने का एलान किया। इसके तहत चार स्टार वाले जनरल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख इनके अधीन होंगे। सीडीएस तीनों सेनाओं का एकीकृत नेतृत्व करेगा।

तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने की लंबे समय से चर्चा चल रही थी। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री ने इसका एलान करते हुए कहा कि सैन्य क्षेत्र से जुड़े सुधारों के क्रम में सीडीएस को लेकर तमाम रिपोर्ट और चर्चाओं में इसकी मांग उठी। इसीलिए निर्णय लिया गया कि सीडीएस की व्यवस्था होगी और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं को शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। यह फैसला सामरिक सुधार के एजेंडे का अहम हिस्सा है।

पीएम ने कहा कि आज युद्ध का दायरा और रंग-रूप बदल रहा है। तकनीक आधारित व्यवस्थाएं बन रही हैं। ऐसे में भारत की तीनों सेनाएं एक-दूसरे से पीछे न रहें, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। हमारी पूरी सैन्यशक्ति एकमुश्त होकर एक साथ आगे बढ़े। हमारी सेनाएं विश्व में बदलते युद्ध और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हों, इसका ध्यान रखते हुए ही सीडीएस के गठन का यह अहम फैसला लिया गया है।

दो दशक से चल रही चर्चा : चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के गठन की जरूरत 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद से ही महसूस की जा रही है। इस युद्ध के बाद बनी कारगिल समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार सीडीएस की सिफारिश की थी। 2012 में रक्षा क्षेत्र के सुधारों पर बनी नरेश चंद्रा कमिटी ने भी चार स्टार जनरल को सीडीएस बनाने की सिफारिश करते हुए तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के लिए इसे जरूरी बताया था। यूपीए सरकार के समय इसके गठन की पहल भी शुरू हुई पर सिरे नहीं चढ़ पाई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी दो-तीन मौकों पर इसकी गंभीर पहल हुई मगर तब भी यह फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाई।

सीडीएस की नियुक्ति से फायदे : सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख की तरह काम करेगा और सरकार के लिए एकल सैन्य सलाहकार होगा। तीनों सेनाओं के लिए लंबी अवधि की योजनाओं, खरीदारी और प्रशिक्षण जैसे कार्यों में समन्वय की भूमिका सीडीएस की रहेगी। सीडीएस की नियुक्ति से सैन्य खरीद को गति मिलेगी। इससे किसी तरह की व्यवस्था या खरीद में दोहराव की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है और यहां सीडीएस परमाणु हथियारों के मामले में प्रधानमंत्री के सलाहकार की भूमिका भी निभाएगा।

अभी क्या है व्यवस्था? : वर्तमान समय में तीनों सेना प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ को चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ (सीओएससी) नियुक्त किया जाता है। हालांकि यह पद केवल एक अतिरिक्त भूमिका की तरह होता है और इसका कार्यकाल भी आमतौर पर बहुत कम रहता है। 31 मई को वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा से यह जिम्मेदारी ली थी। 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होते ही धनोआ इस पद से भी मुक्त हो जाएंगे। उनके बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत सीओएससी बनेंगे। वह भी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

कई देशों में है इस तरह का पद : सभी बड़े देशों, विशेषतौर पर परमाणु शक्ति संपन्न देशों में सीडीएस जैसा पद है। अमेरिका में चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की नियुक्ति होती है। वहीं कनाडा, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में सीडीएस का पद है। ब्रिटेन में सीडीएस के साथ-साथ परमानेंट सेक्रेटरी का भी पद है। परमानेंट सेक्रेटरी की भूमिका रक्षा मामलों में प्रधान नागरिक सलाहकार की होती है। रक्षा क्षेत्र में नीति निर्धारण, वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं में इसकी भूमिका रहती है।

सीडीएस पर सरकार ने सेनाओं से मांगी है राय

नई दिल्ली, एएनआइ : देश में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति की दिशा में सरकार कदम बढ़ा चुकी है। इस संबंध में तीनों सेनाओं से राय मांगी गई है। नए पद की रूपरेखा तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। अगले कुछ हफ्तों में सेनाओं की ओर से इस संबंध में राय मिलने की उम्मीद है। सीडीएस से जुड़ी व्यवस्था तैयार करने का काम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के परामर्श और रक्षा मंत्रालय की मदद से किया जा रहा है। सीडीएस की भूमिका और कार्यकाल जैसे बिंदुओं पर निर्णय के बाद इस दिशा में बढ़ा जाएगा। (पेज-5)

न्यूज गैलरी

सिटी न्यूज ▶ पृष्ठ 2

29 अक्टूबर से डीटीसी बसों में महिलाओं का सफर होगा मुफ्त

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में एलान किया कि 29 अक्टूबर से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर करेंगी। उन्होंने कहा, आज दिल्ली की सभी बहनों के लिए फर्ज अदा कर रहा हूं।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई आज

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले और उसके बाद राज्य में मीडिया और अन्य संचार माध्यमों पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ मामले की सुनवाई करेगी।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 9

इफको का तोहफा, खादों के दाम 50 रुपये घटाए

नई दिल्ली : देश की अग्रणी को-ऑपरेटिव संस्था इफको ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों को उर्वरकों की कीमत में कमी का तोहफा दिया है। इफको ने डीएपी और एनपीके खादों के दाम 50 रुपये प्रति बोरी घटा दिए हैं। ताजा कटौती के बाद डीएपी के दाम प्रति बोरी 1,250 और एनपीके-1 (नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटाशियम) की कीमत प्रति बोरी 1,200 रुपये हो गई है। उर्वरकों की घटी हुई कीमतें गुरुवार से ही लागू हो गई हैं।

चीन फिर पाक के साथ, कश्मीर पर यूएन की आपात बैठक आज

- खुले में वार्ता की पाकिस्तान की अपील ठुकराई, अब बंद कमरे में होगी बातचीत

संयुक्त राष्ट्र, एएफपी : कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए चीन की मांग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई है, जो बंद कमरे में होगी। सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष पोलैंड ने इस मुद्दे को चर्चा के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध कर दिया। बता दें कि चीन ने पैंतरा बदलते हुए पाक की मांग का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की थी। इससे पहले पाक ने कश्मीर मसले पर खुले में वार्ता के लिए बैठक बुलाने की मांग थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ठुकरा दिया था।

बैठक की जानकारी देते हुए राजनयिकों ने कहा, चीन ने सुरक्षा परिषद से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 'बंद कमरे' में बैठक बुलाने को कहा था। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पाक अपने विश्वसनीय सहयोगी चीन का समर्थन प्राप्त करने की निरंतर कोशिश कर रहा था। एक राजनयिक ने बताया कि पाक ने कश्मीर मसले पर खुले में वार्ता करने के लिए अगस्त माह में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पोलैंड को पत्र लिखा था। राजनयिक ने कहा, 'चीन ने सुरक्षा परिषद की कार्यसूची में शामिल 'भारत-पाकिस्तान सवाल' पर चर्चा की मांग की थी। यह मांग पाक की ओर से सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे पत्र के संदर्भ में की गई थी।'

इससे पहले जियो न्यूज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जोआना रोनेका के हवाले से कहा था कि सुरक्षा परिषद जम्मू-कश्मीर मसले पर चर्चा करेगी। बैठक के समय के बारे में पूछे जाने पर रोनेका ने कहा था कि संभवतः यह बैठक शुक्रवार को हो, क्योंकि गुरुवार को सुरक्षा परिषद की बैठक नहीं होती।

बता दें कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना उसका आंतरिक मामला है और उसने पाक से भी इसे स्वीकार करने की सलाह दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारत-पाक से संयम बनाए रखने तथा शिमला समझौते के तहत विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है।

भारत ने चीन से कहा, आंतरिक मामला पेज>>10

पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब, दुश्मन के तीन सैनिक ढेर

- पुंछ में की थी भारी गोलाबारी, भारतीय सेना ने कई बंकर किए तबाह
- सीमा पर नजर आईं पाक सेना की कई एंबुलेंस, बड़े नुकसान का अनुमान

जागरण संवाददाता, जम्मू

स्वतंत्रता दिवस के दिन पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इस पर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तानी सेना के तीन जवान मार गिराए। साथ ही दुश्मन के कई बंकर भी नष्ट कर दिए। इसके अलावा पाकिस्तान के कई सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। वहीं, पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक ट्वीट कर दावा किया कि गोलाबारी में भारत के पांच सैनिक मारे गए हैं। जबकि भारत की ओर से उसके इस दावे को सिरे से नकार दिया गया है। भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से किया गया पांच भारतीय सैनिकों के शहीद होने की बात पूरी तरह से आधारहीन है।

पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार शाम करीब पांच बजे कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी शुरू कर दी। पाक सेना इस गोलाबारी की आड़ में आतंकवादियों के दल को भारतीय क्षेत्र में दाखिल करवाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने इस प्रयास को विफल कर दिया और जवाबी कार्रवाई करते हुए पलटवार किया। भारत की ओर से की गई इस जवाबी कार्रवाई में पाक सेना के तीन जवान मारे गए हैं। जबकि कई जवान घायल हो गए और पाक सेना के कई बंकर भी नष्ट हो गए। गोलाबारी के दौरान पाक सेना की कई एंबुलेंस सीमा के करीब आती नजर आई। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पाक सेना का जवाबी कार्रवाई में काफी नुकसान हुआ है।

भारतीय सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पाक सेना के सिपाही रमजान, लांस नायक तैमूर और नायक तनवीर मारे गए। इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाक सेना ने गोलाबारी को बंद कर दिया।

छत्तीसगढ़ में एससी-एसटी और ओबीसी को 72 फीसद आरक्षण

संजीत कुमार, रायपुर

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की यह बड़ी घोषणा
- कांग्रेस सरकार ने खेला बड़ा दांव, अभी तक तीनों वर्गों का 58 फीसद था आरक्षण

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का कोटा 58 से बढ़ा कर 72 फीसद करने का एलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोटे में 14 फीसद इजाफे की घोषणा की। राज्य में अभी तक एसटी को 32, एससी को 12 और ओबीसी वर्ग को 14 फीसद आरक्षण मिल रहा था। सरकार ने इसे बढ़ाकर क्रमशः 32, 13 और 27 करने का फैसला किया है। जहां एक ओर इस फैसले का स्वागत हो रहा है, वहीं आरक्षण के 50 फीसद की तय सीमा लांघने की चिंता भी बढ़ गई है। ध्यान रहे पिछली बार कोटे में किए गए बदलाव को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ज्ञात हो, राज्य में चार माह बाद निकाय चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में लगे झटके को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार जोखिम (रिस्क) लेना नहीं चाहती।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला : पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 18 जनवरी 2012 को आरक्षण नीति में बदलाव किया था। इसके तहत लोक सेवा (अजा, अजजा एवं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा चार में संशोधन किया गया था। इसके अनुसार अनुसूचित जनजाति को 32, अनुसूचित जाति को 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 फीसद आरक्षण देना तय किया था। इस प्रकार कुल आरक्षण 58 फीसद होता है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 फीसद की सीमा से अधिक है। इसके खिलाफ 2012 में ही गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी रायपुर, सतनाम सेवा संघ रायपुर, पीआर खुंटे समेत अन्य ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं लगाई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को सुनवाई के लिए हस्तांतरित कर दिया था, मामला अभी लंबित है।

लद्दाख में जश्न

अनुच्छेद-370 हटने के बाद लद्दाख ने मनाया अपना पहला स्वतंत्रता दिवस, तिरंगा फहराने के बाद बोले सांसद, लद्दाख को कश्मीर से मिली आजादी, 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित राज्यों में बंट जाएगा

सड़क पर नाच सांसद जामयांग ने मनाया स्वतंत्रता दिवस

जेएनएन, नई दिल्ली

आजादी का जश्न पूरे देश में मना, लेकिन अनुच्छेद-370 हटने के बाद देशभर की नजरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर थीं। कश्मीर में तो समारोह में भीड़ कम रही, लेकिन अनुच्छेद-370 हटने के बाद अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहे लद्दाख का जश्न सबसे अलग रहा। इसकी चर्चा सबकी जुबान पर रही और वीडियो भी खूब वायरल हुआ। इसका कारण बने लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल। उन्होंने जनता के साथ सड़क पर नाच कर खुशी का इजहार किया। जामयांग ने कहा, लद्दाख को कश्मीर और वहां की सियासत से आजादी मिल गई है। ऐसे में यह जश्न तो ट्रेलर है। इससे पूर्व उन्होंने भाजपा महासचिव राम माधव के साथ पार्टी ऑफिस में झंडा फहराया।

ज्ञात हो, पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया था। ऐसे में 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित राज्यों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बदल जाएगा। सांसद ने ट्वीट किया-लद्दाख के हर घर में तिरंगा लोगों की देशभक्ति व भारत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे पूर्व लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद जब जामयांग पहली बार अपने क्षेत्र पहुंचे थे तो तब भी समर्थकों संग तिरंगा लेकर नाचे थे।

लोकसभा में दमदार भाषण से सुर्खियों में आए लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल स्वतंत्रता दिवस समारोह पर डांस करके फिर सोशल मीडिया में छा गए। लद्दाख में लोगों के साथ लोकनृत्य 'जबरो' करते जामयांग (मध्य में)। प्रेट्र

पीडीपी और नेकां पर साधा था निशाना : संसद में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और लद्दाख को केंद्र शासित बनाए जाने के बिल पर चर्चा के दौरान जामयांग के भाषण की काफी चर्चा हुई थी। उन्होंने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 की वजह से लद्दाख की पहचान छुपी रही। कश्मीर के नेता केंद्र से पैसा ले जाकर घाटी में ही रखते थे। इसके चलते लद्दाख पूरी तरह से पिछड़ा रह गया।

शहीदों को किया नमन : जामयांग शेरिंग ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दौरान उन्होंने उन चार युवा नायकों को भी नमन किया, जिन्होंने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कुछ साल पहले आंदोलन करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे। (संबंधित खबरें पेज-4)

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2020
6 Aug | 12 Sept

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक
- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- निबंध लेखन - शैली, PT 365, Mains 365, सीसैट कक्षाएं
- मुख्य परीक्षा, निबंध, PT, सीसैट टेस्ट सीरीज

अभ्यास मेन्स 2019
ऑल इंडिया GS मेन्स मॉक टेस्ट (ऑफलाइन)

30 शहरों में
Also in English Medium
GS-I & GS-II 24 अगस्त | GS-III & GS-IV 25 अगस्त
पंजीकरण करें www.visionias.in/abhyaas

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | COIMBATORE
DEHRADUN | DELHI | GHAZIABAD | GREATER NOIDA | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JAIPUR
JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOLKATA | LUCKNOW | MUMBAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE
RAIPUR | RANCHI | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VISAKHAPATNAM

DELHI
- 635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
- 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
- Contact : 8468022022, 9019066066, 9650617807

JAIPUR 9001949244 | PUNE 8007500096 | HYDERABAD 9000104133 | AHMEDABAD 9909447040 | LUCKNOW 8468022022

1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से यमुना में। शुक्रवार शाम तक इसके दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के बाढ़ व सिंचाई नियंत्रण विभाग के अनुसार यहां यमुना में इस बार बाढ़ के आसार नहीं हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 16 अगस्त 2019

मिलेगा तोहफा ▸ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा

29 अक्टूबर से डीटीसी बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि 29 अक्टूबर से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर करेंगी। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की अपनी सभी बहनों के लिए मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। इससे बहनों की सुरक्षा बढ़ेगी। उनका सशक्तीकरण होगा। वे अपने सपने हासिल करने के लिए मजबूत बनेंगी।

केजरीवाल ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि दिल्ली की सभी बसों में और मेट्रो में सभी महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की जाएगी। आज मैं उसमें से पहली घोषणा करना चाहता हूं। 29 अक्टूबर को भाई दूज का दिन है। इस दिन से दिल्ली की सभी बसों- डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए सफर मुफ्त होगा। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि केजरीवाल सब कुछ मुफ्त करते जा रहे हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं पैसे खा नहीं रहा। पैसों की चोरी करके स्विस बैंकों में जमा नहीं करा रहा। आपके ही टैक्स के पैसे जो कल तक चोरी हो जाया करते थे, उन्हें बचा कर दिल्ली के लोगों पर खर्च कर मुफ्त सेवाएं दे रहा हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर दिल्ली के बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं तो क्या वह गलत है। हम निजी स्कूलों के मुकाबले शानदार शिक्षा सरकारी स्कूलों में मुफ्त में दे रहे हैं। मोहल्ला क्लीनिक के अंदर, पॉली क्लीनिक व अस्पतालों के अंदर अगर लोगों को फ्री दवाइयां, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त ऑपरेशन कर रहे हैं, तो बताइए कि क्या गलत कर रहे हैं? क्या दिल्ली की जनता का मुफ्त में इलाज नहीं होना चाहिए? अगर हम लोगों ने पैसे बचाकर आपकी 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी, आपका पानी मुफ्त कर दिया तो बताइए कि क्या गलत किया? आज मंदी का दौर है। लोगों की तनख्वाह बढ़ नहीं रही है। कारोबार बंद हो रहे हैं, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपका मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी बिजली और पानी मुफ्त करके आपके जेब में तीन-चार हजार रुपये डाल देता हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? मैंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। कुछ लोगों का कहना है कि केवल महिलाओं का टिकट मुफ्त क्यों किया जा रहा है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलता है? नहीं मिलता। दिल्ली में जितने भी कामकाजी लोग हैं, उनमें से 11 फीसद महिलाएं हैं। आज दिल्ली की बसों में, मेट्रो में केवल 30 फीसद महिलाएं सफर करती हैं। हमारे प्रयास से महिलाओं को अपने सपने पूरे करने में बड़ी सहायता मिलेगी।के बेटियां, जिन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, लेकिन कॉलेज घर से बहुत दूर है और वहां तक जाने में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वे कॉलेज जा सकेंगी। जिनका स्कूल बहुत दूर है, आने-जाने के पैसे नहीं हैं तो घरवाले कहते थे कि रहने दो। ऐसी बेटियां स्कूल जा सकेंगी। ऐसे महिलाएं, जो काम करना चाहती हैं, लेकिन काम की जगह बहुत दूर है, आने-जाने के लिए पैसे नहीं हैं, अब ऐसी महिलाओं के सपने पूरे होंगे।

सरकारी स्कूलों में लागू होगा देशभक्ति-पाठ्यक्रम : अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर निजी स्कूलों से बेहतर हो गया है। नतीजे शानदार आने लगे हैं। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा के तीन लक्ष्य होने चाहिए- अच्छा इंसान बने, अपने परिवार के भरण-पोषण लायक बने, सच्चा देशभक्त बने। मुझे बेहद खुशी है कि हैप्पीनेस पाठ्यक्रम बच्चों को अच्छा इंसान बना रहा है। शिक्षा को लेकर गांधी जी के बताए गए दो लक्ष्यों पर हम काम कर रहे हैं। तीसरी बात पर अब काम करने का समय आ गया। अब सरकारी स्कूलों में देशभक्ति का पाठ्यक्रम लागू होगा। देश भर के लोगों से राय लेकर देशभक्ति-पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। उम्मीद है कि अगले शैक्षणिक सत्र से इसे लागू कर दिया जाएगा।

सीसीटीवी लगने से महिलाओं को सुरक्षा की अनुभूति हो रही : मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अंदर अपनी बहनों की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित रहता हूं। दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है लेकिन हमारे अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी आता है, हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। जहां-जहां सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, वहां-वहां से खासतौर पर महिलाएं मुझसे मिलने आ रही हैं। वे बहुत खुश हैं। उन्हें अब सुरक्षा की अनुभूति हो रही है। वे जब घर से बाहर निकल रही हैं तो सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

मैं आप में से एक हूं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है : अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पांच साल पहले आप लोगों ने हमें चुनकर हमारी सरकारी बनाई। मेरे जैसे आम आदमी को दिल्ली की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। यह केवल बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की वजह से हुआ कि एक आम आदमी भी इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता है। मैं आप में से एक हूं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं किसी राजनीतिक व किसी रईस परिवार से नहीं आता। मैं आम आदमी हूं। यही कारण है कि आपकी समस्याओं को समझ पाता हूं।

छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुफ्त सफर से महिलाओं का सशक्तीकरण होगा। जागरण

महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा पर भाजपा ने उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा की घोषणा पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि बसों की कमी दूर किए बगैर इस तरह की घोषणा का कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली के भविष्य को दरकिनार कर रहे हैं। वह केवल लोक-लुभावने वादे कर दिल्ली को बर्बाद करने पर तुले हैं। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने में असफल रहने के बाद मुफ्त यात्रा की घोषणा से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बना तरक्की के नए आयाम रचने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश की राजधानी का विकास करने में असफल रहे मुख्यमंत्री राजनीतिक जमीन बचाने के लिए मुफ्त योजनाओं के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन बसों की कमी दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। साढ़े चार साल पहले जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय डीटीसी के बेड़े में पांच हजार बसें थीं जो कि अब कम होकर 3800 रह गई हैं। इनमें से भी अधिकांश जर्जर स्थिति में हैं। लोग बस के इंतजार में बस स्टॉप खड़े रहते हैं। यदि बस आती है तो उसमें भी इतनी भीड़ होती है कि महिलाएं सवार नहीं हो पाती हैं। जब बसें ही नहीं हैं तो फिर मुफ्त सफर की घोषणा का फायदा किसे होगा। जनता यह समझ रही है कि चुनावी फायदे के लिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। मतदाता अब मुख्यमंत्री के बहकावे में नहीं आएंगे।

शाहबेरी मामले में बीस बिल्डरों के खिलाफ फिर दर्ज हुई एफआइआर

जासं, ग्रेटर नोएडा : शाहबेरी के खरीदारों के हंगामे की गूंज जैसे-जैसे तेज होती जा रही है उप्र के मुख्यमंत्री की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मामले में जिला प्रशासन के लापरवाह रवैये पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिल्डरों पर कार्रवाई के मामले में अधिकारी रिश्तेदारी न निभाएं। शासन के आदेश के बाद बिसरख पुलिस ने बीते तीन अगस्त को दर्ज किए गए 27 बिल्डरों के मुकदमे में बदलाव किया है। पहले इन बिल्डरों के नाम एक ही एफआइआर में दर्ज किए गए थे। बदलाव करते हुए अब हर बिल्डर की अलग-अलग एफआइआर हुई है। बिसरख पुलिस ने अब 20 मुकदमे दर्ज किए हैं। साथ ही दबिश देकर एक बिल्डर को गिरफ्तार भी किया है। दबाव के बाद अन्य बिल्डरों की गिरफ्तारी व उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई को लेकर पुलिस-प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं।

शाहबेरी गांव में प्राधिकरण ने 2009 में 155 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था। किसानों ने अधिग्रहण को कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने 2010 में अधिग्रहण रद कर दिया था। खेती करने की बजाय किसानों ने बिल्डरों को जमीन बेचनी शुरू कर दी थी। बिल्डरों ने नियमों के विरुद्ध अधिसूचित क्षेत्र में फ्लैट बना दिए। इसके लिए किसी भी विभाग से अनुमति नहीं ली। लोगों को झांसे में लेकर फ्लैट बेच दिए। मिलीभगत करके बैंकों से लोन करा दिया। पिछले वर्ष 17 जुलाई को शाहबेरी में छह-छह मंजिला दो इमारतें जमींदोज हो गई थीं। घटना में नौ लोगों की मौत हो गई थी।

न्यूज गैलरी

आज तेज हवा के साथ झमाझम बारिश देगी उमस से राहत

नई दिल्ली : उमस भरी गर्मी झेल रहे दिल्लीवासियों को शुक्रवार को खासी राहत मिलने की संभावना है। तेज हवा के साथ होने वाली झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राहत का यह दौर अभी सप्ताह भर तक जारी रहेगा। इस बीच गुरुवार को सुबह कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश हुई। इस बारिश ने गर्मी से कुछ ही देर राहत दी। बाद में धूप निकल आई और उमस फिर से बढ़ गई। अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश सुबह साढ़े आठ बजे तक 10.8 मिमी रिकार्ड की गई। सर्वाधिक बारिश पालम में 48.0 मिमी हुई। (जासं)

एयरपोर्ट पर सीआइएसएफ के जवानों ने दिखाया दमखम

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर स्वतंत्रता दिवस उल्लास पूर्वक मनाया गया। टर्मिनल-3 पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डायल के सीईओ विदेह जयपुरियार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर एयरपोर्ट यूनिट में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों ने हथियार के साथ दक्षता का प्रदर्शन किया। डॉग शो आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान विदेह जयपुरियार ने अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले जवानों को पुरस्कृत किया। झंडोत्तोलन कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह नौ बजे हुआ। इसमें सीआइएसएफ के जवानों ने मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। क्विक रिएक्शन टीम (क्यूआरटी) कमांडो ने चिंतनशील शूटिंग की और जवानों ने सुरक्षा से जुड़े अन्य अभ्यास किए। डॉग शो के दौरान तरह-तरह के प्रदर्शन किए गए। एयरपोर्ट पर डीटीएस भवन में भी झंडोत्तोलन समारोह हुआ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन अनुज अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। (जासं)

मिलिंद ने लगाई दौड़, दिया महिलाओं को स्वास्थ्य संदेश

नई दिल्ली : 15 अगस्त पर पारंपरिक परिधानों में पिंकडिपेंडेंस डे रन का आयोजन किया गया। 150 से अधिक महिलाओं ने तीन किमी की दौड़ में हिस्सा लिया। इसकी शुरुआत सुबह सात बजे लोधी गार्डन से हुई। अभिनेता मिलिंद सोमन ने हरी झंडी दिखाकर रन को रवाना किया। साथ ही वह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुल 73 किलोमीटर तक दौड़े और सभी महिलाओं को स्वास्थ्य एवं फिटनेस का संदेश दिया। मिलिंद ने मुरथल पर दौड़ समाप्त की। (जासं)

कश्मीर मुद्दे का जनता के बीच प्रचार पर भाजपा का रहेगा जोर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

सदस्यता अभियान के अंतिम चरण को सफल बनाने में भाजपा नेता जी जान से जुट गए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें पार्टी के विभिन्न विभागों, प्रकल्पों व प्रकोष्ठों के प्रभारी, सह-प्रभारी, प्रमुख व सह-प्रमुख शामिल हुए। उन्हें बूथ स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने व ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में शामिल करने को कहा गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे को भी जनता के बीच प्रचारित किया जाएगा।

भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने कहा कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं की मेहनत व लगन से संगठन पर्व सदस्यता अभियान अपनी मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है। सदस्यता अभियान की तिथि 11 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। समापन तिथि के बढ़ने से हम सभी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें और अधिक संख्या में लोगों को भाजपा से जोड़ने के लिए काम करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ानी होगी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का निर्णय ऐतिहासिक है जिसके बारे में लोगों को बताकर उन्हें भाजपा के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।

प्रदेश महामंत्री व सदस्यता अभियान प्रमुख कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि दिल्ली के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता की मेहनत व लगन का परिणाम है कि रिकॉर्ड संख्या में दिल्ली के लोग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग खुद भाजपा से जुड़ने के लिए संपर्क कर रहे हैं। सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार से दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि 54 महीने में इसने कोई भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया है। दिल्लीवासियों की उम्मीदें भाजपा के साथ जुड़ी हैं। इस स्थिति में हमें लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए उनके बीच जाना होगा।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए संघर्ष करने वालों की जिंदगी बीत गई, लेकिन कांग्रेस की सरकारों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची।

यूनिटेक बिल्डर को ब्याज समेत लौटाने होंगे साढ़े 33 लाख रुपये

जासं, नई दिल्ली : उपभोक्ता आयोग ने यूनिटेक बिल्डर के खिलाफ दर्ज एक मामले में आदेश दिया है कि बिल्डर उपभोक्ता को ब्याज सहित 33 लाख रुपये लौटाए। नई दिल्ली के कमला नगर निवासी सुरहिद भंडारी ने यूनिटेक लिमिटेड के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में जनवरी 2012 में फ्लैट बुक किया था। फ्लैट की कुल कीमत करीब 78 लाख रुपये तय हुई थी।

उपभोक्ता ने अलग-अलग समय पर बिल्डर को 33 लाख 59 हजार रुपये चुका दिए। अनुबंध के मुताबिक मार्च 2015 में फ्लैट का कब्जा मिलना था, लेकिन बिल्डर ने प्रोजेक्ट की स्थिति के बारे में जवाब देना ही बंद कर दिया। पत्राचार करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। आयोग ने कहा कि सात साल गुजर गए और निर्माण पूरा नहीं हुआ। निकट भविष्य में भी निर्माण पूरा होने जैसे हालात नजर नहीं आते। लिहाजा उपभोक्ता को उसकी मेहनत से कमाया पैसा ब्याज के साथ वापस मिलना चाहिए। आयोग ने बिल्डर को आदेश दिया है कि 33 लाख 59 हजार रुपये 10 फीसद वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए जाएं। आयोग ने कहा है कि 45 दिन में आदेश की पालन किया जाए।

पतंग की डोर ने डेढ़ घंटे तक थामी मेट्रो की रफ्तार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

बिजली आपूर्ति बाधित होने से ब्लू लाइन पर मेट्रो का परिचालन प्रभावित हुआ। मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ लग गई। इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। एएनआइ

पतंग की डोर ने गुरुवार को ब्लू लाइन पर मेट्रो ट्रेन की रफ्तार रोक दी। दरअसल, चाइनीज मांझा फंसने के कारण मेट्रो के ओएचई (ओवर हेड इक्यूपमेंट) में खराबी आ गई और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इससे दोपहर में ब्लू लाइन पर करीब डेढ़ घंटा मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा। ओएचई में यह खराबी दोपहर दो बजे सुभाष नगर से राजौरी गार्डन के बीच आई। इस वजह से द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा व वैशाली जाने वाली मेट्रो ट्रेनें रुक गईं। यात्री मेट्रो के अंदर व स्टेशनों पर काफी देर तक फंसे रहे। बाद में तीन लूप में मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया। यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के सोशल नेटवर्क के हैंडल पर ट्वीट कर रोष जाहिर किया।

सिंगल लाइन पर हुआ परिचालन : ब्लू लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे व्यस्त कॉरिडोर है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का कहना है परिस्थिति को देखते हुए ब्लू लाइन पर तीन हिस्सों में परिचालन किया गया। इसके तहत जनकपुरी पश्चिम से कीर्ति नगर के बीच सिंगल लाइन पर परिचालन हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से मेट्रो ट्रेनें रोक-रोककर एक ही ट्रैक से निकाली जा रही थीं। इस वजह से जनकपुरी से कीर्ति नगर के बीच परिचालन काफी हद तक ठप था क्योंकि 15-20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो उपलब्ध हो पा रही थी। इस वजह से जनकपुरी पश्चिम, सुभाष नगर, राजौरी गार्डन, कीर्ति नगर, द्वारका के कई स्टेशनों पर भीड़ एकत्रित हो गई। डीएमआरसी का कहना है कि कीर्ति नगर से नोएडा के बीच परिचालन सामान्य रहा, लेकिन नोएडा व वैशाली से द्वारका की तरफ जाने वाली ज्यादातर मेट्रो ट्रेनें कीर्ति नगर से ही वापस लौट रही थीं। इसी तरह द्वारका सेक्टर 21 से चलने वाली ज्यादातर मेट्रो जनकपुरी पश्चिम से वापस लौट रही थीं।

डीएमआरसी का कहना है कि कई जगहों पर ओएचई में चाइनीज मांझे फंसे हुए थे। कर्मचारियों ने मैनुअली जांच कर एक-एक जगह से पतंग की डोर को निकाला। दरअसल, चाइनीज मांझे में धातु का इस्तेमाल होता है। इस वजह से यह विद्युत का वाहक है। ओएचई में मांझा फंसने पर बिजली ट्रिप हो गई। दोपहर 3:15 बजे सभी जगहों से पतंग की डोर को निकाला जा सका। इसके बाद करीब साढ़े तीन बजे मेट्रो का परिचालन सामान्य हो पाया।

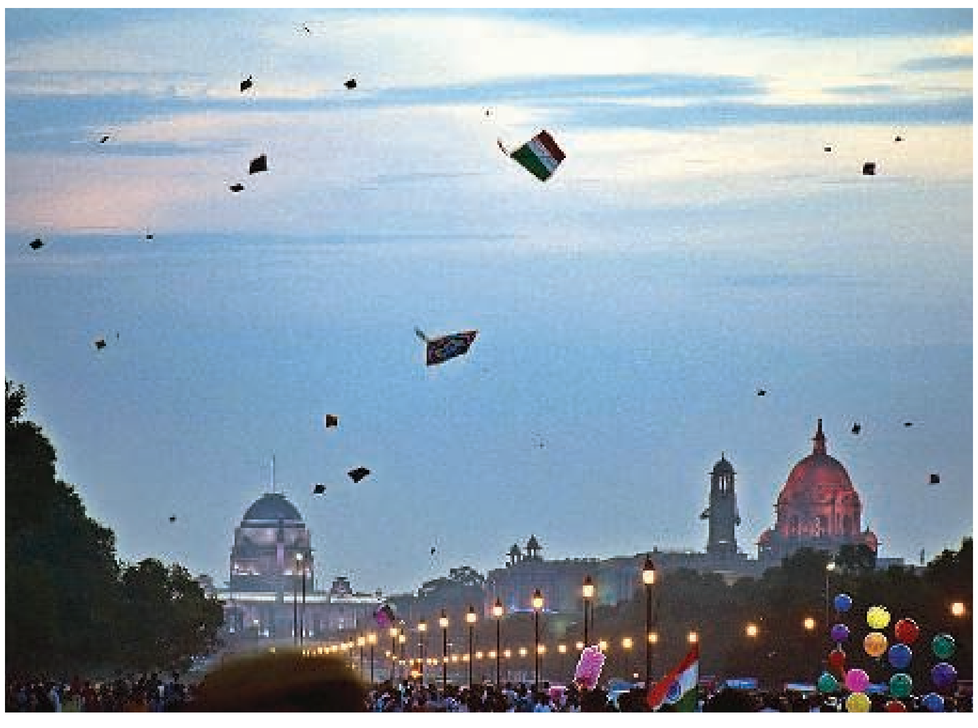

आजादी के जश्न में खूब हुई पतंगबाजी

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को पूरी दिल्ली देशभक्ति के रंग में डूबी हुई दिखी। जगह-जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पूरे दिन पतंगबाजी का दौर भी जारी रहा। राजपथ के लॉन में भी लोगों ने खूब पतंगें उड़ाईं। संजय

गलत लेन में टैक्सी ले जाने से रोका तो कर दी पिटाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आइजीआइ के टर्मिनल-1 पर एक कर्मचारी ने काली-पीली टैक्सी चालक को गलत लेन में जाने से रोका तो उसने कर्मचारी की रॉड से पिटाई कर दी। उसने वहां बने बूथ को भी तोड़ दिया। सुरक्षाकर्मियों को चकमा देते हुए आरोपित मौके से फरार हो गया। एयरपोर्ट थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

राजनगर पार्ट वन निवासी पीड़ित विनोद कुमार एयरपोर्ट पार्किंग में कस्टमर सर्विस एसोसिएट हैं। मंगलवार की रात उनकी तैनाती टर्मिनल-1 पर थी। रात करीब दो बजे उन्होंने पाया कि एक काली-पीली टैक्सी चालक अपनी लेन में न जाकर कार्मशियल वाहनों के लिए बनी लेन में जाने की कोशिश कर रहा है। विनोद ने उसे रोका। चालक गलत लेन में प्रवेश कर प्लास्टिक के बैरिकेड में टक्कर मारते हुए टैक्सी को भगाने लगा। पीड़ित द्वारा रोकने की कोशिश के दौरान टैक्सी के एक दरवाजे का शीशा टूट गया। इससे नाराज राज कुमार ने टैक्सी से रॉड निकाल उससे विनोद पर हमला कर दिया। इसमें पीड़ित की पीठ, हाथ और पैर पर चोटें आई हैं। चालक ने बूथ में लगा शीशा भी तोड़ दिया। विनोद पीसीआर को कॉल करने लगे तो आरोपित टैक्सी लेकर फरार हो गया। पीड़ित को डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें उपचार के छुट्टी दे दी गई।

डीसीपी आत्महत्या मामले में आरोपित इंस्पेक्टर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

- एसीपी क्राइम के नेतृत्व में एसआइटी गठित
- दूसरा आरोपित सतीश मलिक गिरफ्तार, पुलिस कर रही तलाश

डीसीपी विक्रम कपूर की आत्महत्या मामले की विस्तृत जांच के लिए पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने एसीपी क्राइम अनिल कुमार के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया है। इसमें इंस्पेक्टर विमल सहित चार लोग हैं। वह भूपानी थाने में प्रभारी के तौर पर तैनात थे। हिरासत में लिए गए आरोपित इंस्पेक्टर अब्दुल सईद को पुलिस ने गुरुवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। एसआइटी शुक्रवार को उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। इस मामले में दूसरे आरोपित सतीश मलिक की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

बता दें कि बुधवार सुबह डीसीपी एनआइटी आइपीएस विक्रम कपूर ने अपने सरकारी आवास पर सर्विस पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया था। इसमें उन्होंने इंस्पेक्टर अब्दुल सईद द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की बात लिखी थी। डीसीपी विक्रम कपूर के बेटे अर्जुन ने अब्दुल सईद व सतीश मलिक द्वारा पिता को ब्लैकमेल किए जाने की शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। बुधवार देर शाम खेड़ी पुल के शमशान घाट में डीसीपी का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले सेक्टर-30 पुलिस लाइन में गारद ने उन्हें सलामी दी। गुरुवार को डीजीपी मनोज यादव डीसीपी विक्रम कपूर के घर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी।

अब तक पुलिस नहीं लगा सकी ठोस कारण का पता

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

डीसीपी विक्रम कपूर द्वारा गोली मारकर आत्महत्या का कोई ठोस कारण अभी जांच टीम नहीं तलाश पाई है। जांच के लिए एसआइटी का गठन किया गया है, जो आरोपित इंस्पेक्टर अब्दुल सईद से पूछताछ में जुटी है। लंबे कार्यकाल के चलते आरोपित इंस्पेक्टर पुलिस की कार्यशैली से भलीभांति परिचित है। ऐसे में वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इससे मामले की तह तक पहुंचने में टीम को देरी लग रही है।

पुलिस टीम आरोपित इंस्पेक्टर से जो सवाल पूछ रही है, उन पर वह चुप्पी साध लेता है या बात को घुमा फिराकर जवाब दे रहा है। जांच टीम आरोपित इंस्पेक्टर से वह वजह जानने की कोशिश कर रही है, जिससे डीसीपी इतने अधिक दबाव में आ गए कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। इस मामले में ब्लैकमेल कर मोटी रकम मांगे जाने की बात सामने आई है। वहीं एक महिला के भी इस मामले में शामिल होने की जानकारी आई हैं। इसके अलावा आरोपित इंस्पेक्टर द्वारा अपने एक रिश्तेदार का मुकदमे में से नाम निकालने के लिए दबाव बनाने की भी बातें सामने आई हैं। पुलिस इन सभी एंगल पर आरोपित इंस्पेक्टर से पूछताछ कर रही है। तह तक पहुंचने के लिए पुलिस टीम डीसीपी व आरोपित इंस्पेक्टर के मोबाइल भी खंगाला रही है। मामला आइपीएस की आत्महत्या से जुड़ा होने के कारण विभाग के आला अधिकारियों की भी इस पर पैनी नजर है। यही वजह है कि जांच टीम हरेक एंगल पर बारीकी से काम कर रही है।

> आरोपित इंस्पेक्टर अब्दुल सईद को निलंबित कर दिया गया है। उसकी जगह भूपानी थाने में जल्द ही नए प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी। मामला भी जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
> –सूबे सिंह, पुलिस प्रवक्ता

योजना

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन करेंगे निर्माण कार्य का शुभारंभ, 550 बेड का सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक भी बनेगा

अटल के नाम पर मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ आज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम पुण्यतिथि पर शुक्रवार को आरएमएल अस्पताल में उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होगा। इसके साथ ही आरएमएल अस्पताल में करीब 550 बेड का सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक भी बनेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान व सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे।

उल्लेखनीय है कि आरएमएल अस्पताल में पहले एमबीबीएस का मेडिकल कॉलेज नहीं था। मौजूदा सत्र से इस अस्पताल में एमबीबीएस का मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है, जिसमें सौ सीटें निर्धारित की गई हैं। यह दिल्ली का 10वां मेडिकल कॉलेज है, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की गई है। यह मेडिकल कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाएगा। आरएमएल अस्पताल में मेडिकल कॉलेज शुरू करने व सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण की योजना स्वास्थ्य मंत्रालय की सौ दिन की प्रमुखता सूची में शामिल थी।

सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक दो साल में होगा तैयार : आरएमएल अस्पताल में 1469 बेड उपलब्ध हैं। मरीजों की भीड़ के लिहाज से यह दिल्ली में एम्स व सफदरजंग अस्पताल के बाद तीसरा सबसे व्यस्त अस्पताल है, जहां प्रतिदिन ओपीडी में करीब 8500 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इसलिए अस्पताल में मरीजों की तुलना में सुविधाएं कम पड़ रही हैं। लिहाजा लंबे समय से अस्पताल के विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके मद्देनजर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। इसमें करीब 550 बेड, 20 ऑपरेशन थियेटर व तीन कैथ लैब की सुविधा होगी।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इसका निर्माण कराएगा और दो साल में यह बनकर तैयार होगा। इसमें किडनी, किडनी प्रत्यारोपण, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कैंसर सर्जरी सहित कई सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं होंगी। इसका निर्माण होने से गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज का बेहतर विकल्प मिल पाएगा।

एम्स में नए ओपीडी ब्लॉक में अगले माह से शुरू होगा इलाज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : एम्स, सफदरजंग, आरएमएल सहित तमाम अस्पतालों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। एम्स में ध्वजारोहण के बाद संस्थान के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने चिकित्सा व शोध सुविधाओं में विस्तार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एम्स में अगले माह मस्जिद मोठ के नजदीक बने नए ओपीडी ब्लॉक में मरीजों का इलाज शुरू होगा। इसके अलावा एम्स ट्रॉमा सेंटर में करीब 100 बेड का बर्न सेंटर भी बनाया गया है, जिसके फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसमें भी जल्द मरीजों का इलाज शुरू होगा। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। एम्स के मुख्य अस्पताल व सभी सेंटरों को मिलाकर प्रतिदिन ओपीडी में करीब 13 हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इसमें से अकेले मुख्य अस्पताल की ओपीडी में करीब नौ हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इस वजह से ओपीडी में जगह कम पड़ रही है। इसके अलावा सर्जरी के लिए भी मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि एम्स में ओपीडी ब्लॉक, सर्जरी ब्लॉक, मातृ व शिशु ब्लॉक व बर्न सेंटर बनाया गया है। एम्स प्रशासन ने नवनिर्मित ओपीडी को पहले शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत एम्स के मुख्य अस्पताल की ओपीडी नए ओपीडी ब्लॉक में स्थानांतरित की जाएगी। इसलिए पुरानी ओपीडी की जगह खाली हो जाएगी। नए ओपीडी ब्लॉक के लिए नौ मंजिला भवन बनाया गया है, जिसमें 570 नए कमरे होंगे। हर मंजिल पर करीब 500 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। इस ओपीडी ब्लॉक में एक माइनर ऑपरेशन थियेटर भी होगा। एम्स ने इस ओपीडी ब्लॉक को अगस्त में ही शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब अगले माह से इसमें मरीजों का इलाज शुरू होगा।

73 वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार छठी बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने चुप्पी के जरिये ही दे दिया पाकिस्तान को बड़ा संदेश

अनदेखी ▸ लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण में एक बार भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं

आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ अभियान जारी रखने के अपने वादे से पड़ोसी को दी नसीहत

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत की कूटनीति भी बदली नजर आ रही है। इसका एक उदाहरण पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से गुरुवार को दिए गए भाषण से भी मिलता है। सभी को उम्मीद थी कि पीएम मोदी लाल किले से पाकिस्तान को कोई संदेश देंगे, लेकिन पीएम के भाषण में पड़ोसी देश का एक बार भी नाम तक नहीं आया जबकि दूसरे पड़ोसी देशों का जिक्र किया। हां, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेहद सख्त संदेश जरूर दिया कि भारत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को पनाह देने वालों को विश्व बिरादरी के सामने एक्सपोज करता रहेगा और अपनी भूमिका भी निभाएगा।

पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की तुलना पड़ोसी देश के पीएम इमरान खान की तरफ से उनके देश केस्वतंत्रता दिवस समारोह (14 अगस्त, 2019) के भाषण से करें तो साफ हो जाता है कि दोनों देशों के विचार कितने अलग-अलग हैं। बता दें कि पीएम खान के भाषण का अधिकांश हिस्सा भारत व कश्मीर केंद्रित था। खान ने कश्मीर, अल्पसंख्यकों की स्थिति जैसे मुद्दों के साथ ही भारतीय पीएम और आरएसएस पर भी करारे हमले किए. लेकिन अपने देश की बेहद खस्ताहाल अर्थव्यवस्था का जिक्र बहुत ही संक्षिप्त में किया। ना ही इसका कोई रोडमैप दिया कि उनकी सरकार आर्थिक बदहाली को रोकने के लिए क्या करेगी। इमरान खान ने अपने भाषण में कहा था कि भारत बालाकोट से भी बड़ा भीषण हमला करने की तैयारी में है।

दूसरी पीएम मोदी का भाषण अनुच्छेद 370 के फायदे को गिनाने और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने पर ज्यादा केंद्रित रहा और पड़ोसी देश पाकिस्तान का सीधे नाम तक नहीं लिया। पीएम मोदी ने वर्ष 2018 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। हालांकि वर्ष 2016 में मोदी ने लाल किले से दिए गए भाषण को पाकिस्तान पर अभी तक किया गया सबसे करारा हमला कहा जाता है। उसमें उन्होंने ब्लूचिस्तान, गिलगित-बाल्टिस्तान का जिक्र कर पाकिस्तान के कूटनीतिक सर्किल में हड़कंप मचा दिया था।

मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक समस्या के तौर पर उठाया वह व्यापक माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि, 'विश्व शांति के लिए भारत को अपनी भूमिका निभानी होगी। वैश्विक परिवेश में भारत मूकदर्शक बन कर नहीं रह सकता और भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को निर्यात करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही रूप में लाते हुए आतंकवाद को नष्ट करने के प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, हम यही चाहते हैं।'

स्वतंत्रता दिवस पर गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में रिसेप्शन का आयोजन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी शामिल हुए। इस दौरान मनमोहन सिंह और हामिद अंसारी के साथ नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

स्वच्छता की तर्ज पर पॉलीथीन से मुक्ति का दिया नया नारा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दो अक्टूबर को देश भर में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाने का एलान
- स्टार्ट-अप और उद्यमियों से अपील की-री-साइकिल के लिए काम करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान की तर्ज पर देश को पॉलीथीन मुक्त करने का एक बड़ा एलान किया। दो अक्टूबर को इसे लेकर देश भर में अभियान चलाने की अपील की है। इसके तहत एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को इकट्ठा करने को कहा है। साथ ही लोगों से अपील की है, वह प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल करे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पीएम मोदी की यह एक बड़ी पहल मानी जा रही है।

लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों को याद दिलाते हुए कहा 2014 में इसी लाल किले से उन्होंने लोगों से स्वच्छता की बात कही थी। इसी का परिणाम है कि देश अगले कुछ ही हफ्तों के बाद पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। पीएम ने ठीक इसी तर्ज पर लोगों से एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को लेकर भी अभियान छेड़ने की अपील की। हालांकि उन्होंने सवालिया अंदाज में लोगों के सामने अपनी यह बात रखी और कहा कि इस दो अक्टूबर को हम भारत को क्या एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति दिला सकते हैं? तो निकल पड़े, टोलियां बना करके। उन्होंने इस दौरान स्टार्टअप और उद्यमियों से भी आग्रह किया कि वह भी विचार करें कि प्लास्टिक के री-साइकिल के लिए क्या करें? इसी तरह दीवाली पर गिफ्ट के रूप में हम कपड़े और जूट का थैला लोगों को दें। इससे किसान सहित इस कारोबार से जुड़े दूसरे लोगों का भी भला होगा।

प्लास्टिक के खिलाफ मोदी ने जो अपील की है वह जनजागरूकता का आधार तैयार करने का काम करेगी। गौरतलब है कि देश ही नहीं दुनिया में प्लास्टिक एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बनकर उभरा है। कई देश इस समस्या से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।

अपील : देश में बनी चीजों को दें प्राथमिकता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा और संघ के एजेंडे में रहे स्वदेशी की झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिए अपने संबोधन में दिखा दी। उन्होंने इसे देश के विकास और निर्माण से भी जोड़ा। प्रधानमंत्री ने अपील की कि सभी लोग देश में बनी चीजों को ही प्राथमिकता दें। उन्होंने एक नारा भी दिया, 'लकी कल के लिए लोकल, उज्ज्वल कल के लिए लोकल'।

मालूम हो कि संघ की ओर से बार-बार स्वदेशी की बात बुलंद की जाती है। इसके अनुसार जो देश में बनता है भारतीयों को पहले उसका ही उपयोग करना चाहिए। जो उपलब्ध नहीं है उसके लिए ही बाहर की चीजों पर निर्भर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' अभियान को आगे बढ़ाने की बात दोहराते हुए कहा, 'हमारे गांव मे जो बनता है वह हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, फिर जो हमारे जिले में बनता है और फिर जो हमारे राज्य में बनता है।' उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण व्यवस्था, लघु उद्यमियों और परंपरागत चीजों को बल मिलेगा। नीचे से लेकर ऊपर तक देश समृद्ध और मजबूत होगा।

छोटे परिवार की जरूरत को देशभक्ति से जोड़ा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पीएम ने कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए जनसंख्या विस्फोट बनेगा संकट
- इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें उठाएं जरूरी कदम
- आबादी पर अंकुश के लिए जागरूकता अभियान चला जा सकता है

लंबे अरसे से भारत की बड़ी जनसंख्या के सकारात्मक पहलू पर छिड़ी चर्चा के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री ने जनसंख्या विस्फोट के भीषण परिणाम के प्रति न केवल आगाह किया, बल्कि इसे सीधे-सीधे देश के हित से भी जोड़ दिया। मोदी ने केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। हालांकि उन्होंने फिलहाल किसी नियम कानून की बात नहीं की, पर जिस तरह उन्होंने समस्याओं को टालने की बजाय उसके निराकरण की बात कही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बारे में भी बड़ा जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है।

पिछले वर्षों में जब जब जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात हुई, इसे राजनीति से भी जोड़ा गया है। आरोप-प्रत्यारोप में इसे सांप्रदायिक रंग भी दिया गया। गुरुवार को जब पीएम ने देश को संबोधित किया तो साफ कहा- 'चुनौतियों को सामने से स्वीकार करने का वक्त आ चुका है। कभी-कभी राजनीतिक नफा-नुकसान के इरादे से हम निर्णय करते है, लेकिन इससे देश की भावी पीढ़ी का बहुत नुकसान होता है। ऐसा ही एक विषय जनसंख्या विस्फोट है।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य व्यक्ति और परिवार से शुरू होता है, लेकिन अगर आबादी शिक्षित व स्वस्थ नहीं है, तो न वह घर सुखी होता है, न ही वह देश सुखी होता है। जनसंख्या विस्फोट जहां हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा कर रहा है, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो स्वःप्रेरणा से अपने को छोटे परिवार तक सीमित रखकर देश के साथ-साथ अपने परिवार का भला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सीधे शब्दों में कहा- 'छोटा परिवार रखकर भी वे देशभक्ति प्रकट करते हैं।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार सोचें कि जो बच्चा आएगा क्या उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगे या फिर उसे समाज और नसीब के भरोसे छोड़ देंगे। जो वर्ग छोटा परिवार रखकर समाज और देश का हित कर रहे हैं उनसे सीख लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से भी कहा कि वह भिन्न- भिन्न योजनाओं को लेकर आगे आएं ताकि इनसे निपटा जा सके।

ध्यान रहे कि अब तक भारत की जनसंख्या में युवाओं की बड़ी आबादी को देशहित में माना जा रहा था, लेकिन यूएनएफपीए रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक यह पूरा परिदृश्य बदलने वाला है। तब भारत की आबादी युवा नहीं होगी और उम्रदराज लोगों की संख्या काफी हो जाएगी। ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अभी से जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय करना आवश्यक है।

हर परिवार साल में पांच स्थलों का करे भ्रमण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बेहद महत्वपूर्ण अपील देशवासियों से की है जिसका दूरगामी व व्यापक असर देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से मांग की है कि वह अपने परिवार के साथ वर्ष 2022 तक देश के कम से कम 15 पर्यटन स्थलों का भ्रमण करें। यह भ्रमण न केवल देश की युवा पीढ़ी को देश के विभिन्न हिस्सों से भावनात्मक रूप से जोड़ेगा बल्कि यह स्थानीय रोजगार व अर्थव्यवस्था को भी बहुत प्रोत्साहित करेगा। यह अपील एक तरह से उन लोगों के लिए संदेश भी है जो विदेश पर्यटन पर ज्यादा केंद्रित होते हैं।

मोदी पहले भी पर्यटन को प्राथमिकता देते रहे हैं लेकिन इस बार व्यापक संदेश है। उन्होंने कहा, 'अपने परिवार के साथ कम से कम 15 पर्यटन स्थलों पर जाएं। वहां कठिनाइयां होंगी तब भी जाएं। हम अपनी बच्चों में आदत डालें कि यही हमारा देश है। एक बार जाना शुरू करेंगे तो लोग वहां व्यवस्था भी करना शुरू कर देंगे।' पीएम ने इस अपील के जरिये यह भी मंशा जताई कि इससे देश में 100 बेहतरीन पर्यटन स्थलों और हर राज्य में कम से कम पांच से सात पर्यटन स्थलों को तैयार किया जा सकता है। यह काम राज्य सरकारें भी लक्ष्य बनाते हुए कर सकती हैं। यह पहल अर्थव्यवस्था के लिहाज से अहम है ही, देश के उस वर्ग को भी संदेश दिया है जो विदेश दौरे पर काफी जाने लगा है। इसमें बड़ी संख्या में नौकरशाह और राजनीतिज्ञ होते हैं।

पीएम की अध्यक्षता में अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यों के बीच विवाद की जांच और सुझाव देने वाले अंतर-राज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष और छह केंद्रीय मंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। अधिसूचना के मुताबिक, पुनर्गठित परिषद में शामिल केंद्रीय मंत्रियों में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं। अन्य केंद्रीय मंत्रियों में समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत और आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं।

दस अन्य केंद्रीय मंत्रियों को परिषद में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इनमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल शामिल हैं। अन्य चार स्थायी आमंत्रित मंत्रियों में जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, रेलमंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं।

छा गया मोदी का साफा

ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से 73 वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी खास अंदाज में नजर आए। यह छठा मौका था जब जश्न-ए-आजादी पर उन्होंने रंग-बिरंगा साफा पहना। राजस्थानी साफा, गमछा, सफेद कुर्ते और चूड़ीदार पायजामे में मोदी का लुक खास आकर्षण का केंद्र बना रहा। वर्ष 2014 से ही हर साल उनके साफे का रंग अलग रहा है। साफा इस प्रकार से बांधा जाता है कि इसके एक छोर पर कपड़ा सिर से पीठ तक नीचे लटका होता है। प्रेट्र

साढ़े तीन लाख करोड़ की लागत वाली 'जल जीवन मिशन' योजना का एलान

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

पीने के पानी को नए भारत के लक्ष्य का अहम हिस्सा बनाते हुए प्रधानमंत्री ने साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के 'जल जीवन मिशन' योजना का एलान किया। उन्होंने कहा कि देश के आधे गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं है और लंबी दूरी से पानी लाने वाली महिलाएं इससे सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। इसीलिए गांवों में पेयजल पहुंचाने, जल संचय से लेकर सिंचाई प्रबंधन पर व्यापक फोकस होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें सरकार नहीं जनता की व्यापक भागीदारी जरूरी है।

सभी को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा : जनसंख्या नियंत्रण हो या प्लास्टिक के खिलाफ दो अक्टूबर से राष्ट्रीय अभियान छेड़ने की घोषणा प्रधानमंत्री ने इन सभी में नागरिकों की संपूर्ण भागीदारी की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, 'भिन्न-भिन्न योजनाओं के तहत चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हर किसी को दायित्व निभाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा।'

तीन लोकसभा सीटों पर होगा एक मेडिकल कॉलेज : नए भारत के लक्ष्य में हर तीन लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज, गांवों में डेढ़ लाख स्वास्थ्य केंद्र, वेलनेस सेंटर, दो करोड़ से अधिक लोगों के लिए घर बनाने, 15 करोड़ ग्रामीण घरों में पेयजल पहुंचाने, गांवों की सवा लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण से लेकर हर गांव को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने की बात प्रधानमंत्री ने कही। इतना ही नहीं, विकास को गति देने के लिए उन्होंने 50 हजार नए स्टार्टअप का जाल बिछाने के इरादे भी जाहिर किए। मोदी ने पांच साल में आए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 के चुनाव से पहले देश में हर तरफ निराशा का माहौल था, मगर 2019 आते-आते देशवासियों का मिजाज बदल चुका था। लोकसभा चुनाव में यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। जब मैंने देखा और उस समय कहा भी था, 'न कोई राजनेता चुनाव लड़ रहा था, न राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा था, न मोदी चुनाव लड़ रहा था, न मोदी के साथी चुनाव लड़ रहे थे, देश का आम आदमी, जनता-जनार्दन चुनाव लड़ रही थी।'

कानून मंत्री ने न्यायिक जवाबदेही के लिए अंदरूनी सुधारों पर दिया जोर

नई दिल्ली, प्रेट्र : कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट समेत सभी अदालतों में अनुशासन, न्यायिक उपयुक्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अंदरूनी (इनहाउस) सुधारात्मक उपाय करने पर जोर दिया। उन्होंने जनहित याचिका पर टालमटोल का रवैया अपनाने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की आलोचना भी की।

- जनहित याचिकाओं पर टालमटोल के लिए की उच्च न्यायालयों की आलोचना

रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट लॉन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोल रहे थे जहां प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में राष्ट्र ध्वज फहराया। इन लोगों में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल भी मौजूद थे। रविशंकर ने कहा कि पुरानी अपीलों के निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक रुख होना चाहिए क्योंकि 1980 के दशक की फौजदारी और दीवानी अपीलें अभी भी हाई कोर्टों में लंबित हैं। उन्होंने कहा, 'कुछ राज्यों के उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाओं को इस तरह से रोककर रखा गया है जैसे वे अपने राज्य प्रशासन के समानांतर चल रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए?' उन्होंने कहा, 'मैं देखता हूं कि 1982/1983 की फौजदारी अपीलें अब भी हाई कोर्टों में लंबित हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वे उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। 1977/1978 की दीवानी अपीलें अब भी लंबित हैं और यहां तक कि प्रथम अपीलें भी लंबित हैं... पुरानी अपीलों के निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक रुख होना चाहिए। 10 वर्ष पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लें और उसके बाद पांच वर्ष पुराने मामलों पर आएं।' कानून मंत्री ने कहा कि जिस तरह कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा कुछ फैसले दिए गए वे 'मनमाने' थे। उन्होंने कहा, 'कुछ न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति से केवल दो दिन पहले संदिग्ध वैधता वाले फैसले देते हैं और उसे उचित ठहराने के लिए तीन दिन टेलीविजन पर बैठते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए।'

अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने भी फौजदारी एवं दीवानी अपीलों के लंबित रहने पर चिंता जताते हुए कहा कि देश के चारों क्षेत्रों (पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण) में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के बीच में 'कोर्ट ऑफ अपील' होने चाहिए। इन 'कोर्ट ऑफ अपील' में अलग जज होने चाहिए। ये जज हाई कोर्टों से प्रोन्नत कर लाए जा सकते हैं और इस प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की व्यवस्था आधार बन सकती है। उन्होंने कहा, 'मैं कल सुप्रीम कोर्ट की वाद सूची देख रहा था, 30 दीवानी अपीलें थीं जो कि 2007 से लंबित हैं, जो लगभग 12 वर्ष का समय होता है। कल्पना कीजिए इतने ही मामले हाई कोर्टों और जिला अदालतों में लंबित हैं, संभव है नौ से 10 वर्षों से। हमें आज एक साहसी व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे देश में अदालती प्रणाली की समस्याओं को दूर कर सके।'

अदालतों में अमर्यादित आचरण पर सीजेआइ ने अफसोस जताया

राष्ट्र ध्वज फहराने के के बाद प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि न्यायपालिका अमर्यादित आचरण के अभूतपूर्व तरीके से बढ़ते मामलों की गवाह बन रही है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि गरिमापूर्ण तरीके से होने वाली चर्चाओं और बहस की जगह अदालतों में मुखर आचरण अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका की गरिमा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों की तेजी से पहचान हो और इन्हें अलग-थलग किया जाए।

अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई आज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले और उसके बाद राज्य में मीडिया और अन्य संचार माध्यमों पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एसए नजीर की विशेष पीठ अधिवक्ता एमएल शर्मा और 'कश्मीर टाइम्स' की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। एमएल शर्मा ने छह अगस्त को दायर अपनी याचिका में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया है कि अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति का आदेश गैरकानूनी है क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सहमति के बिना जारी किया गया। वहीं, 10 अगस्त को दायर याचिका में पत्रकार अनुराधा भसीन ने पूरे राज्य में मोबाइल, इंटरनेट एवं लैंडलाइन सेवाओं समेत संचार के सभी माध्यमों को बहाल करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की है ताकि मीडिया अपना काम कर सके। जम्मू-कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी नेशनल कांफ्रेंस ने भी याचिका दायर कर अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है। पार्टी ने तर्क दिया है कि इन बदलावों ने जनादेश के बिना वहां के नागरिकों से उनके अधिकार छीन लिए हैं। यह याचिका नेशनल कांफ्रेंस के लोकसभा सदस्यों मुहम्मद अकबर लोन और जस्टिस (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी ने दायर की है। लोन जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं जबकि जस्टिस मसूदी जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के वही पूर्व न्यायाधीश हैं जिन्होंने 2015 में एक फैसले में अनुच्छेद 370 को संविधान का स्थायी प्रावधान करार दिया था। मालूम हो कि कुछ अन्य लोगों ने भी इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, लेकिन उन्हें शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले को दी गई है चुनौती

अटार्नी जनरल बोले, अनुच्छेद 370 निरस्त करना केंद्र का अच्छा कदम : अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का फैसला एक अच्छा कदम है। इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी वेणुगोपाल ने उनका विरोध किया था।

बढ़ती करीबी

मुंहबोली बहन कमर ने तत्काल तीन तलाक बैन करने पर दिया धन्यवाद, कहा-उनके पास प्रधानमंत्री को देने के लिए एक सरप्राइज पेंटिंग है..

इशरत समेत कई महिलाओं ने मोदी को बांधी राखी

नई दिल्ली, एएनआइ : रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर तत्काल तीन तलाक की याचिकाकर्ता इशरत जहां समेत कई महिलाओं और बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी है। इन महिलाओं में शामिल उनकी राखी बहन कमर मोहसिन शेख ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। साथ ही नए कानून के जरिए तत्काल तीन तलाक को अपराध करार दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है।

गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी को कुछ स्कूली छात्राओं और महिलाओं ने राखी बांधी। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद यह छात्राएं बेहद उत्साहित दिखीं। कुछ दिव्यांगों ने भी पीएम की कलाई पर राखी बांधी। पश्चिम बंगाल में हावड़ा की रहने वाली इशरत जहां ने भी प्रधानमंत्री की कलाई पर तिरंगे वाली राखी बांधी है।

तत्काल तीन तलाक मामले में पांच याचिकाकर्ताओं में से एक इशरत जहां ने बताया कि उन्होंने सभी मुस्लिम महिलाओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल तीन तलाक को अवैध घोषित करने के लिए धन्यवाद कहा। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारा हक है और यह हमें मिलना ही चाहिए। उन्होंने बताया कि वह बड़े भाई मोदी के लिए कोलकाता से रसगुल्ले लाई थीं, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें दे नहीं पाईं। इशरत ने तब सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी जब 2014 में उसके पति ने दुबई से फोन पर उसे तीन बार तलाक कहकर छोड़ दिया था।

प्रधानमंत्री को राखी बांधने के लिए मुलाकात से पहले उनकी मुंहबोली बहन कमर मोहसिन शेख ने बताया कि उनके पास पीएम को देने के लिए एक सरप्राइज है। मैं उन्हें अपने पति की बनाई एक पेंटिंग भेंट करूंगी। शेख ने इस बात पर खुशी जताई कि उन्हें साल में एक बार प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करती हूं कि अगले पांच साल उनके सकारात्मक निर्णयों से इतने अच्छे हों कि पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक हो।

कमर मोहसिन शेख दरअसल एक पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो शादी होने के बाद भारत आईं। उन्होंने पहले बताया था कि वह पिछले 25 सालों से मोदी की कलाई पर राखी बांध रही हैं।

उन्होंने तत्काल तीन तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार के बनाए कानून की तारीफ करते हुए कहा कि कुरान और इस्लाम में तत्काल तीन तलाक के प्रावधानों का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और यह कदम नहीं उठा सकता था। मुस्लिम महिलाओं के हित में उन्होंने यह बहुत बड़ा कदम उठाया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका बड़ा प्रभाव होगा। ऐसे फैसले राजनीतिक साहस के साथ लिए जाते हैं। हमें खुशी है कि मोदी सरकार ने इस साहस का प्रदर्शन किया है।

रक्षाबंधन के अवसर पर गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मुंहबोली बहन कमर मोहसिन शेख ने राखी बांधी। एएनआइ

कह के रहेंगे माधव जोशी

15 सितंबर, 1891 को तिरुवनंतपुरम में क्रांतिकारी चेंबाकरमण पिल्लई का जन्म हुआ था। गुलामी के आदी हो चुके देशवासियों में आजादी की आकांक्षा के बीज डालने के लिए उन्होंने कॉलेज के दिनों के दौरान जय हिंद को अभिवादन के रूप में प्रयोग करना शुरू किया था।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 16 अगस्त 2019

कश्मीर से कन्याकुमारी तक आजादी का जश्न

उत्साह, उमंग और उल्लास ▸ किसी ने बेहतर शासन का लिया संकल्प, तो किसी ने रोजगार बढ़ाने का किया वादा

बाढ़ प्रभावित महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में सादगी से मना स्वतंत्रता दिवस

नई दिल्ली, प्रेट्र : देशभर में 73वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्यों में मुख्यमंत्रियों के संबोधन में शासन को और चुस्त-दुरुस्त बनाने से लेकर रोजगार के अवसर पैदा करने और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद के प्रभाव जैसे मुद्दे प्रमुखता में रहे। नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के बाद परेड की सलामी भी ली।

सबकी नजर जम्मू-कश्मीर पर थी। आजादी के 72 साल बाद पूरी तरह से भारत का अंग बने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तिरंगा फहराया। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मलिक ने कहा कि इससे न तो कश्मीर के लोगों की पहचान खतरे में पड़ी है और न ही उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है। इस फैसले से राज्य के विकास के दरवाजे खुलेंगे और विभिन्न समुदायों को जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। नए बदलाव को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर थी।

अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने का असर सुदूर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संबोधन में भी दिखा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में ध्वजारोहण के बाद लोगों को भरोसा दिलाया कि अनुच्छेद 371-एच के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस अनुच्छेद से राज्य को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं। इसी लाइन पर चलते हुए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा, '73 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मैं संविधान के अनुच्छेद 371 (एफ) की रक्षा, संरक्षण और समेकित करने का संकल्प करता हूं जो हमारे राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है।' वहीं, मिजोरम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने अपने संबोधन में विकास और प्रगति के बारे में चर्चा की। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर अपनी सरकार के रुख का बचाव किया और भूमिहीन परिवारों को जल्द ही जमीन का अधिकार देने के संबंध में नई नीति बनाने का वादा किया। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में तिरंगा फहराने के बाद लोगों तक सरकार के पहुंचने के एक कार्यक्रम की घोषणा की। इसके तहत मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक लोगों को फोन कर सरकार के कामकाज पर उनकी राय जानेंगे। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में महात्मा गांधी की अहिंसा को शामिल करने की मांग को भी आगे बढ़ाते हुए कहा कि इससे विदेशों में भारतीय लोकतंत्र का गौरव बढ़ेगा।

केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जश्न-ए-आजादी के त्योहार पर बाढ़ का असर दिखा। इन राज्यों में सादे समारोह में तिरंगा फहराया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावितों का जल्द से जल्द पुनर्वास की कोशिश में लगी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य के लोगों की नौकरियों में किसी तरह की कटौती नहीं होने देने की बात कही। चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में ध्वजारोहण के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने वेल्लोर जिले को तीन हिस्सों में बांटने की घोषणा की। केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने संविधान को कमजोर करने की कोशिश के खिलाफ चेताया।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा में भी वहां के मुख्यमंत्रियों ने तिरंगा फहराया और लोगों के कल्याण के लिए काम करने का संकल्प लिया।

स्वतंत्रता दिवस पर गुरुवार को श्रीनगर में भव्य आयोजन हुआ, जिसमें छात्र-छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। एएनआइ

अटारी-वाघा सीमा पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान मौजूद जनसैलाब ने भारत माता की जय के नारे लगाए। जागरण

अटारी पर उमड़ा देशभक्ति का सैलाब

जेएनएन, अमृतसर : 73वें स्वतंत्रता दिवस पर अटारी-वाघा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देशभक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जोश दिखाया तो भारत मां की जय के नारे गूंज उठे। गुरुवार को आयोजित रिट्रीट सेरेमनी में देशभक्ति की धारा बह उठी। पूरा माहौल अद्भुत था। स्टैंडों में खचाखच भरे लोग तिरंगा लहराते हुए जयघोष कर रहे थे। करीब 50 हजार की संख्या में देशभर से आए लोगों ने हाथों में तिरंगा ले रखा था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशभक्ति का भाव रहा। देश प्रेम जगाने वाले गानों पर सैलानियों ने खूब खूब डांस किया। मुख्य मेहमान बीएसएफ के महानिदेशक रजनीकांत मिश्रा रहे। वहीं, पूरे पंजाब में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। शहर-शहर, गांव-गांव वंदे वातरम के घोष और देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। राजस्तरीय समारोह जालंधर में हुआ, जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली।

सऊदी अरब में भी तिरंगे को सलामी

हज करने के लिए सऊदी अरब गए भागलपुर के पूर्व क्रिकेटर हसन खान ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सऊदी अरब में तिरंगे को सलामी देकर आजादी का जश्न मनाया।
फोटो सौजन्य – हसन खान

जेएनएन, नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश ही नहीं, विदेश में भी तिरंगा शान से फहराया गया। हज करने के लिए सऊदी अरब गए भागलपुर के पूर्व क्रिकेटर हसन खान ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सऊदी अरब में तिरंगे को सलामी देकर आजादी का जश्न मनाया।

हसन खान वर्तमान में नगर निगम में कार्यरत हैं। वह दो अगस्त को कोलकाता के रास्ते हज करने सऊदी अरब गए थे। नौवें दशक में हसन खान भागलपुर जिला क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज और विकेटकीपर रहे थे। सीनियर डिवीजन से संन्यास के बाद वह जिला जूनियर क्रिकेट टीम के चयनकर्ता और कोच भी रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर से हज करने सऊदी अरब के मक्का-मदीना गए हाजियों ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा लहराकर नई मिसाल पेश की।

भारत में कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं : सोनिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि भारत में कट्टरता और धर्मांधता के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सच्ची आजादी के लिए देश से हर अन्याय, असहिष्णुता और भेदभाव के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया है।

73वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर अपने संदेश में सोनिया गांधी ने सहानुभूति, सह-अस्तित्व और समग्र विकास के सिद्धांतों को नीति, समुदाय और अर्थव्यवस्था की अमिट विशेषताओं के रूप में फिर से स्थापित करने को कहा है। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ चुका है लेकिन मूल बुनियादी सिद्धांत सत्य, अहिंसा, संवेदना और देशभक्ति है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने देशवासियों को रक्षाबंधन की भी बधाई दी। उन्होंने ऐसे समाज की स्थापना होने की उम्मीद जताई जिसमें लिंग के आधार पर जरा भी भेदभाव नहीं होगा। एक बयान में उन्होंने कहा है, 'रक्षाबंधन हमारी गौरवशाली संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह पर्व न केवल बहनों-भाइयों के बीच पवित्र संबंध का परिचायक है बल्कि यह त्योहार देश के लोगों और समुदायों के बीच परस्पर प्रेम, भाईचारे तथा सहयोग को भी दर्शाता है।'

उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन है कि इस पवित्र-पर्व से पारिवारिक बंधन मधुर और मजबूत होंगे तथा एक ऐसे सुरक्षित समाज की स्थापना होगी, जिसमे लिंग के आधार पर भेदभाव की ज़रा सी भी गुंजाइश न हो।' कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद पार्टी नेताओं का अभिवादन करतीं वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी। जागरण

मोदी है तो मुमकिन है नारा सही : भागवत

नागपुर, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख सर संघचालक मोहन भागवत ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरे समाज ने प्रतिबद्धता दिखाई और इस मुद्दे पर दृढ़ इच्छाशक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले दिल से प्रशंसा की। भागवत ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं- मोदी है तो मुमकिन है, जो गलत नहीं है। देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लोगों में यह विश्वास जगा है कि वह नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान लोगों को बधाई देते हुए भागवत ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 370 हटाया जा सका, क्योंकि पूरे समाज ने इसके लिए प्रतिबद्धता दिखाई। आज के दिन हम आजादी के लिए दिए गए बलिदानों को याद करते हैं। इसके बाद डॉ. हेगड़ेवार स्मृति मंदिर परिसर में ध्वजारोहण करते हुए भागवत ने मोदी और जम्मू-कश्मीर का नाम लिए बगैर कहा कि यह लोगों की दृढ़ इच्छाशक्ति थी, देश के नेतृत्व को राज्य के लिए यह फैसला लेने के लिए मजबूती मिली।

उन्होंने कहा कि लोग प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं कि अगर वह हैं तो सब कुछ संभव है। यह सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इससे पहले सर कार्यवाह भय्याजी जोशी ने महल क्षेत्र में स्थित संघ मुख्यालय में ध्वजारोहण किया।

स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय में झंडारोहण के बाद सलामी देते संघ प्रमुख मोहन भागवत। एनएनआइ

क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं : नीतीश कुमार

जागरण संवाददाता, पटना : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म (अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता) से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। नीतीश ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में बिहार की अग्रणी भूमिका रही है। देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने और राष्ट्र निर्माण में हमेशा ही बिहार ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज बिहार में न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में हुए बदलाव की तस्वीर पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 तक राज्य के सभी पंचायतों में नौवीं कक्षा तक की पढ़ाई सुनिश्चित कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय योजना से पूरे राज्य की तस्वीर बदल रही है। हर घर नल जल योजना से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता गांव-गांव तक हो रही है। अगले वर्ष के अंत तक शहरी हो या ग्रामीण, सभी घर में नल का जल उपलब्ध होगा।

दारुल उलूम समेत मदरसों में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

जागरण संवाददाता, सहारनपुर

▸ मौलाना अरशद मदनी ने कहा, आजादी की लड़ाई में मुसलमानों, मदरसों और उलमा का भी योगदान

उप्र में सहारनपुर के दारुल उलूम समेत मदरसों में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। विश्व विख्यात इस्लामी शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद में डीएम आलोक पांडेय और कार्यवाहक मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मद्रासी ने झंडारोहण किया। राष्ट्रगान हुआ और छात्रों ने दारुल उलूम का तराना गाया। जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों, मदरसों और उलमा का अहम किरदार रहा है। दारुल उलूम का मकसद ही देश को अंग्रेजों से आजाद कराना था। जंग ए आजादी में उलमा ने कुर्बानियां दी। जमीयत उलेमा ए हिंद ने पूरी शिद्दत से आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिमों की अजीम कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ हिंदुस्तान नफरत की सियासत से नहीं, बल्कि मोहब्बत से चलेगा। इसलिए देश में रहने वाले हर मजहब और तबके के लोग देश की तरक्की के लिए आपसी भाईचारे को बढ़ाएं। गुरुवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर देश का आजादी दिलाने वालों शहीदों और वीरों को याद किया गया।

दारुल उलूम में ध्वजारोहण किया गया। जागरण

प्रदेश के युवाओं का रोजगार करेंगे सुनिश्चित : कमलनाथ

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के लोगों को ही देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी और अपने वादों को दोहराया। युवाओं से जुड़ी घोषणाओं पर उनका खासा जोर रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए भोपाल में निर्माणाधीन ग्लोबल स्किल पार्क में सालाना चार हजार 800 विद्यार्थियों को एडवांस प्रशिक्षण दिया जाएगा। संभागीय मुख्यालयों के आइटीआइ को मेगा आइटीआइ बनाया जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश बड़े शहरों में कौशल विकास के लिए नए केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण की क्वालिटी पर नजर रखी जा रही है। यही नहीं, शहरी बेरोजगारों को रोजगार और कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है।

आज देश का विकास नेहरू की सोच का नतीजा : गहलोत

जागरण संवाददाता, जयपुर : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी भाषण दिया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधने के साथ ही अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जैसे 2014 से पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। मैं कहता हूं कि आज मुल्क अपने जिन पांवों पर खड़ा है, उसकी नींव का पत्थर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था।

उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में जो आज विकास हो रहा है, वह नेहरू की ही सोच का नतीजा है। नेहरू ने सिंचाई के लिए नहर और बांध बनाए। प्लांट लगाए। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए योजनाएं बनाईं। भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि माहौल कुछ भी बनाया जाए, लेकिन सच्चाई अलग है। इसरो की स्थापना उस वक्त हुई थी। तभी आज सैकड़ों उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। गहलोत ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि हर गांव और कस्बे की भावना थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं।

बड़ी घोषणाएं

हिमाचल में प्रतियोगी परीक्षा के लिए महिला अभ्यर्थियों को नहीं देनी पड़ेगी फीस

जेएनएन, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अब महिला अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग और दूसरे बोर्डों की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ऐसे में अब लोक सेवा आयोग, कर्मचारी अधीनस्थ चयन बोर्ड और शिक्षा बोर्ड के माध्यम से की जानी वाली विभिन्न विभागों की भर्तियों में महिला अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी पड़ेगी, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो। सीएम का यह फैसला हजारों बेरोजगार महिला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सौगात है। इसके साथ ही सीएम ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए चार फीसद महंगाई भत्ते का एलान किया है। सीएम ने कहा इससे सरकार के खजाने पर 260 करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। नौवीं और दसवीं के बच्चों को मुफ्त किताबें देने का ऐलान भी किया है। प्रदेश के 65 हजार छात्रों को 1500 रुपये तक की किताबें मुफ्त दी जाएंगी। सीएम ने पूर्व सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों की सालाना वित्तीय मदद भी दस हजार से बढ़ाकर 20 हजार कर दी है।

छत्तीसगढ़ में बनेगा एक और जिला

नईदुनिया, रायपुर : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में एक और जिला बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को जनहित के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए एक ओर जहां अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने मूल कार्यों पर ध्यान देने के लिए सचेत किया है, वहीं जवाबदेही तय करने के लिए 'लोकसेवा गारंटी अधिनियम' का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं एक और बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए एक नए जिले के निर्माण की घोषणा करता हूं। यह जिला 'गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही' के नाम से जाना जाएगा। इस तरह अब छत्तीसगढ़ 28 जिलों का राज्य बन जाएगा। इसके अलावा 25 नई तहसीलें भी बनाई जाएंगी।

इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को नया 'एलिफेंट रिजर्व' मिलेगा, जो कोरबा जिले के लेमरू में होगा। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला 'एलीफेंट रिजर्व' होगा, जहां हाथियों का स्थाई ठिकाना होगा।

अब निंबार्क के नाम से पहचाना जाएगा राजस्थान का सलेमाबाद

संवाद सूत्र, अजमेर : जगतपिता भगवान ब्रह्मा के पावन धाम पुष्कर के अरण्य क्षेत्र में स्थित अति प्राचीन निंबार्क तीर्थ का गौरव लगभग 500 सालों बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से लौट आया है। दरअसल, सलेमाबाद के नाम से पहचाने जाने वाले इस इलाके का नाम बदलने की केंद्र ने अनुशंसा की, जिस पर राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने बदलाव कर दिया। इसके लिए निंबार्क पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण ने काफी प्रयास किया था।

सलेमाबाद का नाम बदलने के लिए पूर्व युवराज और वर्तमान में निंबार्क पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण जी प्रयासरत थे। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सलेमाबाद का नाम बदलने की अनुशंसा की और उन्हीं के निर्देशों के चलते राजस्थान सरकार ने अब हमेशा-हमेशा के लिए सलेमाबाद नाम समाप्त कर इसका नाम श्री निंबार्क तीर्थ करने की घोषणा कर दी है।

माना जाता है कि लगभग 5116 साल पहले स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्रज भूमि पर निंबार्क संप्रदाय की स्थापना की गई थी। आज देश और दुनिया में लाखों की तादात में इसके अनुयायी हैं।

कश्मीर में शान से लहराया तिरंगा, लगे वंदे मातरम के नारे

जश्न

राज्यपाल ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले से क्षेत्रीय पहचान को कोई संकट नहीं, राजनीति समेत सभी क्षेत्रों में युवाओं से आगे आने की अपील की

नवीन नवाज, श्रीनगर

डल झील के किनारे स्थित गोपाद्री पर्वत पर जहां आदि शंकराचार्य ने शंख बजाकर शैववाद को पुनर्स्थापित किया था, आज उसी गोपाद्री पर्वत की तलहटी में स्थित शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास बना। इस दौरान भीड़ बेशक कम थी, लेकिन दर्शक दीर्घा में तिरंगा लहराते और वंदे मातरम का नारा लगाते युवाओं ने बता दिया कि वे बदलाव और राष्ट्र की मुख्यधारा का हिस्सा बनने का जश्न मना रहे हैं।

गुरुवार को कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि, सुरक्षा प्रबंध बीते सालों की तरह चाकचौबंद थे, लेकिन जो तनाव 15 अगस्त या 26 जनवरी को कश्मीर में रहता था वह कहीं नहीं दिखा। न कोई बंद का एलान था और न किसी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार करने का फरमान सुनाते हुए कहा कि जो जाएगा, भुगतेगा। ऐसे में धीरे-धीरे लोग शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में जमा होने लगे। जो भी मैदान में पहुंचा, उसने कहा कि यह एतिहासिक दिन है।

जम्मू-कश्मीर से अनु.370 हटाए जाने के बाद गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मच्छल सेक्टर में स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों को गले लगाकर मुंह मीठा कराया और स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद दी। एएनआइ

शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने उन्हें यकीन दिलाया कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने पर उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, बल्कि सच तो यह है कि इससे आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सुशासन, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। नौकरी के रास्ते खुलेंगे। कश्मीरी, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, बालटी, शीना सहित अन्य भाषाएं नए सेटअप में कामयाब होंगी। राज्य में सभी जनजातियों और जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी पहचान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।

स्टेडियम में अपनी पांच साल की बेटी संग आए मुश्ताक अहमद ने कहा कि यह एक नए दौर की शुरुआत जैसा है। मैं 45 साल का हूं। बीते 30 सालों में मैने पहली बार यहां किसी को आम कश्मीरियों को यौम-ए-स्याह बनाने का हुक्म नहीं सुनाया है। किसी ने काले झंडे लहराने को नहीं कहा है।

फारूक, उमर और महबूबा के बारे में नहीं हुआ कोई सवाल : राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती स्वतंत्रता समारोह में शामिल नहीं हुए। यह तीनों वादी में ही हैं। फारूक अपने घर में नजरबंद हैं, जबकि उमर और महबूबा को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में रखा हुआ है। इनके अलावा भी कश्मीर केंद्रित सियासत करने वाले मुख्यधारा के राजनीतिक दलों का कोई नेता या कार्यकर्ता इस समारोह का हिस्सा नहीं बना, लेकिन किसी ने भी उनकी अनुपस्थिति पर सवाल नहीं किया।

एकीकृत जम्मू कश्मीर राज्य का अंतिम समारोह : आज पूरे देश में 73वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया है, लेकिन एकीकृत जम्मू-कश्मीर में अंतिम बार स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया है, क्योंकि 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित राज्यों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बदल जाएगा। ऐसे में आगे से जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल और लद्दाख में उपराज्यपाल ही राष्ट्रध्वज फहराएंगे।

समारोह में मौजूद थे डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। वह बीते 10 दिनों से कश्मीर में ही हैं और यहां सुरक्षा-व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। किसी राज्य में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के भाग लेने का यह पहला मौका है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। एएफपी

श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में तिरंगा फहराने के बाद सैल्यूट करते राज्यपाल सत्यपाल मलिक। प्रेट्र

150 यात्रियों के साथ श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गुरुवार रात में एक विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ। यह पहली बार है जब रात में किसी विमान ने यहां से उड़ान भरी है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने यह जानकारी दी।

मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी कई घंटे फंसी रही पैसेंजर ट्रेन

परेशानी ▸ घंटों इंतजार के बाद वापस झांसी भेजी गई

पानी निकालने की शाम तक हुई मशक्कत

नईदुनिया, भोपाल

पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते दिल्ली-मुंबई रेल लाइन के झांसी और भोपाल स्टेशनों के बीच ट्रैक पर अचानक पानी बढ़ने से एक पैसेंजर ट्रेन कई घंटे तक फंसी रही। बाद में पानी कुछ कम हुआ तो ट्रेन को वापस झांसी की ओर लौटाया गया। इसके बाद और हालत सुधरे तो अन्य स्टेशनों पर रुकी ट्रेनों को कॉशन ऑर्डर पर निकाला गया। इस दौरान कई ट्रेनों जहां की तहां फंसी रहीं। देर शाम तक रेल विभाग का अमला ट्रैक पर भरे पानी को निकालने और ट्रैक को सुधारने में जुटा रहा।

झांसी से बीना की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को धौर्रा और मोहासा स्टेशन के बीच अचानक ट्रैक पर पानी देखकर ट्रेन को रोकना पड़ा। यह जगह मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना स्टेशन और उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्टेशन के बीच आती है। सुबह करीब नौ से दस बजे के समय की यह घटना बताई जा रही है। जहां ट्रेन रुकी, वहां पहाड़ी को काटकर रेल लाइन बिछाई गई है। एक ओर से पहाड़ी से आ रहा पानी का तेज प्रवाह ट्रैक पर ही गिर रहा था। ऐसे में वहां पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। ड्राइवर ने तत्काल इसकी सूचना रेल अधिकारियों के साथ ही बीना और ललितपुर स्टेशनों पर दी। इस पैसेंजर ट्रेन में सामान्य श्रेणी के दस डिब्बे होते हैं। रक्षाबंधन का दिन होने के कारण सभी डिब्बों में भीड़ थी।

अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ट्रैक पर पानी का आना लगातार जारी था। ऐसे में कोई जोखिम न लेते हुए पैसेंजर ट्रेन को वापस झांसी की ओर लौटाने का फैसला लिया गया। इसमें भी खतरा था, क्योंकि जहां ट्रेन रुकी हुई थी, वहां भी ट्रैक डूब चुका था। दोपहर के डेढ़ बजे के बाद जब पानी कम होना शुरू हुआ तो ट्रैक को सुधारना शुरू किया गया। साथ ही वहां जमा पानी निकालने के लिए कोशिश शुरू हुई। इसके बाद कॉशन आर्डर पर ट्रेनें निकालना शुरू हुआ। समाचार लिखे जाने तक मौके पर सैकड़ों की संख्या रेल कर्मी जुटे हुए थे। इसके चलते दर्जनों ट्रेनों को दोनों ओर से स्टेशनों पर रोक दिया गया था।

झांसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिह के मुताबिक पानी में फंसी पैसेंजर ट्रेन को वापस कर दिया गया है। अब सबकुछ ठीक है। इस घटना के कारण झांसी की तरफ आने वाली ट्रेन झेलम एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, एपी एसी एक्सप्रेस, पंजाब मेल घंटों देरी से रवाना हो सकीं। भोपाल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 22163 भोपाल-खजुराहो महामना एक्सप्रेस करौंदा स्टेशन पर निरस्त होकर वहीं से वापस भोपाल आएगी और गुरुवार रात को खजुराहो से चलने वाली गाड़ी संख्या 22164 महामना एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

मूसलधार बारिश से इस तरह रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। नईदुनिया

नहीं रहीं बॉलीवुड की 'रजनीगंधा'

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

▸ मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में विद्या सिन्हा ने ली आखिरी सांस

बासू चटर्जी निर्देशित फिल्म रजनीगंधा में अपने अभिनय से प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंची बॉलीवुड की अभिनेत्री 71 विद्या सिन्हा का फेफड़े और हृदय संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया। जुहू के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें रविवार को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था।

1974 में मशहूर कहानीकार मन्नू भंडारी की कहानी 'यही सच है' पर बनी फिल्म रजनीगंधा से वह चर्चा में आई थीं। इस फिल्म में लता मंगेशकर का गाया शीर्षक गीत 'रजनीगंधा फूल तुम्हारे' को आज भी लोग चाव से सुनते हैं। अभी तक करीब 25 फिल्मों में काम कर चुकी विद्या 2011 में आखिरी बार फिल्म बॉडीगार्ड में कैमियो के रोल में नजर आई थीं। 1974 में फिल्म 'राजा काका' से बड़े पर्दे पर कदम रखने वाली विद्या पिछले कुछ समय से छोटे पर्दे पर सक्रिय थीं। इन दिनों वह धारावाहिक 'कुल्फी कुमार बाजेवाला' में दादी का किरदार निभा रही थीं। खराब स्वास्थ्य के चलते एक महीने से वह शो से दूर थीं। इसके अलावा छोटे पर्दे पर 'काव्यांजलि', 'हार जीत', 'कुबूल है' और 'इश्क का रंग सफेद' 'चंद्र नंदिनी' धारावाहिकों में भी उन्होंने काम किया।

15 नवंबर 1947 को जन्मी विद्या के पिता राणा प्रताप सिंह फिल्म निर्माता थे। मॉडलिंग से उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया था। मिस बांबे प्रतियोगिता जीतने के बाद फिल्म निर्माता बासु चटर्जी की उनपर नजर पड़ी। फिल्म 'राजा काका' उनकी शादी के बाद रिलीज हुई।

विद्या सिन्हा की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही। 1996 में उनके पति वेंकटेश्वरन अय्यर का निधन हो गया था। दोनों की एक बेटी जाह्नवी है। अय्यर के निधन के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए अभिनय से दूरी बना ली थी। 2001 में उन्होंने नेताजी भीमराव सालुंखे से दूसरी शादी की थी। हालांकि शादी टिक नहीं सकी। वर्ष 2009 में उन्होंने सालुंखे के खिलाफ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसी साल दोनों में तलाक भी हो गया था।

विद्या सिन्हा। फाइल फोटो

विद्या सिन्हा की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। अपने बेहतरीन काम की वजह वह हमेशा याद की जाएंगी। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों और मित्रों के साथ हैं।
मधुर भंडारकर, फिल्म निर्माता-निर्देशक

प्यारी अभिनेत्री विद्या सिन्हा के निधन पर गहरा दुख हुआ। उनकी मधुर आवाज और अलौकिक सुंदरता उन्हें दूसरों से अलग करती थी। फिल्म 'तेरे आने से' में उनकी बेटी के रूप में काम कर मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ हैं।
रितुपर्णा सेनगुप्ता, फिल्म अभिनेत्री एवं निर्माता

उल्लेखनीय फिल्में

'हवस' (1974), 'छोटी सी बात' (1975), 'मेरा जीवन' (1976), 'इन्कार', 'किताब' (1977), 'पति, पत्नी और वो', 'सफेद झूठ' (1978), 'सुबूत' (1980), 'लव स्टोरी', 'जोश' (1981)।

न्यूज गैलरी

घर से होटल में शिफ्ट किए गए नजरबंद शाह फैसल

श्रीनगर : नजरबंद पूर्व आइएएस अधिकारी शाह फैसल को उनके घर से होटल में शिफ्ट किया गया है। उन्हें बुधवार रात श्रीनगर के सेंटोर होटल में भेजा गया। बता दें जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के अध्यक्ष शाह फैसल को मंगलवार रात इस्तांबुल जाने से दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था। इसके बाद बुधवार को श्रीनगर भेज दिया गया, जहां उन्हें जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंद कर दिया गया। पूछताछ के दौरान फैसल ने बताया था कि वह दिल्ली से लंदन वाया इस्तांबुल जा रहे थे। उन्हें इस्तांबुल से लंदन की उड़ान लेनी थी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का शाह विरोध कर रहे हैं। (प्रेट्र)

असीत त्रिपाठी बने ओडिशा के मुख्य सचिव

भुवनेश्वर : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने आइएएस स्तर पर फेरबदल किया है। असीत त्रिपाठी को मुख्य सचिव बनाया गया है। 1986 बैच के आइएएस अधिकारी असीत वर्तमान समय में विकास कमिश्नर हैं। वह सुंदरगढ़ के जिलाधीश रह चुके हैं। सुरेश महापात्र को विकास कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उन्हें श्रीमंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। प्रदीप्त महापात्र को कृषि उत्पादन कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति मिली है। किशन कुमार को श्रीमंदिर के मुख्य प्रशासक के तौर पर अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। किशन कुमार वर्तमान समय में वर्क्स डिपार्टमेंट के सचिव हैं। आर बालकृष्णन को सीएमओ सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। (जासं)

बालिका की बहादुरी से पकड़े गए दुष्कर्म की नीयत से अपहरण करने वाले

उदयपुर : स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाकर लौट रही स्कूल की दो नाबालिग लड़कियों को दुष्कर्म की नीयत से आरोपित उठा ले गए। एक बालिका की बहादुरी से दो अपहरणकर्ता पकड़े गए। जानकारी के अनुसार ओगणा थाना क्षेत्र में स्कूल से लौट रही बालिकाओं का अपहरण कर लिया गया। कार में दुष्कर्म का प्रयास कर रहे एक आरोपित के हाथ में एक बालिका ने बहादुरी दिखाते हुए काट लिया। इसके साथ ही उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाने पर आवाज सुनकर अपहरणकर्ता की कार का ग्रामीणों ने पीछा शुरू कर दिया। निकट गांव में ग्रामीणों की घेराबंदी कर दो आरोपितों को पकड़ लिया, जबकि एक फरार हो गया। पकड़े गए आरोपितों की ग्रामीणों ने जमकर की धुनाई की। (संवाद सूत्र)

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर केंद्र सरकार ने सेनाओं से मांगी है राय

▸ अगले कुछ हफ्तों में तीनों सेनाओं से जवाब मिलने की उम्मीद

▸ सरकार के फैसले से इंटीग्रेटेड कमान बनाने का भी मिला संकेत

नई दिल्ली, एएनआइ : देश में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति की दिशा में केंद्र सरकार कदम बढ़ा चुकी है। इस संबंध में तीनों सेनाओं से राय मांगी गई है। नए पद की रूपरेखा तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक, अगले कुछ हफ्तों में सेनाओं की ओर से इस संबंध में राय मिलने की उम्मीद है।

सीडीएस से जुड़ी पूरी व्यवस्था तैयार करने का काम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के परामर्श और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। सीडीएस की भूमिका और कार्यकाल जैसे बिंदुओं पर निर्णय के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। देश में सैन्य प्रमुखों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस हो सकते हैं। 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के सेवानिवृत्त होने के बाद रावत तीनों सेनाओं में सबसे वरिष्ठ होंगे।

सीडीएस की नियुक्ति पर सरकार का यह फैसला इंटीग्रेटेड थिएटर कमान की स्थापना का भी संकेत माना जा रहा है। सरकार में कई लोगों का मानना है कि इस तरह की कमान बनाई जानी चाहिए। इस कमान में तीनों सेनाओं के जवान और अन्य व्यवस्थाओं को जगह दी जाएगी। इसका नियंत्रण एक अधिकारी के हाथ रहेगा। अमेरिका जैसे कई पश्चिमी देशों में ऐसी कमान हैं। भारत में इस तरह की कम से कम दो कमान बनाने की बात चल रही है। एक कमान पश्चिम में पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटने के लिए होगी और दूसरी कमान पूर्व में चीन से निपटने के लिए होगी।

विशेषज्ञों ने किया सरकार की पहल का स्वागत

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने सीडीएस के गठन पर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इसे सैन्य सुधारों की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) वीपी मलिक ने कहा, 'ऐतिहासिक कदम के एलान के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी। यह कदम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावी और किफायती बनाएगा। सैल्यूट!'

पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल (सेवानिवृत्त) सुनील लांबा ने भी इसे बड़ा कदम बताया। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीबी शेकातकर ने इसे स्वागतयोग्य कदम बताया। उन्होंने कहा, 'मेरी अध्यक्षता में गठित समिति ने सरकार के समक्ष जो 188 सिफारिशें रखी थीं, यह उनमें से एक है।' शेकातकर की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति बनाई थी। समिति ने दिसंबर, 2016 में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। दैनिक जागरण से बातचीत में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एनसी विज ने कहा कि इससे तीनों की सेनाओं की ताकत समान रूप से बढ़ेगी। तीनों सेनाओं की बात एक साथ सरकार तक पहुंचेगी। इससे सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों और अन्य सुविधाओं से लैस करने का काम भी तेज होगा।

भाजपा नेताओं ने की प्रधानमंत्री के भाषण की सराहना

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की भाजपा नेताओं ने जमकर सराहना की है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण बेहद प्रेरणादायक है जो नए भारत के निर्माण का उनका संकल्प दर्शाता है।

नड्डा ने भाजपा मुख्यालय पर राष्ट्रध्वज फहराने से पूर्व कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने इस उम्मीद से लंबी छलांग लगाई है कि वह दुनिया के विकसित देशों में शुमार होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब ऐसा निश्चित तौर पर होकर रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगी संजीव बाल्यान को गले लगाते एक फोटो भी शेयर किया। संयोग से बाल्यान ने जनसंख्या पर रोक के लिए लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। अपने भाषण में जनसंख्या विस्फोट के बारे में बोलने के लिए बाल्यान ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि इसे किसी जाति और धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

अभिनंदन को पाक के एफ-16 को मार गिराते देखा था : मिंटी

▸ बालाकोट एयरस्ट्राइक के दौरान फ्लाइट कंट्रोलर रहीं स्क्वाड्रन लीडर ने घटनावाले दिन की दी जानकारी

▸ कहा, भारत के सुखोई-30 को मार गिराने का पाकिस्तान का दावा भी झूठा

नई दिल्ली, एएनआइ : बालाकोट एयरस्ट्राइक के दौरान फ्लाइट कंट्रोलर रहीं स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि किस तरह से 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के एफ-16 विमान को मार गिराया था। इस कार्रवाई में अहम भूमिका निभाने वाली स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया है। यह मेडल पाने वाली वह पहली महिला रक्षा अधिकारी हैं।

मिंटी अग्रवाल ने बताया 'फाइट कंट्रोलर के तौर पर ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं अपने एयरक्राफ्ट को गाइड करूं। इसके साथ ही मुझे पायलट्स को ये सूचना भी देनी थी कि वो किन हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें कब और कहां से मिसाइल लॉन्च करना चाहिए।' मिंटी अग्रवाल आगे बताती हैं, 'मैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भी निर्देश दे रही थी। मैंने उन्हें हवा में क्या स्थिति है ये पूरी तरह से समझाया। इसी दौरान पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की स्थिति के बारे में उन्हें बताया और उन्होंने अपने टार्गेट पर अचूक निशाना साधा। मैंने अपनी आंखों के सामने ही स्क्रीन पर एफ-16 को हवा में गिरते हुए देखा था।'

भारत की कार्रवाई को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को हमने बालाकोट में आतंकी शिविरों पर एयरस्ट्राइक के मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। स्क्वाड्रन लीडर ने कहा, 'हमें लग रहा था कि पाकिस्तान इसके बाद तुरंत कार्रवाई करेगा। हम सभी पूरी तरह से तैयार थे। पाकिस्तान ने 24 घंटे में ही भारत में बम गिराने की नाकाम कोशिश की। शुरू में पाकिस्तान के बहुत कम विमान थे लेकिन जल्द ही उनकी संख्या बढ़ गई थी।'

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई को देखते हुए हमने पहले ही सीमा पर विमान तैनात कर दिए थे। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन इन विमानों की तैनाती को देखकर वह डर गए और भाग गए। उन्होंने पाकिस्तान के उस दावे को भी झूठा बताया, जिसमें कहा गया था कि उसने 27 फरवरी को भारतीय वायु सेना के सुखोई-30 विमान को मार गिराया था।

सतलुज नदी पार कर पाकिस्तान से आया, हेरोइन के साथ गिरफ्तार

जेएनएन, फिरोजपुर

▸ एक दिन पहले सीमा पर गायब हो गया था हरजिंदर

▸ हथियार, मोबाइल व पीओके का सिम भी बरामद

टायर ट्यूब के सहारे सतलुज नदी पार कर पाकिस्तान से भारत आए तस्कर को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। उससे हेरोइन (31 पैकेट), एक मैगजीन, 31 राउंड कारतूस, एक मोबाइल फोन और गुलाम कश्मीर (पीओके) का एक सिम बरामद हुआ है।

आरोपित हरजिंदर सिंह फिरोजपुर के गांव पल्ला मेघा का रहने वाला है। बीएसएफ के अनुसार कुछ दिन पहले उसकी मां का देहांत हो गया था। बुधवार को उनका भोग था। हरजिंदर शाम के समय सरहद किनारे घूमते-घूमते गायब हो गया। गांव वालों के बीच चर्चा हुई तो बात बीएसएफ की खुफिया विंग तक पहुंची। इसके बाद सीमा पर बहती सतलुज नदी पर पहरा कड़ा कर दिया गया। रात तीन बजे हरजिंदर एक टायर ट्यूब के सहारे नदी पार करते नजर आया। किनारे पर पहुंचते ही बीएसएफ ने दबोच लिया। तलाशी लेने पर पता चला कि वह ट्यूब में छिपाकर 16 किलो हेरोइन, हथियार सहित अन्य सामान ला रहा था।

पुलिस कर रही जांच, आतंकियों से तो नहीं जुड़े तार

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कड़ी सुरक्षा के दावों के बीच हरजिंदर का पाकिस्तान चले जाना और हेरोइन व हथियारों के साथ लौटना हैरान करने वाला है। बता दें कि गुरदासपुर के दीनानगर और पठानकोट एयरबेस पर हमले के दौरान आतंकवादी नदी के ही रास्ते में घुसे थे। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं हरजिंदर के तार आतंकवादियों से तो नहीं जुड़े हैं। उसे ओल्ड महमूदी की बॉर्डर आउटपोस्ट से गिरफ्तार किया गया।

रक्षाबंधन पर जनेऊ संस्कार

अहमदाबाद में बहन-भाई के स्नेह के पावन पर्व रक्षाबंधन पर गुरुवार को मंदिर में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण बच्चों ने प्रार्थना की और जनेऊ संस्कार (यज्ञोपवीत) कराया। रायटर

झारखंड के मंत्री को साइबर अपराधियों ने कॉल कर दी गालियां

जागरण संवाददाता, रांची : साइबर अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे वीआइपी तक को भी अपना निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह को भी साइबर अपराधियों ने कॉल किया। कॉल करने वाले ने पहले एकाउंट बंद होने की बात कह अकाउंट नंबर और आधार नंबर मांगा। इस पर जब मंत्री ने धन्यवाद कहा तो अपराधियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इस मामले में नगर विकास मंत्री ने मामला दर्ज कराया है।

मंत्री ने पुलिस को बताया कि बुधवार शाम करीब चार बजे उनके मोबाइल पर फोन आया। फोन उठाते ही कॉल करने वाले ने कहा कि वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बोल रहा है। मंत्री समझ गए कि किसी साइबर अपराधी का कॉल आया है। साइबर अपराधी ने अकाउंट बंद होने की बात कही। इस पर मंत्री ने धन्यवाद कहा। बोले कि आपने सूचना देकर अच्छा काम किया है। यह सुनते ही साइबर अपराधी ने मंत्री से गाली-गलौज शुरू कर दी। वह लगातार गालियां देता रहा। इस पर मंत्री ने फोन काट दिया।

राजनीति

पूर्व सीएम ने अलग पार्टी बनाने का फैसला अपने समर्थकों पर छोड़ा, भजनलाल, बंसीलाल व बीरेंद्र के अलग पार्टी बनाने के अनुभव नहीं रहे ठीक

हुड्डा के अगले कदम पर विरोधियों की खास निगाह

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक में होने वाली महा परिवर्तन रैली पर दूसरे राजनीतिक दलों के साथ-साथ कांग्रेस में ही हुड्डा विरोधी खेमे की भी निगाह टिकी हुई है। हुड्डा की 18 अगस्त की रैली से पहले प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर जहां हुड्डा विरोधी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं हुड्डा ने नई पार्टी बनाने का फैसला कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है। पूर्व सीएम अपने समर्थकों की सलाह पर ही कोई फैसला लेंगे।

हरियाणा कांग्रेस की बागडोर नहीं मिलने से नाराज समर्थकों ने हुड्डा पर अलग पार्टी बनाने का दबाव बना रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी तथा चौ. भजनलाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया था। कांग्रेस में रहते हुए चौ. बीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस तिवारी के नाम से अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन इन पार्टियों का हश्र अच्छा नहीं रहा। ऐसे में हुड्डा कार्यकर्ताओं की राय के बिना कोई कड़ा फैसला लेने के मूड में नहीं हैं। हुड्डा की इस रैली से पहले कांग्रेस हाईकमान ने शुक्रवार को हरियाणा के प्रमुख नेताओं की बैठक बुला रखी है, जिसमें सभी धड़ों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बैठक में भी हुड्डा को मनाने की कोशिश हो सकती है। हुड्डा समर्थक विधायकों का कहना है कि पिछले छह साल से संगठन बिल्कुल कमजोर हो गया। इसलिए चुनाव के वक्त अब बागडोर हुड्डा को दी जानी चाहिए, ताकि विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जा सके।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को ही हुड्डा ने अपने निवास पर कुछ विधायकों की बैठक बुला रखी थी, लेकिन अब यह बैठक नहीं होने जा रही है। हुड्डा से इतर अशोक तंवर ने जरूर गुरुग्राम में अलग से एक बैठक बुला ली, जिसमें हुड्डा विरोधी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। घोषित रूप से यह बैठक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती कार्यक्रमों की तैयारियों के सिलसिले में बुलाई गई है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फाइल फोटो

हर क्षेत्र में 52 हजार सदस्यों का परिवार तैयार कर रही भाजपा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा भाजपा ने भले ही 75 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन उसकी निगाह राज्य की सभी 90 सीटों पर है। भाजपा ने बड़े ही रणनीतिक ढंग से हर हलके में कम से कम 52 हजार सदस्य बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। फिलहाल भाजपा के हर विधानसभा क्षेत्र में 36-36 हजार सदस्य हैं, जिनमें 16-16 हजार की बढ़ोतरी होनी है। यह टारगेट अगले एक सप्ताह के भीतर पूरा करने की योजना बनाई गई है। पिछले माह हरियाणा भाजपा को साढ़े छह लाख नए सदस्य जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रदेश संगठन ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है, जिसके बाद अब साढ़े आठ लाख और नए सदस्य बनाने का टारगेट संगठन को दे दिया गया है। इसे 20 अगस्त तक पूरा करना है, लेकिन इस काम को आगे भी विधानसभा चुनाव से पहले पहले पूरा किया जा सकता है। राज्य में भाजपा के 32 .5 लाख सदस्य हैं। 11 अगस्त तक साढ़े छह लाख नए सदस्य बनाकर इस संख्या को 39 लाख तक पहुंचाना था, जिसमें सफलता हासिल कर ली गई है। अब यह लक्ष्य 15 लाख कर दिया गया है। यानी लक्ष्य में साढ़े आठ लाख नए सदस्य जोड़ने की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। भाजपा अब राज्य में 47 .50 लाख सदस्यों का परिवार खड़ा करेगी। हर हलके में जिस पार्टी को 50 हजार से अधिक मत हासिल हो जाएं, उसकी जीत की राह आसान हो जाती है।

चंडीगढ़ के पीजी में दो बहनों की गला रेतकर हत्या

जेएनएन, चंडीगढ़

स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस प्रबंधों को धता बताते हुए शहर के बीचोंबीच स्थित सेक्टर-22 में दो सगी बहनों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दोनों यहां पीजी में रह रही थीं। हत्या का पता गुरुवार सुबह चला।

पंजाब के अबोहर निवासी दोनों बहनें राजवंत कौर और मनप्रीत कौर जीरकपुर स्थित एक फैक्टरी में काम करती थीं। दोनों सेक्टर 22 स्थित पीजी (मकान नंबर 2598) में पिछले चार सालों से रह रही थीं। गुरुवार सुबह परिजनों ने दोनों बहनों को बार-बार फोन किया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। तब उन्होंने चंडीगढ़ में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार को फोन किया। वह रिश्तेदार पहुंचे तो पीजी के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। उन्हें कुछ शक हुआ। ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो माहौल देखकर घबरा गए। अंदर दोनों बहनों के शव लहूलुहान अवस्था में पड़े थे। चारों तरफ खून फैला हुआ था। तब जाकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पत्नी से वीडियो कॉल करते समय जवान ने की खुदकशी

नईदुनिया, जगदलपुर : पत्नी के साथ वीडियो पर कॉल करते समय एक जवान ने आत्महत्या कर ली। जब उसने खुद को गोली मारी वह ड्यूटी पर तैनात था। जानकारी के अनुसार पांचवीं बटालियन छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स (सीएएफ) के जवान सुभाष यादव ने गुरुवार शाम चार बजे खुद को गोली मार ली। उन्होंने जब आत्महत्या की तब वह पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के बोरगांव निवासी सुभाष 12 अगस्त को ही अवकाश से लौटे थे।

Downloaded from: www.iascgl.com

दैनिक जागरण

उत्तरदायित्व के बोध के बिना स्वतंत्रता निरर्थक है

भावी भारत का खाका

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में जो कुछ कहा उसमें बहुत कुछ उल्लेखनीय है, लेकिन जो सर्वाधिक उल्लेखनीय है वह यह कि उन्होंने बढ़ती आबादी की चुनौतियों को रेखांकित करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की कि वे जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के बारे में भी सोचें। प्रधानमंत्री ने जिस तरह सीधे-सपाट शब्दों में कहा कि छोटा परिवार रखना भी अपनी देशभक्ति प्रकट करने का तरीका है और हर किसी को यह सोचना चाहिए कि जो शिशु धरती पर आने वाला है उसकी आवश्यकताएं कैसे पूरी की जाएंगी, उस पर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। यह ऐसा विषय है जो किसी नियम-कानून से अधिक जनजागरूकता से ही हल होगा। देशहित से जुड़े ऐसे विषयों पर संकीर्ण राजनीति की कहीं कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने देश के उद्योग जगत को यह भरोसा दिलाया कि उसे किसी तरह की आशंका रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार देश के विकास में योगदान देने और रोजगार के अवसर पैदा करने वाले उद्यमियों को मान-सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भरोसा इसलिए जरूरी था, क्योंकि उद्योग जगत ही देश की संपदा बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन अनेक राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उद्यमियों-उद्योगपतियों के प्रति लोगों को बरगलाने का काम करते हैं।

लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन कुल मिलाकर अगले पांच साल के लिए देश के भावी पथ की तस्वीर बयान करता है। अपने संदेश में उन्होंने विकास के प्रति प्रचलित धारणाओं को बदलने पर तो जोर दिया ही, यह भी साफ किया कि सुधार के लिए साहसिक कदमों का सिलसिला और तेज होगा। एक ऐसा ही सुधार पूरे देश में एक साथ चुनाव के रूप में हो सकता है, जिसके प्रति प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपना संकल्प व्यक्त किया है। यदि लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का मार्ग प्रशस्त होता है तो यह एक क्रांतिकारी बदलाव ही होगा। देश इस बदलाव का इंतजार कर रहा है, क्योंकि यह उचित नहीं कि विकास और सुशासन आए दिन आदर्श आचार संहिता की बंदिशों में कैद रहें। बेहतर हो कि राजनीतिक दल एक साथ चुनाव पर आम सहमति कायम करें। ये सहमति तभी कायम होगी जब वे चुनाव सुधारों पर अपने किंतु-परंतु का त्याग करेंगे। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 75 दिनों में जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं उससे यह भरोसा मजबूत होता है कि लाल किले से प्रधानमंत्री ने जो भी घोषणाएं की हैं और भावी भारत का खाका खींचा वैसा वास्तव में हो सकेगा।

पुलिस पर हमला

मॉब लिंचिंग को लेकर बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों ने असहिष्णुता की बातें करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। विरोधी दलों ने कई सवाल उठाए थे, परंतु मॉब लिंचिंग से बचाने की जिम्मेवारी जिस पुलिस पर है यदि उसका ही लिंचिंग, वह भी थाने में, होने लगे तो स्थिति कहां तक पहुंच चुकी है इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। वह भी किसी दूर दराज के ग्रामीण इलाके में नहीं, बल्कि कोलकाता जैसे महानगर में थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई की गई। वह भी किस लिए, एक नशेड़ी बाइक चालक को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में। यही नहीं पिटाई के बाद भी पुलिस अफसरों को मुकदमा दर्ज करने एवं कार्रवाई में कई घंटे लग गए। पुलिस पर हमले के करीब तीस घंटे बाद 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। उधर थाने में हुए हमले और एफआइआर में देरी होने पर टालीगंज थाना प्रभारी अनूप घोष को हटा दिया गया। बता दें पिछले रविवार रात नशे में धुत होकर बाइक चलाने के आरोप में चेतला निवासी रंजन हलदर को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। इसकी भनक लगते ही महिलाओं समेत 40-50 लोगों की भीड़ ने थाने पर हमला बोल दिया और पुलिस कर्मियों को जमकर पीटा, जिसमें पांच पुलिस कर्मी घायल हो गए। इसके बाद आरोपित के परिजनों ने पुलिस के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस को घटना में स्वतः संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट दर्ज करने में 11 घंटे लग गए। मामले के तुल पकड़ने पर कोलकाता पुलिस आयुक्त ने थाना प्रभारी अनूप घोष की भूमिका पर नाराजगी जताई थी। साथ ही आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार करने के आदेश दिए। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि मालदा जिले के रतुआ में भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ करने के बाद आग लगाने की कोशिश की। बाद में अन्य थानों से पुलिसकर्मी पहुंच कर स्थिति को नियंत्रित किए, परंतु यहां बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतना साहस बिना राजनीतिक प्रश्रय के हमलावरों में कहां से आ जाएगा? टालीगंज में हुई घटना में तो तृणमूल के ही दो मंत्रियों के बयान से विरोधाभास पैदा हो गया है, परंतु जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह कहती हैं कि पुलिसकर्मी से लेकर अधिकारी बिना रंग देखे कार्रवाई करें तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस पर मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करानी चाहिए। ताकि कोई पुलिस पर हमला न कर सके।

जुड़ाव की राजनीति के आगे बेबस विपक्ष

बद्री नारायण

अपने विरोधी विचार से जुड़कर उसे पूरी तरह आत्मसात करने वाली संघ-भाजपा की रणनीति से विपक्ष की बची-खुची सियासी जमीन भी खिसकती दिख रही है

हिंदुत्व परिवार की राजनीति दिन प्रतिदिन विस्तृत हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस विस्तार की भूमिका रच रहा है और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा इसे अंजाम देती जा रही है। भाजपा की राजनीति के इस विस्तार का मूलमंत्र है समावेशन यानी जुड़ाव की रणनीति। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वह रणनीति है जिसे उसने अपनी संरचना में आज के संदर्भ में एक लय के रूप में विकसित कर लिया है। यह नीति हालांकि संघ की खोज है, परंतु इसके विकास में निरंतर बदलती भाजपा का प्रभाव भी शामिल है। मैं यहां कहना यह चाह रहा हूं कि संघ एवं भाजपा दोनों अपनी रणनीति के विकास में एक-दूसरे को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते दिखते हैं। समावेशन से यहां आशय अपने विरोधी विचारों, प्रतीकों एवं जनाधार को स्वयं में समाहित करने से है। अर्थात अपने विरोधी एवं प्रतिरोधी विचार को अपने दिलोदिमाग में जगह देना, उसके साथ जुड़ जाना एवं अपने से उसे जोड़ लेना ही समावेशन है। भाजपा की यह नीति इतनी कारगर है कि इसने विपक्ष की राजनीतिक जमीन को ही सिकोड़ना शुरू कर दिया है।

दरअसल जनतंत्र की राजनीति में दो तरीकों से जनता की लामबंदी राजनीतिक दल करते रहे हैं। एक तरीका प्रतिरोध का है और दूसरा समावेशन का। विपक्ष प्रायः प्रतिरोध के माध्यम से सत्ता एवं प्रभावी राजनीतिक शक्ति को कमजोर बनाता है। वहीं प्रभावी एवं मुख्यधारा के केंद्र में अवस्थित राजनीतिक शक्ति समावेशन के औजार से स्वयं को मजबूत करती जाती है। इसके लिए अपने विचारों में लचीलेपन का गुण और विरोधियों के विचारों एवं जनाधार को आत्मसात कर लेने की अपार शक्ति का होना जरूरी है। मुख्यधारा की राजनीति प्रायः अपने प्रतिरोधियों को तो पचाती जाती है, अनेक सह उप-राजनीतिक धाराओं को भी स्वयं में समाहित करती जाती है। अपने प्रतिरोधी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सतत संवाद बनाए रखना समावेशन की प्रक्रिया का पहला चरण है।

अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा को अपने दूसरे कार्यकाल को दलितों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों पर केंद्रित करने का सुझाव दिया है। इस सुझाव का तात्पर्य यह है कि सरकार अपनी नीतियों, कार्य योजनाओं एवं परियोजनाओं के माध्यम से दलितों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यक सामाजिक समूहों के मध्य प्रवेश करे। हम यह जानते हैं कि दलित, अल्पसंख्यक एवं नारी आंदोलन भारतीय राजनीतिक जनतंत्र में विपक्ष की राजनीति का आधार रहे हैं। समाजवादी राजनीति, बहुजन राजनीति, वामपंथी राजनीति एवं कांग्रेस की राजनीति इन सामाजिक समूहों के प्रतिरोधी आंदोलनों से ही अपना आधार विकसित करती रही है।

अब संघ एवं भाजपा इन सामाजिक समूहों को स्वयं में समाहित कर या जोड़कर विपक्षी राजनीति को ध्वस्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। इन सामाजिक समूहों को जोड़ने की संघ प्रेरित कार्यनीति का मूलाधार उनमें प्रतिरोधी चेतना जगाकर उन्हें जोड़ने की विपक्षी रणनीति के समानांतर उनमें आकांक्षा जगाकर उन्हें जोड़ने की रणनीति पर आधारित है। इस आकांक्षा का मूल है-महाजनोयेन पन्थाः सुगता। अर्थात जिस रास्ते पर प्रभावी लोग चल रहे हैं, उसी रास्ते पर चलकर प्रभावी होने की आकांक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। मुख्यधारा का प्रतिरोध नहीं, बल्कि मुख्यधारा से जुड़ते जाना, इस कार्यनीति का मूल है। सरकारी योजनाओं को पाने की चाह एवं उनकी तह तक पहुंचने की आकांक्षा अति उपेक्षित रहे दलितों के एक तबके को सत्ता में प्रभावी राजनीति एवं विचार से जोड़ती जा रही है। अगर गहराई से देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समावेशन की सामाजिक संस्कृति रच रहा है एवं भाजपा जनतांत्रिक माध्यम से उपेक्षित एवं अति उपेक्षित समूहों में समाहित होने की आकांक्षा उत्पन्न कर रही है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कई अनुषंगी संस्थाएं जनजातीय समूहों, दलित एवं उपेक्षित सामाजिक समूहों, नारी शक्ति और अल्पसंख्यकों के बीच कार्यरत है। वनवासी कल्याण के क्षेत्र में संघ की प्रभावी गैर सरकारी सेवाभावी संस्थाएं वन क्षेत्रों में सक्रिय हैं। दलित सामाजिक समूहों के बीच संघ द्वारा प्रस्तावित सामाजिक समरसता अभियान चल ही रहे हैं। मुस्लिम सामाजिक एवं धार्मिक समूहों के बीच भी राज्य मुस्लिम संगठन की तर्ज पर अनेक संस्थाएं संचालित हो रही हैं।

संघ ने जिस प्रकार से इन सामाजिक समूहों से जुड़े वैचारिक आदर्श के प्रतीकों को अपने में आत्मसात किया है, वह भी समझना जरूरी है। डॉ. भीमराव आंबेडकर एवं राममनोहर लोहिया, जो उपेक्षित एवं पिछड़ों की राजनीति के वैचारिक स्रोत रहे हैं, उन्हें संघ एवं भाजपा ने अपने साथ जोड़ा है। संघ के तमाम कार्यक्रमों में डॉ. आंबेडकर एक केंद्रीय प्रतीक होकर उभरने लगे हैं। नरेंद्र मोदी राममनोहर लोहिया की बार-बार सराहना करते हैं। संघ के कार्यालय में कई जगह डॉ. आंबेडकर की तस्वीरें लगी मिल जाएंगी। बिरसा मुंडा, ऊदा देवी, सुहेलदेव जैसे दलित एवं जनजातीय प्रतीक पुरुषों को संघ एवं भाजपा ने अपने साथ आत्मसात करने की कोशिश की है। इन प्रतीक पुरुषों के लिए स्मृति स्थल विकसित करना, इनकी स्मृति में पार्क एवं चौराहों का नामकरण करना, इनके नाम पर ट्रेन चलाना, इनकी जयंती आयोजित करना संघ एवं भाजपा की इसी कार्य नीति का हिस्सा हैं। भाजपा ने इन सामाजिक समूहों से राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मंत्री बनाकर, उनके नेताओं को राजनीति में समाहित कर उनकी आकांक्षाओं की गति को अपने पक्ष में करने की सफल कोशिश की है।

भाजपा दिन-प्रतिदिन नए-नए क्षेत्रों में, तमाम वंचित सामाजिक समूहों के बीच अपनी राजनीति का प्रसार कर रही है। छोटी-छोटी जातीय एवं सामाजिक अस्मिताओं को अपने में समाहित कर उन्हें बड़ी-सी महसूस होने वाली अस्मिताओं जैसे-राष्ट्र, धर्म, सत्ता के भागीदार समूहों में जोड़ती जा रही है। अस्मिताओं की छोटी एवं ज्यादा करीब की इकाइयां जैसे जाति एवं उप-राष्ट्रीयता हममें सनसनी तो पैदा करती हैं, पर बड़ी अस्मिताएं बड़े सम्मान का बोध जगाती हैं। विपक्ष की राजनीति के सामने अब बड़ा संकट है कि कैसे इन लघु अस्मितापरक इकाइयों को बड़ी अस्मिता की इकाई में बदले और संघ एवं भाजपा द्वारा रची जा रही नई आकांक्षापरक अस्मिताओं के समावेशन से निर्मित एक वृहत सामाजिक गठजोड़ का मुकाबला करे। आगे भारतीय जनतंत्र की राजनीति और भी रोचक होने जा रही है। देखना है कि विपक्ष आने वाले समय में इसके खिलाफ कैसे राजनीतिक अस्त्र विकसित करता है? जाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों में पीड़ित होने के भाव को कैसे जागृत करता है? साथ ही भारतीय जनतंत्र में जाति की राजनीति को कैसे पुनः परिभाषित करता है?

(लेखक प्रयागराज स्थित गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं)

response@jagran.com

एनआरसी पर अनुचित आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस यानी एनआरसी को प्रकाशित करने की मियाद और नहीं बढ़ाई जाएगी। एनआरसी को दोबारा कराने की अर्जी भी खारिज कर दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 26 जुलाई के फैसले पर मुहर लगाते हुए 12 अगस्त को आदेश दिया कि 31 अगस्त तक दी गई समयसीमा में ही एनआरसी की अंतिम सूची जारी करनी होगी। अब इसमें पखवाड़े भर का समय शेष है। शीर्ष अदालत की अगुआई में हो रही इस कवायद से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पक्ष-विपक्ष भी इसमें एक दूसरे पर हमलावर हुए जा रहे हैं। कोर्ट का 26 जुलाई का निर्णय वास्तव में जनवरी 2018 में प्रकाशित प्रारूप सूची के बाद आया है जिसमें असम एनआरसी के 3.29 करोड़ आवेदकों में से लगभग 40 लाख नाम हटा दिए गए थे। यह मुद्दा न केवल नागरिकता और राष्ट्रवाद की अवधारणा से जुड़ा है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला भी है। इसलिए इस मामले का व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है।

नागरिकता की बहस अठारहवीं शताब्दी में उठी जब पाश्चात्य समाज पुनर्जागरण आंदोलन से प्रभावित था। उसी दौर में उदारवाद भी जन्म ले रहा था। नागरिकता और राष्ट्रवाद की बहस तब और तीव्र हुई जब यूरोपीय देश संविधान को चर्च से ज्यादा महत्व देने लगे। हालांकि उदारवादियों ने इन दिनों उदारवाद के मूल सिद्धांतों को भुलाकर वामपंथ की कई अवधारणाओं को अपना लिया है। इनमें एक विचित्र अवधारणा ओपन बॉर्डर यानी 'खुली सीमा' की भी है जिसे अपनाकर उदारवादी नागरिकता की संकल्पना को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। नागरिकता को लेकर इन हालिया बहसों का वैश्विक संदर्भ भी है जहां यह तमाम देशों के राजनीतिक दलों के बीच बहस का प्रमुख मुद्दा बन जाती है। यह बहस अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के बीच प्रमुख मुद्दों में से एक है। इस साल जून में पहली डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल बहस में तो एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। उसमें सभी उम्मीदवारों ने अवैध प्रवासियों के लिए मुफ्त सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन किया। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव में इस घोषणा का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक भी अवैध प्रवासियों को मिल रहे ऐसे महत्व को लेकर संशय में हैं।

बैजयंत 'जय' पांडा

कुछ छिटपुट गलतियों के कारण एनआरसी जैसी बड़ी कवायद की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर उसे खारिज करना सही नहीं

उदारवाद की मूल विचारधारा में राष्ट्रवाद को प्रमुखता दी गई थी, लेकिन यह अमेरिकी उदाहरण दर्शाता है कि यह विचारधारा अपने मूल विचार से कितना भटक चुकी है। जब उदारवादी असम में एनआरसी की अवहेलना करते हैं तो वे व्यावहारिक रूप से 'खुली सीमा' की वकालत करते हैं। वे भूल जाते हैं कि पड़ोसी बांग्लादेश से अवैध रूप से आने वाले लोगों के चलते असम की स्थानीय आबादी का स्वरूप बिगड़ रहा है। राज्य के मूल निवासियों को इससे काफी परेशानी हो रही है।

मोदी सरकार के विरोध में तर्क दिया जाता है कि यह विद्वेष फैलाने वाली सरकार है जिसके लिए वे 2016 में बने प्राथमिकता कानून का उदाहरण देते हैं। इस कानून के तहत पड़ोसी देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों (हिंदुओं, ईसाइयों और पारसियों आदि) को प्राथमिकता दी जाती है। आलोचक भूल जाते हैं कि बांग्लादेश से प्रवासी मजदूर बेहतर वेतन और संसाधनों के लिए असम आते हैं, न कि अपने देश में हो रहे उत्पीड़न से बचने के लिए। अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक देश में शरणार्थियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, न कि अवैध प्रवासियों को जो केवल बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में अवैध रूप से किसी राज्य में घुस जाते हैं।

विपक्षी दल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनआरसी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वे भूल रहे हैं कि इस कवायद की निगरानी सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है। वर्तमान प्रक्रिया की जड़ें भी असम समझौते में हैं, जो दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विरासत है। इससे कांग्रेस के लिए एनआरसी प्रक्रिया का विरोध करना और भी मुश्किल हो जाता है। एनआरसी के आलोचक यह क्यों नहीं देख पा रहे हैं हैं कि तीन दशकों की अकर्मण्यता के बाद आखिर इस मामले में एक सही पहल हुई है। असम समझौते के बाद राज्य दशकों तक गतिरोध की स्थिति में फंसा हुआ था और उसमें बनी सहमति के आधार पर फैसलों को लागू करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हो रहे थे।

इसमें संदेह नहीं कि एनआरसी की गिनती में भी कुछ गलतियां हुई हैं। हालांकि इतनी व्यापक कवायद में कुछ खामियां स्वाभाविक ही हैं। वर्तनी की गलती के कारण एक महिला की गलत पहचान के एक मामले को स्वीकार कर उसे राहत दी जा चुकी है। एक पूर्व भारतीय सैनिक को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में जमानत दे दी गई। हालांकि उनकी नागरिकता के मामले में अभी सुनवाई शेष है। इन छिटपुट मामलों को उछालकर आलोचक पूरी प्रक्रिया को ही संदिग्ध बताने के अभियान में जुटे हैं। वे इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि नागरिकता के महत्वपूर्ण सवाल को निर्धारित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने वाला राज्य ही अपने नागरिकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से लक्षित कर उनकी पूर्ति कर सकता है। निःसंदेह इन गलतियों की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक भी नागरिक को गलत तरीके से अयोग्य घोषित करना एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे बचने के लिए तंत्र को और प्रभावी बनाना होगा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसे संभव बनाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कदम पीछे नहीं खींचे जा सकते। सरकारी कार्यप्रणाली और दस्तावेजीकरण को सुधारने के लिए अन्य उपायों पर भी हमें भविष्य में बहस शुरू करनी होगी।

आखिर हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं? विपक्ष बुनियादी रूप से जिस काल्पनिक संकट का हौवा खड़ा कर रहा है उसमें तथ्यों, आंकड़ों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को नकारा जा रहा है। अब हमें एक नए भारत की कल्पना करनी होगी जहां प्रत्येक भारतीय नागरिक के अधिकार सुरक्षित होंगे और सरकारी कार्यप्रणाली भी सक्षम होगी।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संवेदना

संवेदना हृदय की गहराइयों से उठती हुई एक पुकार है। मानव संवेदनशील होकर ही एक सुसभ्य एवं सुव्यवस्थित समाज की परिकल्पना कर सकता है। संवेदना के अभाव में मनुष्य के जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं है। जब इंसान सिर्फ अपने हित या स्वार्थ तक ही सीमित रहेगा और समाज के कमजोर, पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करेगा तो यह धरती निराशा के घर में तब्दील हो जाएगी। प्रत्येक मनुष्य को एक-दूसरे के साथ संवेदना रखनी चाहिए। संवेदना इंसान के अंतःकरण की गहन और मौन अभिव्यक्ति है। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती है। जिस व्यक्ति को दूसरों के दुखों को देखकर दुख महसूस नहीं होता या दुखी व्यक्ति के लिए उनके मन में संवेदना उत्पन्न नहीं होती तो यह मान लेना चाहिए कि वह संवेदनहीन मनुष्य है। मानव वही है, जिसमें मानवता है और मानवता वह है जिसमें संवेदना है।

संवेदना एक ऐसा गुण है, जिससे मनुष्य किसी का भी दिल जीतकर उसे अपना बना सकता है। संवेदना से पराए भी अपने हो जाते हैं और संवेदना न हो तो अपनों को पराया बनने में भी ज्यादा देर नहीं लगती। मनोविज्ञान कहता है कि संवेदना व्यक्त करने से दोनों पक्षों को लाभ होता है। संवेदना देने और लेने वाले दोनों एक-दूसरे को मन की शक्ति और भावनाओं की विशालता प्रदान करते हैं। जहां संवेदना लेने वाले को अपने दुखों से लड़ने के लिए मानसिक शक्ति और भावनात्मक बल मिलता है, वहीं संवेदना व्यक्त करने वाले को इसका दोहरा लाभ प्राप्त होता है। संवेदना व्यक्त करने से मनुष्य में उदारता, दया, भावुकता, ईमानदारी जैसे कई सकारात्मक गुण आ जाते हैं।

इन गुणों के विस्तार से न केवल मनुष्य का जीवन जीने का नजरिया बदल जाता है, बल्कि उसकी आयु भी बढ़ जाती है। वास्तव में संवेदना से मनुष्य का मन निर्मल और पवित्र होता है और बुद्धि-प्रखरता से उसका व्यक्तित्व निखर उठता है। यदि मनुष्य एक-दूसरे के प्रति संवेदना व्यक्त करे तो इस संसार में दुख मिट जाएगा।

शंभूनाथ पांडेय

सेहत से खिलवाड़

अमृत कुमार

देश में मिलावटी एवं नकली दूध का खूब बोलबाला है। इस मिलावट के चलते बीमारियां भी फैल रही हैं

दुनिया में दूध उत्पादन में अव्वल होने के साथ हम दूध की सबसे ज्यादा खपत में भी आगे हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को औसतन 290 ग्राम दूध रोजाना मिलता है। इस हिसाब से देश में कुल खपत प्रतिदिन 45 करोड़ लीटर दूध की हो रही है, जबकि शुद्ध दूध का उत्पादन करीब 15 करोड़ लीटर ही है। जाहिर है दूध की कमी की पूर्ति नकली दूध बनाकर और पानी मिलाकर की जा रही है।

देश में दूध का 70 फीसद कारोबार असंगठित ढांचा संभाल रहा है। इस कारोबार में ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं, लेकिन पारंपरिक ज्ञान से न केवल वे बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन में सफल हैं, बल्कि इसके सह-उत्पाद दही, घी, मक्खन, पनीर, मावा आदि बनाने के भी जानकार हैं। देश में दूध उत्पादन में 96 हजार सहकारी संस्थाएं जुड़ी हैं। 14 राज्यों की अपनी दूध सहकारी संस्थाएं हैं। इससे सात करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आजीविका जुड़ी है। रोजाना दो लाख से भी अधिक गांवों से दूध एकत्रित करके डेयरियों में पहुंचाया जाता है। इतना व्यापक और महत्वपूर्ण व्यवसाय होने के बावजूद इसकी गुणवत्ता की निगरानी के लिए कोई नियामक तंत्र देश में नहीं है। इसलिए दूध की मिलावट में इंसानी लालच बढ़ी समस्या बना हुआ है।

इस पर नियंत्रण की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए भारत में ही निर्मित एक नए यंत्र की जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया है कि मिलावट की मामूली मात्रा को भी यह यंत्र पकड़ने में सक्षम है। हालांकि केवल दूध के नमूने की जांच भर से शुद्ध दूध की गारंटी संभव नहीं है। वह इसलिए, क्योंकि मवेशियों को जो चारा खिलाया जाता है, उसमें भी दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए रासायनिक तत्व मिलाए जाते हैं। यही नहीं मवेशी दूध ज्यादा दें इसके लिए उन्हें जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनसे दूध का उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन अशुद्धता भी बढ़ती है। दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए जो डिब्बाबंद चारा बनाया जाता है, वह नाइट्रोजन को बढ़ाता है। जाहिर है दूध की शुद्धता के लिए इन उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाना जरूरी है, क्योंकि दूध के नमूने की जांच में वह दूध भी अशुद्ध पाया गया है, जिसमें ऊपर से कोई मिलावट नहीं की जाती है। यह अशुद्धता चारे में मिलाए गए रसायनों के द्वारा सामने आई है।

यह सही है कि यदि दूध में मिलावट हो रही है तो इसे अच्छी सेहत के लिए दूर करना सरकार का दायित्व है, लेकिन महज तकनीक से मिलावट की समस्या का निदान हो जाएगा, यह मात्र भ्रम है। यदि इंसानी लालच दूध में मिलावट का कारण है तो तकनीक से दूध की जांच भी वही सरकारी नौकरशाही करेगी, जो भ्रष्ट है। ऐसे में तकनीक चाहे जितनी सक्षम क्यों न हो, उसकी अपनी सीमाएं हैं। मनुष्य के लालच के आगे तकनीकी उपकरणों के पराजित होने के अनेक मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए इस विकराल समस्या के निराकरण के लिए इसके सहायक पहलुओं के भी शुद्धिकरण की जरूरत है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

समय की मांग है गांधीवाद

'गांधीवाद की ओर लौटने की दरकार' शीर्षक से लिखे अपने लेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने विविध सदर्भों में गांधीवाद के महत्व तथा उतरोत्तर गांधीवादी मूल्यों के ह्रास होते जाने पर विश्लेषण के साथ-साथ चिंता भी व्यक्त की है। वर्ष 2014 और फिर 2019 में राजनीतिक रूप से हुए बड़े परिवर्तन ने देश की आगामी योजनाओं की दिशा तय कर दी थी। अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हुईं, जिसका परिणाम बदलाव के रूप में सामने आया और एक नया तथा सशक्त भारत आज शिखर की ओर बढ़ रहा है। अनुच्छेद 370 का हटाया जाना उसी सफलता में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। किंतु स्वच्छ भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, ग्राम विकास, जल संरक्षण, सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न भारत तथा राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण भारत आदि अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गांधी जी ने एक समर्थ तथा सशक्त भारत का स्वप्न देखा था, जिसकी चर्चा वह अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक 'मेरे सपनों का भारत' में करते हैं, लेकिन विडंबना यह रही कि गांधीवाद पर और गांधी जी के नाम पर लंबे समय तक राजनीतिक रोटियां तो खूब सेंकी गईं, किंतु उनके सपनों का भारत पुस्तक में ही बंद रहा। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सदाचार तथा अपरिग्रह आदि मूल्य हाशिये पर ही पड़े रहे। निश्चित रूप से आज निहित स्वार्थों को छोड़कर गांधीवाद की ओर लौटने से ही अंतिम जन की आशा आकांक्षा पूरी हो सकेगी।

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली

पाक ने सत्य स्वीकारा

सत्य थोड़े समय के लिए दब सकता है, लेकिन एक न दिन बाहर आ ही ज्यादा है। पाकिस्तान के द्वारा बालाकोट में एयर स्ट्राइक की बात सिरे से खारिज करना और फिर अपने स्वतंत्रता दिवस पर कबूल कर लेना कुछ इसी तरह के संकेत देते हैं। पुलवामा की आतंकी घटना के कुछ ही दिन बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले करके पाकिस्तान के यहां पल रहे आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया था, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उस समय पाक के पीएम ने इस कार्रवाई को झूठा बताया था जिसमें हमारे देश के भी कुछ विपक्षी नेता और पश्चिमी मीडिया उनका साथ दे रहा था। इमरान ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस मनाने के दौरान इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत ने बालकोट में जबरदस्त हमला किया था। अब जब पाक के प्रधानमंत्री ने बालकोट के सच को स्वीकार कर लिया है तो अब उम्मीद बढ़ गई है कि भारत में सुबूत मांगने वाले लोगों को भी विश्वास हो जाना चाहिए।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

स्वामी दयानंद का योगदान

दैनिक जागरण के 15 अगस्त के अंक में गोपालकृष्ण गांधी का लेख, तिरंगा और आजादी का उत्सव, पढ़ा। इसमें लेखक ने आजादी में योगदान के लिए पांच गणमान्य व्यक्तियों का स्मरण किया। मगर 1857 के पश्चात आजादी के लिए अलख जगाने वाले क्रांतिकारी संत स्वामी दयानंद का नाम स्मरण नहीं किया। स्वामी जी का कथन था कि कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सबसे उत्तम होता है। विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायी नहीं है। स्वामी जी के विचार चिंतन का परिणाम ही था कि देश को लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी मिले। ये सब आर्य समाज से प्रभावित थे।

डॉ. विवेक आर्य, शिशु रोग विशेषज्ञ, दिल्ली

सामान्य श्रेणी के छात्र

केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) ने एससी और एसटी छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क को 24 गुना बढ़ा दिया है। एससी और एसटी श्रेणी के छात्रों को 1200 रु और सामान्य श्रेणी के छात्रों को 1500 रु परीक्षा शुल्क के रूप में देने होंगे। दिल्ली सरकार भी केवल विशेष वर्ग के छात्रों के लिए चिंतित नजर आई। दिल्ली सरकार ने एससी और एसटी श्रेणी के छात्रों का बढ़ाया गया परीक्षा शुल्क अपनी जेब से भरने का एलान किया, लेकिन सामान्य श्रेणी के छात्रों का शिक्षा अधिकार क्यों नजर नहीं आता? क्या दिल्ली सरकार के लिए सभी छात्र समान नहीं हैं?

निशांत रावत, डॉ. भीमराव आंबेडकर कॉलेज

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

4,000 अरब घनमीटर पानी प्राप्त होता है बरसात के रूप में समूचे देश को जिसमें से करीब एक-चौथाई पानी ही कई तरीकों से उपयोगी हो पाता है, शेष हिस्सा जल प्रबंधन के अभाव में बेकार चला जाता है।

आजकल

वंदे मातरम के भाव से विकास का संकल्प

स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन की शुभकामनाओं से प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय सामाजिक पर्व का यह संयोग बड़ा संदेश देने वाला है। राष्ट्र समाज से ही बनता है। रक्षाबंधन सामाजिक एकता, सौहार्द व सुरक्षा का भाव जागृत करता है। यही विचार राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। महज दस सप्ताह के समय में केंद्र सरकार ने कई नए आयाम स्थापित किए हैं। जम्मू कश्मीर पर बड़ा फैसला लिया। मुस्लिम महिलाओं को कुप्रथा से आजादी दिलाई। यह सब प्रधानमंत्री के दृढ़ निश्चय से ही मुमकिन हुआ

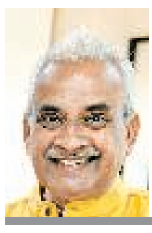

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री
स्वतंत्र टिप्पणीकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से न्यू इंडिया का संकल्प दोहराया जिसमें समस्याओं को हटाकर विकास का मार्ग तैयार करने पर जोर दिया। शांति और सुरक्षा विकास के लिए आवश्यक है। इस संबंध में भारत को अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। आतंकवाद मानवता के लिए चुनौती है। आतंकवाद के निर्यातक मुल्क से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि अनेक देश पीड़ित हैं। भारत इनके साथ है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन यह जरूर दोहराया कि आतंकवाद का निर्यातक कौन है, यह जगजाहिर है। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की आजादी के सौ वर्ष पूरे होने की भी बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने दो अक्टूबर को प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान शुरू करने का आह्वान किया। दुकानदार भाइयों से कहा कि वह अपनी दुकानों पर यह लिखें कि हमसे पॉलीथिन की अपेक्षा न करें, और जनसामान्य से अनुरोध किया कि आपस में भेंट स्वरूप उन्हें कपड़े के थैले देने चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण के साथ ही उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की। सौ पर्यटन स्थलों को विश्व प्रसिद्ध बनाया जा सकता है। वंदे मातरम बोलने से प्रेरणा मिलती है। धरती मां को तबाह करने, बीमार बनाने का हक किसी को नहीं। प्रधानमंत्री ने किसानों से खेती में केमिकल का प्रयोग कम करने का आह्वान किया।

आजादी के छह दशकों के बाद ही सही नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गरीबों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। आरोग्य सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए गए। मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता लाई गई, और सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। बच्चों की सुरक्षा हेतु कठोर कानून बनाए गए। पिछले पांच वर्षों में गरीब कल्याण योजनाओं पर बल दिया गया। सरकार का यह कार्यकाल लोगों के सपने साकार करेगा। अगले पांच वर्षों में नए भारत का निर्माण हो सकेगा।

देखा जाए तो वर्ष 2014 के पहले लोगों में एक प्रकार की निराशा की भावना थी। पांच वर्ष तक प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने समर्पण भाव से कार्य किया। निराशा को आशा में बदल दिया। सबको विश्वास हुआ कि देश बदल सकता है। सबका साथ सबका विकास लेकर वे चले। इसमें सबका विश्वास जुड़ गया। अब स्वावलंबन के बल पर आगे की यात्रा चल रही है। इसी से सफलता हासिल होगी। समस्याओं का समाधान टुकड़ों में नहीं समग्रता से होगा।

मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक से भयभीत रहती थीं। उनके इस भय को दूर किया गया। तमाम मुस्लिम मुल्क इसे पहले हटा चुके थे, लेकिन हमारे देश में इसे हटाने में संकोच था। इस सरकार ने इसे कर दिखाया। यह सरकार समस्याओं को न पालती है, न उसे छोड़ती है।

जनता ने जो काम सरकार को सौंपा है, सरकार उसे पूरा कर रही है। पिछली सरकारों ने प्रयास किए, लेकिन उसके परिणाम नहीं मिले। जम्मू कश्मीर के साथ न्याय नहीं हुआ। अब जाकर वहां के लोगों को न्याय मिला है। दलितों और पिछड़ों को लाभ मिलेगा। अलगाववाद, आतंकवाद और परिवारवाद दूर होगा।

पूरा देश जम्मू कश्मीर पर लिए गए सरकार के निर्णय के साथ है। लेकिन कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। वह इसकी पैरवी कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने बहुमत के बाद भी इस अनुच्छेद को स्थायी क्यों नहीं किया। जबकि इस अनुच्छेद के हटने से 'एक देश एक संविधान' संभव हुआ। इसके पहले 'वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन ग्रिड' को लागू किया गया। अब 'एक देश एक चुनाव' पर चर्चा चल रही है। ये प्रयास 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का निर्माण करेगा।

पिछले पांच वर्षों में गरीबी कम करने का प्रयास तेज गति से हुआ है। गरीब बंधु गरीबी से लड़ने की क्षमता रखते हैं। सरकार उनके लिए माहौल बना रही है। इसी क्रम में बैंकों में उनके जनधन खाते खोले गए, शौचालय बनाए गए, आवास बनाए जा रहे हैं। उनके घरों में पेयजल पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। जल जीवन मिशन योजना शुरू होगी। साढ़े तीन अरब रुपये से यह योजना संचालित होगी। पानी की बर्बादी रोकी जाएगी। पानी का संरक्षण किया जाएगा। इस दिशा में जो कार्य सात दशकों में नहीं हुआ, उससे चार गुना ज्यादा काम पांच वर्षों में होगा। प्राचीन संतों ने भी जल संरक्षण का संदेश दिया। एक संत ने तो सौ वर्ष पहले लिखा था कि पानी दुकानों में मिलेगा। यह स्थिति आ गई है। अब हमको जल प्रबंधन करना है।

जनसंख्या विस्फोट संकट बढ़ाने वाला है। देश का जागरूक वर्ग इस बात को समझता है। यह वर्ग शिशु जन्म से पहले उसको मिलने वाले अधिकारों व सुविधाओं का आकलन करता है। ऐसे लोग सम्मान के हकदार हैं। ये देश के हित के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। पिछले कार्यकाल में औसतन प्रतिदिन एक अनुपयोगी कानून हटाए गए। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभूतपूर्व सफलता मिली। आमजन के जीवन को भी सरकार ने आसान बनाने का प्रयास किया है। भारत को विकसित बनाया जाएगा। दो लाख करोड़ रुपये तकनीकी ढांचागत निर्माण में खर्च किया जाएगा। पहले कागज पर निर्णय भी हो जाते थे। अब नागरिकों की सोच बदली है। अब बढ़िया रेलवे स्टेशन बनने के बाद नागरिक पूछते हैं कि हवाई अड्डा कब बनेगा, पक्की सड़क बनती है, तो लोग पूछते हैं कि कितने लेन की बनेगी। अब वह बिजली के खंभे मात्र को देखकर संतुष्ट नहीं होता। बिजली की उपलब्धता भी होनी चाहिए। यह सोच सरकार को प्रेरणा देते हैं। पहले सरकारें बताती थीं कि किस क्षेत्र को क्या दिया, अब देश के लिए क्या हुआ इस पर कार्य हो रहा है। किसानों की आय दोगुनी होगी, सबके पास मकान होगा, प्रत्येक घर में बिजली, शौचालय होगा। प्रत्येक जिले निर्यात का हब बनेगा, किसान भी निर्यातक बनेगा, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, पर्यटन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा।

दुनिया भारत को नए ढंग से देखने को तैयार है। वैज्ञानिकों को सुविधा मिलेगी, सेना को पर्याप्त संसाधन मिलेगा, इन सब प्रयासों से भारत विकसित बनेगा। महंगाई को नियंत्रित रखकर विकास किया जाएगा। विश्व अब भारत के साथ व्यापार व निवेश बढ़ाने को उत्सुक है। हमको इसका लाभ उठाना है। भारत के उद्योगपति भी निवेश को तैयार हैं। नकारात्मक मान्यताएं समाप्त होंगी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को देश के सर्वांगीण विकास का अवसर बनाया जाएगा।

लाल किला से राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद बच्चों से मिलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फोटो सौजन्य : पीआइबी

पानी और पर्यावरण बचाने की कवायद

सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाइएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

मानव सभ्यता के विकास को जिन कारकों ने प्रभावित किया उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिद्दत से छूने का प्रयास किया। स्वतंत्रता दिवस क्या चिन्हित करना चाहता है इसकी भी झलक भाषण में दिखी। सामान्यतः लाल किले से ऐसे अवसरों पर प्रधानमंत्री अधिकतर अपनी सरकार के कार्यों का बखान करते रहे हैं। मगर इसी लाल किले से स्वच्छता, शौचालय, पानी और पर्यावरण समेत जनसंख्या विस्फोट व प्लास्टिक पर पाबंदी तथा बुनियादी विकास के प्रसंगों का वर्णन शायद ही सुनने को मिला हो। मोदी ने तमाम संवेदनशील मसलों को छूने का प्रयास किया। किसानों और व्यापारियों को मिलने वाली मदद की चर्चा करना और यह कहना कि अब सपनों को पूरा करने का समय आ गया है, वाकई ऐसा लगा कि मानो एक नए भारत की सोच और समझ को पुख्ता करने का प्रयास किया गया है।

पिछले पांच सालों में 1,450 गैर जरूरी कानून सरकार ने खत्म किए हैं। दूसरी पारी में ही अब तक 60 कानून खत्म किए जा चुके हैं। वर्ष 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ा चुकी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने बड़ा रूप देने का मन बना लिया है।

इसके अलावा जीवन के उन संवेदनशील पहलुओं को भी मोदी चेताना नहीं भूले जिस पर यह देश-दुनिया टिकी रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पानी की बचत, पर्यावरण का संरक्षण और प्लास्टिक को नकारने का अब समय आ गया है। जनसंख्या विस्फोट का उनके भाषण में होना यह संकेत देता है कि सरकार इस समस्या के प्रति भी गंभीरता से सोच रही है।

श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य को लेकर मोदी पड़ोसी पाकिस्तान को घसीटना नहीं भूले। हालांकि पाकिस्तान को इस बार वैसा नहीं ललकारा जैसा कि मोदी की प्रकृति में है। विरोधियों को भी बहुत ज्यादा आड़े हाथ नहीं लिया। शायद एक मजबूत सरकार के तौर पर मोदी ये समझ रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए व्यावधानों को पहचानना है, उन्हें दूर करना है, न कि बेफजूल की राजनीति में वक्त जाया करना है।

संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि विश्व के देशों ने पानी बचाने के उपायों पर जल्द काम शुरू नहीं किया तो आने वाले डेढ़ दशकों में पूरी दुनिया को 40 फीसद पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारत में दिल्ली एनसीआर से प्रति वर्ष भूमिगत जल चार फीट नीचे जा रहा है। खबर यह भी है कि चेन्नई में भूमिगत जल का खजाना खाली हो गया है। देखा जाए तो पानी और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक हैं, और जब पर्यावरण बचेगा तभी जल भी बचेगा। रिपोर्ट यह भी है कि जो ग्लेशियर नदियों को पानी देते हैं वे 2030 तक काफी पैमाने पर सिकुड़ जाएंगे। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल आग से स्वाहा हो जाते हैं। नीति आयोग भी कहता है कि 75 फीसद घरों में पीने के पानी का संकट है।

वर्तमान में जिस जीडीपी को सरकार दहाई के आंकड़े तक पहुंचाना चाह रही है, गिरते भूजल स्तर के कारण वर्ष 2050 तक इसमें छह फीसद तक का नुकसान हो सकता है। तब तक आबादी और भी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या पर चिंता जाहिर करके यह संकेत दे दिया है कि यदि आने वाली पीढ़ियों को अनेक संकटों से बचाना है तो इसके प्रति जागरूक होना ही होगा। पानी और पर्यावरण के साथ प्लास्टिक भी बुनियादी समस्या बन चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहता है कि दिल्ली में रोजाना 690 टन, चेन्नई और कोलकाता में 429 टन प्लास्टिक कचरा फेका जाता है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों का दुश्मन है। प्रधानमंत्री ने इस पर भी चिंता जाहिर करते हुए प्लास्टिक मुक्त भारत की अवधारणा पेश कर दी है और कपड़े के थैले की नीति को आगे बढ़ा दिया है। लोगों को सचेत किया और दुकानदारों को इस पर एक्शन लेने का सुझाव भी दिया है। साथ ही इससे बड़े पैमाने पर लघु उपक्रमों के शुरू होने से रोजगार की चर्चा भी की है।

खरी-खरी

दिवस मनाने को कम पड़ते दिन

विकेश कुमार बडोला

देख कर हैरान हूं कि किसी न किसी दिन कोई न कोई अंतरराष्ट्रीय दिवस पड़ ही जा रहा है। अलग-अलग विषयों पर दिवस आयोजन की यही गति रही तो वर्ष के 365 दिन कम पड़ जाएंगे। सोचता हूं इसके बाद क्या वैश्विक और सार्वभौमिक समस्याओं के विषय खत्म हो जाएंगे। विचारणीय यह भी है कि देश-दुनिया की वास्तविक समस्याओं पर तो अभी तक दिवस आयोजित ही नहीं हो रहे। जैसे भारत में जो राजकीय घपले-घोटाले हुए उनसे संबंधित एक घोटाला दिवस तो बनता ही है। जन-जीवन में भ्रष्टाचार जिस गति से फैल रहा है, क्या यह भ्रष्टाचार की उपलब्धि नहीं? भ्रष्टाचार को देश-विदेश में लोगों ने जिस सहजता और सहृदयता से स्वीकार किया है, क्या ऐसे में विश्व कल्याण के लिए भ्रष्टाचार का योगदान किसी भी दृष्टि से कम आंका जा सकता है? कदापि नहीं। तो फिर एक दिन अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस भी अवश्य होना चाहिए।

इस दुनिया में जब से दिवस मनाने की परिपाटी शुरू हुई, तब ही से घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती, बलात्कार, विश्वासघात आदि खूबियां उन खूबियों के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ीं व सार्वजनिक जीवन में स्वीकृत हुईं, जिनके लिए साल भर तक दिवस मनाते-मनाते अब दिवस ही कम पड़नेवाले हैं।

लोगों का तो यहां तक सुझाव है कि दिन के पहले हाफ में यानी लंच से पूर्व विषयवस्तु की समस्या अर्थात घोटाला दिवस मनाया जाए और लंच के बाद समस्या का समाधान अर्थात नोटबंदी दिवस। पहले हाफ में मदिरा प्रेमियों के लिए मदिरा दिवस तो दूसरे हाफ में मदिरा से बर्बाद लोगों के लिए मदिराबंदी दिवस। ऐसे प्रबंधन से दिवसों का समायोजन किया जा सकता है। इस तरह वैश्विक समस्याओं पर एक वर्ष में 365 गुणे दो यानी 730 अर्ध-दिवस मनाने शुरू किए जाएं। इसके बाद भी जब दिवस आयोजन हेतु समस्याएं 730 से अधिक हो जाएं तो दिन को तीन हिस्से में बांट कर, एक दिन में तीन दिवस मनाए जाएं। फिर एक दिन में चार दिवस भी मनाए जा सकते हैं।

एक व्यक्ति ने पूछा कि एक दिन के चार हिस्से कर चार दिवस मनाने के बाद भी यदि अनेक विषयगत समस्याओं को दिवस आबंटित न हो पाएं तो फिर क्या? उसकी बात पूरी होने से पहले मैं झुंझला कर बोला, महाराज! इतनी समस्याएं होंगी तो दिवस मनाने के लिए न तो दिन बचेंगे, न जन बचेंगे और न ही यह जग बचेगा।

ट्वीट-ट्वीट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने देश की सबसे बड़ी चिंता 'जनसंख्या विस्फोट' को लालकिले की प्राचीर से आवाज दी। यह भरोसा भी दिया कि सरकार सामाजिक जागरूकता के जरिये इस दिशा में प्रयास भी करेगी।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

प्रधानमंत्री चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से लेकर प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को बंद करने जैसे तमाम मुद्दों पर बोले। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान शायद हैरान होंगे कि-भाई मेरे मुल्क का तो जिक्र कर देते, आखिर अपने स्वतंत्रता दिवस पर भाषण में पूरे आधे घंटे मैं आपके देश के बारे में ही बोलता रहा।
स्मिता प्रकाश@smitaprakash

कारोबारियों और उनके द्वारा सृजित की जाने वाली संपदा पर मोदी जी के विचार सराहनीय हैं। प्रगतिशील नीति निर्माण, कुशल नेतृत्व और प्रतिबद्ध कर्मियों के चलते जो उद्यम फलता-फूलता है, उसका जश्न मनाया ही जाना चाहिए। प्रगति के लिए वे अनिवार्य हैं।
अनिल अग्रवाल@AnilAgarwal_Ved

अभिमन्यु शर्मा
संपादक, जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर डायरी

निवेश से होने वाले फायदे गिन रहे कश्मीरी

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और इसका पुनर्गठन कर दो केंद्र शासित प्रदेश (लद्दाख और जम्मू-कश्मीर) बनाने के प्रस्ताव पारित हुए अब एक सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। अब हालात धीरे-धीरे पूरे राज्य में सामान्य होते जा रहे हैं। जम्मू संभाग के पांच जिलों में जहां प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए गए हैं और शेष पांच जिलों में भी बाजार खुले हुए हैं, वहीं कश्मीर में भी समय-समय पर कुछ क्षेत्रों में ढील दी गई है। दो दिन तक ईद के त्यौहार का शांतिपूर्वक और उल्लास के साथ संपन्न होना यह दर्शा रहा है कि कश्मीर अब बदल रहा है।

तीन दशकों में यह पहली बार हुआ है कि ईद पर कश्मीर में कहीं पर भी भारत विरोधी नारे नहीं लगे और न ही कहीं पर हिंसा हुई। लोग बड़ी संख्या में मस्जिदों में नमाज के लिए पहुंचे। दक्षिण कश्मीर के आतंकवाद ग्रस्त शोपियां, पुलवामा में भी ईद पर शांति रही।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले स्वतंत्रता दिवस को भी यादगार तरीके से मनाया गया है। लोगों को यह आभास हो रहा है कि संपूर्ण विलय को पहली बार पूरी तरह से अंजाम दिया गया है। इससे उनमें जोश है। सात दशकों से कश्मीर के चंद हुक्मरानों के कारण उन्हें जो भुगतना पड़ा है, उसका गुस्सा कहीं कश्मीर के क्षेत्रीय दलों के नेताओं पर न निकले और वे जम्मू-कश्मीर की शांति में खलल डालने के लिए ओछी राजनीति न करें, उन्हें राज्य प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर उपजेल बनाकर रखा हुआ है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस के नेता अब एक-दूसरे पर खीज निकालने में जुट गए हैं। उन्हें यह अहसास हो गया है कि अब जम्मू-कश्मीर के लोगों को वे गुमराह नहीं कर सकते।

राज्य प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई अलगाववादियों और पत्थरबाजों को राज्य की जेलों से पंजाब और उत्तर प्रदेश की जेलों में भेज दिया है। वहीं राज्य प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जम्मू-कश्मीर के किसी भी भाग में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। अस्पतालों में जहां पर्याप्त जीवन रक्षक दवाइयां मुहैया करवाई हैं, वहीं बाहरी राज्यों में पढ़ रहे कश्मीर के युवाओं को अपने घरों से संपर्क करने में कोई परेशानी हो, इसके लिए पूरे कश्मीर संभाग में 300 टेलीफोन बूथ स्थापित किए गए हैं। कई वर्षों बाद कश्मीर में इतने दिनों से कहीं पर कोई भी गोली चलने की आवाज नहीं आई है। धीरे-धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन लोगों का विश्वास जीतने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक सप्ताह से कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं और कई संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं। सभी जिलों के जिला उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। पूरा जम्मू-कश्मीर बदलता हुआ नजर आ रहा है।

यह पहली बार है कि लोग सड़कों पर आतंकवाद पर नहीं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से होने वाले विकास पर चर्चा कर रहे हैं। घाटी तक में अलगाववादियों का जिक्र नहीं हो रहा। लोग रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के अलावा जम्मू-कश्मीर में होने वाले निवेश से होने वाले फायदे गिन रहे हैं। उन्हें यह अहसास हो रहा है कि देश के अन्य भागों के साथ विकास के पथ पर चलने में शायद देर हो गई, लेकिन अब उनमें उत्साह है। जम्मू-कश्मीर के देश भक्त लोगों को लगता था कि देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे उनके मनोबल पर भी असर पड़ता था। मगर अब देश के खिलाफ आग उगलने वालों के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई के बाद हर कोई जोश में है।

उत्साह में लद्दाख : केंद्र शासित राज्य बने लद्दाख में लोगों में उत्साह देखने वाला है। दो कुछ दिनों पूर्व जब स्थानीय सांसद दिल्ली से लद्दाख पहुंचे तो सड़कों पर लहरा रहे तिरंगे इस बात के गवाह थे कि एक नया इतिहास लिखा गया है। कारगिल के लोगों ने हालांकि कुछ दिन विरोध जरूर जताया, लेकिन राज्य सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए वहां के लोगों की मांगों को भी सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि इसके बारे में केंद्र सरकार को अवगत करवाया गया है। तत्पश्चात कारगिल में भी जनजीवन सामान्य हो गया और लोगों ने ईद शांति के साथ मनाई। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। लद्दाख क्षेत्र के लोगों की केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग वर्षों पुरानी थी। उन्हें लगता था कि कश्मीर केंद्रित दल उनके क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं। अब स्थानीय लोग एक नया इतिहास लिखने के लिए पूरी तरह उत्साहित और तैयार नजर आ रहे हैं।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला सही है?

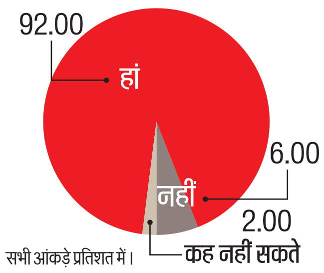

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

मुद्दा

मीठे पानी का विकल्प नहीं समुद्री जल

देश के अनेक हिस्सों में पर्याप्त बारिश होने के बावजूद जल संरक्षण के अभाव में पेय जल कम होता जा रहा है जिसके विकल्पों की तलाश के बजाय प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल को ही बचाना आज समय की मांग है

चंदन कुमार चौधरी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

नीति आयोग ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि वर्ष 2020 तक दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सहित देश के 21 शहरों में भूजल खत्म हो जाएगा और पानी के कारण करीब 10 करोड़ लोग दिक्कत का सामना करेंगे। साथ ही वर्ष 2030 तक भारत के 40 प्रतिशत आबादी को पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। देश में जारी भारी जल संकट के बीच नीति आयोग ने देश की करीब 7,800 किमी लंबी तटीय रेखा के पास तैरते हुए या तट पर बड़े डिसैलिनेशन संयंत्र लगाने का सुझाव दिया है। सरकार चाहती है कि जिन इलाकों में भूजल स्तर काफी कम हो गया है वहां डिसैलिनेशन से पानी मुहैया कराया जाए। इसके लिए नीति आयोग जल्द ही उन तकनीकों की जानकारी पेश करेगा जिसका इस्तेमाल विभिन्न राज्य डिसैलिनेशन संयंत्र लगाने के लिए कर सकते हैं। डिसैलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुद्री जल के खारेपन को दूर कर उसे पीने योग्य बनाया जाता है। समुद्री पानी से नमक दूर करने की प्रक्रिया को डिसैलिनेशन अथवा विलवणीकरण कहा जाता है। इसके लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल वाले वाटरवे (पानी के पाइपलाइन) तैयार करने होंगे।

हमारे देश का बहुत बड़ा भूभाग समुद्र से लगा हुआ है और डिसैलिनेशन की प्रक्रिया अपना कर सरकार जल संकट से निपटने के लिए गंभीर नजर आ रही है। हालांकि प्राकृतिक जल संसाधन, नदियों, जलस्रोतों से भरपूर इस देश में जल संकट से निपटने के लिए इस तरह की प्रक्रिया अपना कर सरकार उलटबांसी करती ही प्रतीत हो रही है। अगर हमने अपने जलस्रोतों को संरक्षित किया होता और उन्हें प्रदूषित होने से बचाया होता तो शायद आज देश इस मुकाम पर नहीं खड़ा रहता जहां मीठे पाने के लिए हमें डिसैलिनेशन संयंत्र लगाने के बारे में सोचना पड़ता। हालांकि अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है और अगर सही दिशा में काम किया जाए तो देश जल समस्या से निपट सकता है और हमें डिसैलिनेशन संयंत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

हमें इससे जुड़े आर्थिक पहलू, पर्यावरणीय संकट और स्वास्थ्य पहलुओं पर भी विचार करना होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि डिसैलिनेशन संयंत्र से उम्मीद से काफी ज्यादा नमक वाले अपशिष्ट जल और जहरीले रसायन वापस समुद्र में जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण और समुद्री जीवों को नुकसान हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में यह इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या हम वर्तमान की समस्या से निकलने के लिए अपना भविष्य खराब करना चाहेंगे?

इजराइल अपने यहां डिसैलिनेशन संयंत्र से रोजाना 6.30 लाख घनमीटर समुद्री पानी पीने योग्य बनाता है। इससे वहां की 40 प्रतिशत पानी की जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन इजराइल की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट में कहा था कि डिसैलिनेशन से साफ हुआ पानी पीने वाले ज्यादातर बच्चों और महिलाओं में आयोडीन व मैग्नीशियम की भारी कमी है।

डिसैलिनेशन की प्रक्रिया में काफी बिजली खपत होती है जिससे लागत अधिक आती है। हालांकि इस खर्च को कम करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कुछ कम तापमान वाले थर्मल डिसैलिनेशन संयंत्र लगाए हैं और तकनीक से पानी को शुद्ध करने में 19 पैसे प्रति लीटर का खर्च आता है। भले ही एक लीटर पानी तैयार होने में 19 पैसे का खर्च मामूली नजर आ रहा हो, लेकिन जब हमें प्राकृतिक स्रोतों से मुफ्त में पानी मिल रहा है और हमें इसके लिए इतना भी पैसा खर्च करना पड़े तो यह दुखद प्रतीत होता है।

सरकार पानी की समस्या से निपटने के लिए अगर दूसरे तरीके से काम करती तो शायद बेहतर नतीजे सामने आते। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बरसात के रूप में हमें 4,000 अरब घन मीटर पानी मिलता है और इसमें से हम केवल 1,000 घन मीटर पानी ही इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर हम 2,000 घन मीटर पानी बचा लें तो हमारे देश में जरूरत से अधिक जल होगा और हम अगले कई वर्षों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। वर्षा के कारण हमारे देश में हर साल बाढ़ आती है और जानमाल का व्यापक नुकसान होता है। इतना ही नहीं, एक ही समय हमारे देश का एक हिस्सा बाढ़ से जूझ रहा होता है तो उसी समय दूसरा हिस्सा सूखा झेल रहा होता है। ऐसे में हमें जल संरक्षण के पुरानी तकनीक और वर्षा जल संरक्षण पर भी समुचित ध्यान देना होगा। भारत में दुनिया की करीब 18 प्रतिशत आबादी रहती है और हमारे ज्यादातर जलस्रोत प्रदूषित हो गए हैं। हमारे यहां कई राज्य ऐसे हैं, जहां साफ पानी यानी पीने का पानी पांच प्रतिशत से भी कम मात्रा में उपलब्ध है। पानी और खेती की 65 प्रतिशत जरूरतें भूजल से पूरी होती हैं और हम हैं कि इसका बेतहाशा दोहन करते जा रहे हैं। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब टैंकर और डिब्बाबंद पानी पर निर्भर होता जा रहा है। हमें समझना होगा कि 20 लीटर वाले पानी के डिब्बे को भरने के लिए हमें 40 लीटर भूजल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे और जल संरक्षण को लेकर जागरूक नहीं होंगे तो हमारे सामने पानी का संकट विकराल होगा ही और हम डिसैलिनेशन जैसे संयंत्रों पर निर्भर होते चले जाएंगे।

ऐसे में जल संरक्षण को लेकर हमें सावधान होना पड़ेगा और इस दिशा में ठोस प्रयास और स्थायी उपाय करने होंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम पानी के मामले में सुरक्षित होंगे और चिंता से दूर आत्मनिर्भर होंगे। इस संकट को दूर करने के लिए हम उन देशों से भी सीख ले सकते हैं, जहां भारत की तुलना में बहुत कम बारिश होती है और जलस्रोत भी कम हैं, लेकिन जल भंडारण के जरिये जल संकट दूर करते हैं।

जनपथ

गलती से भी यदि कहीं इनका वश चल जाय,
दे डालें कश्मीर ये पूरा थाल सजाय।
पूरा थाल सजाय पाक को देयं खजाना,
ज्यों पीओके सौंप गए इनके परनाना!
यह तो मोदी राज न इसमें इनकी चलती,
वरना दें दोहराय पुन: पुश्तैनी गलती!!
– ओमप्रकाश तिवारी

21 21 कैदी गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर आगरा कारागार से रिहा किए गए। इन कैदियों की सजा खत्म हो गई गई थी, लेकिन जुर्माना न भर पाने के कारण इनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। इन कैदियों के लिए जुर्माने की रकम स्थानीय व्यापारी राकेश सहगल ने भरी। सभी कैदियों को मिलाकर कुल जुर्माना 1.73 लाख रुपये था।

मप्र सरकार बाघों की सुरक्षा पर 81 करोड़ करेगी खर्च

तैयारी ▸ जंगल-खेतों के बीच बनाई जाएगी बाउंड्रीवॉल, लगाए जाएंगे रिफ्लेक्टर

केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर वन्य जीवों के लिए 441 कार्यों को दी है मंजूरी

नईदुनिया, भोपाल

टाइगर स्टेट का दर्जा दोबारा मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार बाघों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा संवेदनशील हो गई है। सरकार इस साल बाघों की सुरक्षा पर करीब 81 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी। इससे जंगल और खेतों की सीमा पर बाउंड्रीवॉल बनाई जाएगी तो पैट्रोलिंग कैंप, ग्रास लैंड डेवलपमेंट के काम भी किए जाएंगे। दो संरक्षित क्षेत्रों से चार गांवों को भी बाहर निकालने (शिफ्ट करने) की रणनीति बनाई गई है।

पिछले साल देश में सबसे ज्यादा 526 बाघ मध्य प्रदेश में गिने गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश ने टाइगर स्टेट का खोया दर्जा प्राप्त कर लिया है। अब बड़ी चुनौती बाघों की सुरक्षा की है, जिसे लेकर राज्य सरकार ने कैंपा फंड से बड़ी राशि ली है। इस राशि से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के काम करवाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर वन्य जीवों के लिए 441 काम मंजूर किए हैं। इनमें बाघों की सुरक्षा के मद्देनजर होने वाले कामों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार बाघों को शिकारियों (फंदे व जहरखुरानी की घटनाओं) से बचाने के लिए नेशनल पार्क, अभयारण्य और बाघ शिकार को लेकर संवेदनशील सामान्य वनमंडलों में जंगल एवं खेतों की सरहद पर बाउंड्रीवॉल बनाएगी। वन अधिकारी इसके कई फायदे गिनाते हैं। वे कहते हैं कि पत्थरों की बाउंड्री बनने से मवेशी और अन्य पालतू जानवर जंगल में नहीं जाएंगे तो बाघ भी जंगल से बाहर नहीं आएगा। इससे मवेशी के शिकार के चलते बाघ के प्रति जनता के गुस्से को रोका जा सकता है। ऐसे में बाघ को जहर देकर, करंट और फंदा लगाकर मारने की घटनाएं रुक जाएंगी। लोग बाघ द्वारा मवेशियों के शिकार पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।

मप्र के जंगल में विचरण करते बाघ। फाइल फोटो

33 क्षेत्रों में बनाई जाएगी बाउंड्री : वन विभाग बांधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी नेशनल पार्क, उमरिया वनमंडल और रातापानी अभयारण्य सहित 33 संरक्षित और गैर संरक्षित वन क्षेत्रों में बाउंड्रीवॉल बनवाएगा। ये क्षेत्र बाघ सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील पाए गए हैं।

2343 हेक्टेयर में ग्रास लैंड विकसित होगा : विभाग 2334 हेक्टेयर में ग्रास लैंड विकसित करेगा। इससे बाघों को छिपने और शिकार करने में आसानी होगी। इसका असर उनके वंशवृद्धि पर भी पड़ेगा। वन अधिकारी कहते हैं कि छिपने की अच्छी जगह मिलेगी तो वंश भी बढ़ेगा। इसके अलावा पैट्रोलिंग कैंप भी बढ़ाए जा रहे हैं। इससे बाघों पर सतत निगरानी रखी जाएगी।

गांव विस्थापित होंगे : बाघों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग श्योपुर के कुनो पालपुर नेशनल पार्क से खजूरी खुर्द, दुरई, खरेंडी-पलौदा, पेंच टाइगर रिजर्व के ग्राम कर्माझिरी और दक्षिण वनमंडल बालाघाट से ग्राम चिखलाबड्डी को विस्थापित करेगा। इसकी मंजूरी मिल गई है और विस्थापन के लिए 21.72 करोड़ रुपये भी मंजूर हो गए हैं।

अस्पताल में भर्ती गौर की कुशलक्षेम पूछने पहुंचे कमलनाथ

नईदुनिया, भोपाल: एक निजी अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की कुशलक्षेम पूछने गुरुवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

गौरतलब है कि गौर को निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ के चलते नर्मदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। दवाओं का असर कम हो रहा है। इस बीच बुधवार को सोशल मीडिया में उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल गईं। अलबत्ता, उनका इलाज कर रहीं डॉ. रेणु शर्मा ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि गौर की हालत चिंताजनक जरूर है, पर उनके शरीर में हलचल है। स्वास्थ्य में जैसा सुधार होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। इस बीच गुरुवार को कमलनाथ उनको देखने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से गौर के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया कि गौर का स्वास्थ्य बुधवार के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने डाक्टरों से गौर के स्वास्थ्य पर सतत निगरानी रखने को कहा। कमलनाथ के साथ जनसंपर्क एवं विधि विधायी मंत्री पीसी. शर्मा भी थे।

गौर को एक महीने पहले हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। इसके बाद वे भोपाल स्थित अपने आवास में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, तभी उनकी हालत बिगड़ गई।

हरियाणा के '0.5' से छत्तीसगढ़ में बढ़ी एक मंत्री की उम्मीद

नईदुनिया, रायपुर

▸ दोनों राज्यों की विधानसभा में हैं 90-90 सदस्य, लेकिन छत्तीसगढ़ में 13 तो हरियाणा में हैं 14 मंत्री

छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का कोरम पूरा होने के बाद मंत्री पद की फिर से दावेदारी उठने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अमितेष शुक्ल ने हरियाणा के फॉर्मूले का हवाला देकर 14वें मंत्री का राग छेड़ दिया है, जिससे दूसरे दावेदार विधायकों की उम्मीद भी जाग गई है। हरियाणा फॉर्मूले को देखा जाए, तो यहां भी 'दशमलव पांच' एक मंत्री का पद बढ़ा सकता है। अभी छत्तीसगढ़ में 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल है।

विधानसभा सदस्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ और हरियाणा बराबर हैं। दोनों राज्यों में 90-90 विधायक हैं। संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या, राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या की 15 फीसद से अधिक नहीं हो सकती है। इस लिहाज से मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 13.5 होती है। छत्तीसगढ़ में दशमलव पांच को छोड़कर 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है, जबकि हरियाणा में दशमलव पांच को पूरा एक मानकर 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया जाता रहा है। हालांकि, हरियाणा में संविधान के विपरीत ज्यादा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगी है, जो विचारधीन है। दोनों राज्यों के मंत्रिमंडल में एक और फर्क है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और 12 कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, जबकि हरियाणा में मुख्यमंत्री के अलावा आठ कैबिनेट मंत्री और बाकी राज्य मंत्री होते हैं। उस आधार पर छत्तीसगढ़ में मंत्री पद के दावेदार विधायक के बीच एक राज्य मंत्री बनाए जाने की मांग उठने लगी हैं।

जोगी शासनकाल में था 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल : छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थी, जिन्होंने अपने शासनकाल में 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया था। मुख्यमंत्री के अलावा 26 मंत्री बनाए थे।

छत्तीसगढ़ के दल-बदल के कारण हुआ संशोधन : जोगी शासनकाल में दल-बदल हुआ था। उसके बाद ही 2004 में संविधान में 91वां संशोधन किया गया था, जिसमें दल-बदल कानून था। उसी समय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या से 15 फीसद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यह नियम भी बन गया।

मंत्री पद के दावेदार खुलकर आ चुके हैं सामने : कांग्रेस में मंत्री पद के दावेदार विधायक खुलकर सामने आ चुके हैं। जब 25 दिसंबर 2018 को कांग्रेस सरकार में दूसरी किस्त में नौ मंत्रियों का शपथग्रहण समारोह हुआ, तो सूची में नाम नहीं होने के कारण अमितेष शुक्ल, धनेंद्र साहू, अरुण वोरा ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया था, जबकि भानुप्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के सामने नाराजगी व्यक्त की थी। इसके अलावा वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा को मंत्री नहीं बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने भी नाराजगी जताई थी।

दो विधायकों के बागी होने के बाद से मप्र में भाजपा नेताओं ने साधी चुप्पी

नईदुनिया, भोपाल : अपनी ही पार्टी के दो विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल के बागी होने के बाद से कमलनाथ सरकार को आए दिन धमकी देने वाले मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। पार्टी की संभागीय स्तर पर समीक्षा बैठकों में भी विधायकों और अन्य नेताओं को साफतौर पर सरकार के भविष्य को लेकर बयानबाजी नहीं करने के निर्देश दिया जा रहे हैं।

गौरतलब है कि जुलाई में संपन्न हुए विधानसभा सत्र के दौरान संशोधन विधेयक पर मत विभाजन के दौरान भाजपा के मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी और ब्योहारी से शरद कोल ने पार्टी लाइन से अलग जाकर कांग्रेस का समर्थन किया था। तब इस बात की चर्चा थी कि ये दोनों विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस बात से चिंतित भाजपा ने अब तक दोनों विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने और परिणाम आने से पहले नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने फ्लोर टेस्ट की बात कही थी। इसके बाद ही कमलनाथ सरकार अलर्ट हो गई और उसने अपने सारे विधायकों की घेराबंदी कर ली। असर ये हुआ कि भाजपा लगातार बयानबाजी करती रही और कांग्रेस ने भाजपा के घर में ही सेंध लगा दी।

भाजपा से बगावत कर कांग्रेस सरकार का समर्थन करने वाले दो बागी विधायकों का अब कांग्रेस में भी विरोध हो रहा है। जिन इलाकों से ये विधायक चुनाव जीतकर आए हैं, वहीं के नेता और कार्यकर्ता इनके खिलाफ लामबंद हो गए हैं।

वनाधिकार दावे और भूमि मान्यता देने में छग देश में दूसरे स्थान पर

नईदुनिया, रायपुर

▸ राज्य में चार लाख व्यक्तिगत और 24 हजार सामुदायिक वनाधिकार के पत्रक वितरित

अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन भूमि की मान्यता देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरा राज्य बन गया है। यहां चार लाख से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रकों का वितरण कर तीन लाख 42 हजार हेक्टेयर वनभूमि पर मान्यता दी गई है। वहीं, 24 हजार से अधिक प्रकरणों में सामुदायिक वनाधिकार पत्रकों का वितरण करते हुए नौ लाख 50 हजार हेक्टेयर भूमि पर सामुदायिक अधिकारों की मान्यता दी गई है।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वनाधिकार पत्रकों के वितरण के मामले ओडिशा और वन भूमि की मान्यता प्रदान करने के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। इन दोनों ही मामलों में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यभार संभालते ही 23 जनवरी को वन अधिकारों को लेकर राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री ने 30 मई को बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर और तीन जून को सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में वनाधिकार की संभागीय कार्यशालाओं में उपस्थित होकर इसके क्रियान्वयन को लेकर मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला में यह बात उभर सामने आई की प्रक्रियागत कमियों की वजह से बड़ी संख्या में वन अधिकार के दावे निरस्त हुए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा करने और अन्य परंपरागत वन निवासियों को भी पात्रतानुसार वनाधिकार प्रदान करने के निर्देश दिए थे।

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को वन अधिकारों के समुचित क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया था। इसमें ग्राम स्तर पर वन अधिकार समितियों के पुनर्गठन करने को कहा गया है। इसके साथ ही अनुभाग और जिला स्तरीय समितियों के गठन के लिए राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर कर दिया गया है।

रेलवे के कंबल की होगी मॉनिटरिंग, 15 दिन बाद बजेगा धुलाई का अलार्म

निशांत यादव, लखनऊ

ट्रेनों के एसी क्लास में मिलने वाले गंदे बेडरोल की शिकायत भले ही रेलवे अनसुना करता हो, लेकिन अब गंदा होने पर कंबल खुद बोलेगा...मैं हो गया गंदा। 15 दिन के भीतर धुलाई न होने पर रेलवे को अलर्ट भेज देगा। यह मुमकिन होगा कंबल की इलेक्ट्रानिक टैगिंग से। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल सभी ट्रेनों के करीब 10 हजार कंबलों में 15 सितंबर से यह व्यवस्था शुरू कर देगा।

यात्रियों को रेलवे जो बेडरोल मुहैया कराता है, उसमें तकिया कवर, चादर और तौलिया को एक बार इस्तेमाल के बाद धोने का नियम है। जबकि कंबल की धुलाई 15 दिन में कराने की व्यवस्था है। हालांकि, हकीकत में उन्हें दो से ढाई महीने बाद धोया जाता है। यही वजह है, बेडरोल में बदबूदार कंबल की शिकायत सबसे अधिक मिलती है। इसी को देखते हुए रेलवे ने कंबल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फैसला किया।

15 सितंबर से लखनऊ की सभी ट्रेनों के कंबल की ई-टैगिंग

ट्रेन में सप्लाई के लिए रखे गए कंबल। फाइल फोटो

> ऑनलाइन मॉनिटरिंग से कंबल की धुलाई सुनिश्चित हो सकेगी। वहीं, इसके चोरी होने और गंदगी को लेकर यात्रियों की शिकायतें कम होंगी।
>
> -संजय त्रिपाठी, डीआरएम, लखनऊ मंडल

ऐसे होगी मॉनिटरिंग : बड़े शॉपिंग मॉल की तरह हरेक कंबल की टैगिंग की जाएगी। इसमें एक बार कोड होगा, जिसे हर बार धुलाई के समय स्कैनर से स्कैन कर उसका डाटा कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। हर एक कंबल का एक आइडी नंबर बनाया जाएगा, जो कंबल की टैगिंग पर दर्ज होगा। एक बार धुलाई के बाद कंबल को दोबारा 15 दिन पूरा होने पर लांड्री में लाना होगा। ऐसा न करने पर 16वें दिन कंप्यूटर पर एक अलार्म बजेगा जिसमें आइडी नंबर से यह पता चलेगा कि कौन सा कंबल है जिसकी धुलाई का समय पूरा हो गया है। मंडल प्रशासन आइडी नंबर से उस ट्रेन को खोज निकालेगा, जिसमें वह कंबल होगा।

निर्धारित दिन से पहले अटेंडेंट की जिम्मेदारी : यदि कंबल 15 दिन से पहले गंदा होगा तो कोच अटेंडेंट उसे निकालकर लांड्री को वापस सौंपेगा। वहां उसकी धुलाई की ऑनलाइन फीडिंग फिर से होगी। रेलवे निजी एजेंसी की मदद से ऑनलाइन मॉनिटरिंग का सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बनवाएगा। इसे कैरिज व वैगन अनुभाग के कर्मचारी नियंत्रित करेंगे।

छड़ी मुबारक पूजन के साथ बाबा अमरनाथ यात्रा संपन्न

जेएनएन, जम्मू

▸ जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात के कारण 31 जुलाई को ही रोक दी थी यात्रा

▸ एक जुलाई को शुरू हुई यात्रा सिर्फ एक महीने चली, तोड़ा तीन साल का रिकॉर्ड

पवित्र छड़ी मुबारक के दर्शनों के साथ ही बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न हो गई। यात्रा एक जुलाई से शुरू हुई थी। छड़ी मुबारक को हेलीकॉप्टर से पंजतरणी ले जाया गया जहां से आगे छड़ी मुबारक पवित्र गुफा तक पहुंची और वहां विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इसी के साथ ही 46 दिन की बाबा अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई। इस बार कुल तीन लाख 40 हजार श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा अमरनाथ के दर्शन किए। हालांकि जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात के कारण यात्रा को 31 जुलाई को ही रोक दिया गया था।

छड़ी मुबारक के संरक्षक और दशनामी अखाड़ा के महंत देपेंद्र गिरि के नेतृत्व में छड़ी मुबारक में पवित्र गुफा के दर्शन किए। यात्रा ने इस बार पिछले तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ा। यात्रा शुरुआत से लेकर स्थगित होने तक श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। यात्रा को बीच में ही रोक दिए जाने के कारण कई श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ा।

जिला पुंछ में स्थित बाबा बुड्ढा अमरनाथ में भी विशेष आरती के बाद छड़ी यात्रा संपन्न होने की घोषणा हुई। हालांकि यहां छड़ी बुधवार को ही स्थापित कर दी गई थी। सुबह से ही छड़ी के दर्शनों के लिए यहां श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। गुरुवार को पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर 1008 राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज सहित अन्य विद्वानों ने छड़ी की पूजा अर्चना की। अमरनाथ यात्रा की तरह ही यहां भी श्रावण मास में श्रद्धालुओं की लाइन लगी रहती है। लेकिन जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात के कारण यात्रा को आरंभ होने से पहले ही स्थगित कर दिया गया था। यही वजह रही कि महामंडलेश्वर की अगुआई में कुछ श्रद्धालुओं की मौजूदगी में ही छड़ी पूजन संपन्न किया गया।

प्रधानमंत्री से मांगेंगे रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जमीन : सुखबीर

जेएनएन, बाबा बकाला साहिब (अमृतसर)

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि शिअद-भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा और दिल्ली में श्री गुरु रविदास मंदिर गिराए जाने के बदले जमीन उपलब्ध कराने की मांग रखेगा।

यहां रखड़ पुनिया पर एक रैली को संबोधित करते हुए सुखबीर ने कहा कि पूजा स्थल ध्वस्त होने का दर्द सिखों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमने कांग्रेस सरकार के हाथों ऐसा दर्द झेला है। शिअद-भाजपा का प्रतिनिधिमंडल जल्द प्रधानमंत्री से मिलेगा और उनसे दिल्ली के तुगलकाबाद में ध्वस्त किए गए श्री गुरु रविदास मंदिर का उपयुक्त समाधान खोजने और दलित समुदाय की आहत भावनाओं पर मरहम लगाने की बात कहेगा।

अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना : सुखबीर ने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर फूट डालो और राज करो की नीति के तहत सिखों को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने झूठ की बुनियाद पर सरकार बनाई। सत्ता में आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को पूर्ण कर्ज माफी, युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने जैसे झूठे वादे गुटखा साहिब हाथ में पकड़ कर किए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कैप्टन तो एक अदृश्य मुख्यमंत्री हैं। उनके पास अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन को प्रणाम करने का समय भी नहीं है। इससे सिख धर्म के प्रति उनकी भक्ति की झलक साफ दिखाई दे रही है।

सुखबीर सिंह बादल। फाइल फोटो

नशा जो-शोर से बिक रहा: सुखबीर ने कहा कि कैप्टन सत्ता में आने के चार सप्ताह के भीतर नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन नशीले पदार्थ जोर-शोर से बिक रहे हैं।

सिखों ने दिया बड़ा बलिदान

बादल ने कहा कि आजादी के संघर्ष में सबसे ज्यादा बलिदान सिख समुदाय का है। काला पानी भेजे गए 97 प्रतिशत कैदी सिख थे। स्वतंत्रता सेनानियों में से 95 प्रतिशत से अधिक सिख थे। सुखबीर ने कहा कि युद्ध के दौरान हमें सबसे पहले दुश्मन का सामना करना पड़ता है। सिख देश के सम्मान के लिए लड़ते हुए महान बलिदान देते आए हैं।

सुखबीर बने मुख्यमंत्री पद का चेहरा

इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक ने सुखबीर बादल को पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया, बीबी जागीर कौर, मनजीत सिंह मियांविंड, बलजीत सिंह जलालउसमां, गुलजार सिंह रणीके, विरसा सिंह वल्टोहा और वीर सिंह लोपोके भी उपस्थित थे।

मेडिकल सुविधा से कैलास मानसरोवर यात्री संतुष्ट नहीं

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: कैलास मानसरोवर यात्रा में जाने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यात्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भेजे जाने वाले चिकित्सक के पास भी दवा उपलब्ध नहीं रहती है। यात्री भोले का नाम लेकर यात्रा करते हैं। पिथौरागढ़ पहुंचे 12वें दल के यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए।

यात्रियों ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें मेडिकल की अच्छी सुविधा नहीं मिली। वायुसेना में विंग कमांडर पद पर तैनात दल के एलओ राजेश ने बताया कि धारचूला से गुंजी तक नाम मात्र के चिकित्सक भेजे गए थे, उनके पास मेडिकल की कोई सुविधा नहीं थी। यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों का स्वास्थ्य खराब हो गया था, मगर चिकित्सक के पास दवा उपलब्ध नहीं थी। राजेश ने बताया कि वह सेना अस्पताल जोधपुर से दवा लेकर आए थे। यात्रियों का इलाज भी दल में शामिल पंजाब निवासी चिकित्सक डॉ. आयुष बलदान द्वारा किया गया। उनके द्वारा कई यात्रियों को ड्रिप भी चढ़ाई गई। जिसके चलते यात्रियों को काफी राहत मिली।

रविशंकर की कलाई पर बांधी राखी

तत्काल तीन तलाक का बिल पास कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद की कलाई पर गुरुवार को नई दिल्ली में रक्षाबंधन पर्व पर मुस्लिम महिलाओं ने राखियां बांधी। मुस्लिम महिलाएं (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 मुस्लिम महिलाओं के लिए एक तरह का वरदान है और उन्हें अब तत्काल तीन तलाक के माध्यम से तलाक देना अवैध बन गया है। जागरण

अटल जी की पहली पुण्यतिथि पर विशेष

बटेश्वर में वाजपेयी की यादें अटल, पर वादे खोखले

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि आज, साल भर बाद भी नहीं रखी जा सकी पैतृक गांव में विकास की नींव

विनीत मिश्र, आगरा

यमुना तीरे बसे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के गांव बटेश्वर में उनकी यादें आज भी अटल हैं, लेकिन अफसरों की लापरवाही से वादे खोखले साबित हो रहे। बटेश्वर ने विकास की उम्मीदें तब भी पालीं, जब अटल विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बने।

ग्रामीण कहते हैं कि उम्मीद थी कि देश के साथ उनके पैतृक गांव का भी विकास होगा। देश आगे बढ़ा भी, लेकिन गांव उसी हाल में रह गया। बीते वर्ष 16 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद बटेश्वर का ये लाल चिरनिद्रा में लीन हो गया। आठ सितंबर को यमुना में अटल की अस्थियां विसर्जित करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो बटेश्वर के विकास को लेकर कई घोषणाएं कीं। उम्मीद बंधी, खुद सीएम आए हैं तो जल्द बटेश्वर में जल्द विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। अटल के जन्मदिन 25 दिसंबर पर विकास योजनाओं के शिलान्यास होने की आस भी बंधी। दस करोड़ रुपये के प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे गए, लेकिन आज तक धनराशि ही जारी नहीं हो सकी। हां, संवरने के नाम पर कुछ हुआ तो अटल की खंडहर हो चुकी पैतृक हवेली को जाने वाला करीब 50 मीटर रास्ता। अटल के परिवार के भतीजे राकेश वाजपेयी और अश्वनी वाजपेयी कहते हैं कि सपने दिखाए गए, लेकिन साकार करना भूल गए।

उत्तर प्रदेश में आगरा के बटेश्वर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हवेली खंडहर हो चुकी है। जागरण

10 करोड़ के ये बने थे प्रस्ताव

- अटल की पैतृक हवेली में अटल के संस्मरण संजोने के लिए संग्रहालय।
- अटल की यज्ञशाला को जोड़ते हुए पार्क और मंदिरों को जोड़ना।
- बटेश्वर की जिस जंगलात कोठी में अटल ने बचपन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तिरंगा फहराया था, उसका जीर्णोद्धार।
- अटल की प्रतिमा की स्थापना।

> घाटों का जीर्णोद्धार और इंटरलॉकिंग के लिए 90 लाख रुपये आवंटित हुए हैं। कार्यदायी संस्था से जल्द काम करने को कहा गया है। अन्य प्रस्ताव के लिए अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं हुई है।
>
> -एनजी रविकुमार, डीएम, आगरा

हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टायफस से पांचवीं मौत

जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश में जानलेवा बीमारी स्क्रब टायफस से एक और मरीज की जान ले ली। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आइजीएमसी) एवं अस्पताल में मंडी जिला के थुनाग निवासी ज्वाला दास की मौत हो गई। ज्वाला दास को 31 जुलाई को आइजीएमसी में दाखिल करवाया गया था। डॉक्टर लगातार निगरानी रख रहे थे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बुधवार दोपहर उनकी मौत हो गई। प्रदेश में स्क्रब टायफस से मरने वालों की संख्या अब पांच हो गई है। इनमें से तीन महिलाएं व दो पुरुष हैं। प्रदेश में 260 से ज्यादा मामले स्क्रब टायफस पॉजिटिव पाए गए हैं।

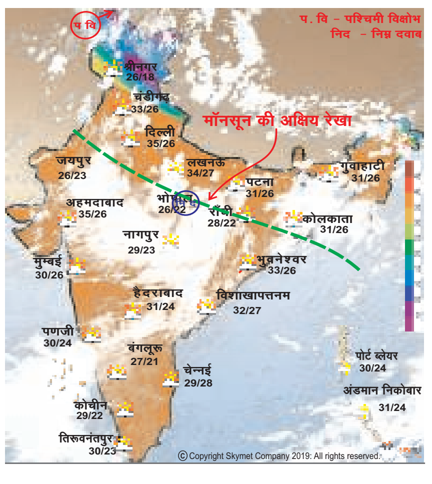

मौसम विशेष

राजस्थान के पूर्वी भागों में अनेक स्थानों पर गरज व तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होगी तथा बाढ़ जैसी स्थिति संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी राजस्थान में मौसम गर्म होगा। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में गरज के साथ वर्षा का दौर जारी रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/26/व	अहमदाबाद	34/25/व
कोलकाता	30/25/आंबा	बड़ौदा	33/25/व
चेन्नई	39/28/आंबा	नागपुर	32/24/आंबा
हैदराबाद	32/24/व	इन्दौर	27/23/व
बंगलूरू	26/20/व	रांची	33/24/आंबा
त्रिवेन्द्रम	31/24/व	पटना	37/28/आंबा
गुवाहाटी	31/26/व	जमशेदपुर	36/27/व
गंगटोक	19/09/व	पुणे	25/22/आंबा

बोली में हेराफेरी करने वाली 51 कंपनियों पर जुर्माना

नई दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने बोली में हेराफेरी करने वाली 51 कंपनियों पर 40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों ने तेल विपणन कंपनी एचपीसीएल को सिलेंडर आपूर्ति के लिए बोली लगाते समय एक-दूसरे से मिलकर धांधली की थी। 18 राज्यों में स्थित एचपीसीएल के बॉटलिंग प्लांटों के लिए कुल 40 लाख सिलेंडरों की आपूर्ति की जानी थी। इनके लिए जनवरी, 2013 में टेंडर निकाले गए थे। 2014 में सीसीआइ ने जांच का निर्देश दिया था। (प्रेट्र)

कंपनी 25 परियोजनाओं पर 83,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। यह निवेश तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

— शशि शंकर
चेयरमैन व एमडी, ओएनजीसी

निवेश के बूते बढ़ेगी अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार : पीएम

एलान ▶ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर सरकार करेगी 100 लाख करोड़ रुपये का बड़ा निवेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे जाते हुए ईज ऑफ लिविंग पर जोर दिया। ध्रुव कुमार

कहा – अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले सभी हैं मान–सम्मान के हकदार, मिलेगी नई ताकत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था की रफ्तार में सुस्ती की चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से अगले पांच साल का आर्थिक विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि अब समय निवेश पर आधारित विकास का है और इसके लिए सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपये की बड़ी राशि खर्च करना तय किया है। इससे अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने देश के कारोबारियों को आश्वस्त किया कि संपत्ति अर्जित करने वालों के बारे में आशंका नहीं रखकर उन्हें मान सम्मान दिया जाना चाहिए। इस बारे में उन्होंने राजनीतिक तौर पर कांग्रेस व उन विरोधी दलों को भी कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जो कुछ उद्योगपतियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं।

अर्थव्यवस्था में भरोसा जगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद बहुत मजबूत है। यह मजबूती हमें आगे ले जाने का भरोसा देती है।' देश की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा, 'हमें अब ऊंची छलांग लगानी होगी।' उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप लाने के लिए आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इसलिए हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपये आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी नई व्यवस्था विकसित होगी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अब तक विकास को लेकर रही प्रचलित धारणाओं को बदलने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक हमारे देश में सरकारों की पहचान इस बात से बनती रही है कि उसने किस इलाके के लिए कितना खर्च किया। या किस वर्ग के लिए कितना दिया। अब वक्त है देश के लिए सपना देखने का, उन्हें साथ लेकर जीने का। उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश को दो लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 70 वर्ष का समय लग गया। लेकिन राजग सरकार ने 2014 से 2019 की पांच साल की सरकार में इसमें एक लाख करोड़ डॉलर जोड़ दिया। मोदी ने कहा कि अगर पांच साल में इतना बड़ा जम्प लगाया है तो आने वाले पांच साल में हम पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं।

बीते पांच साल में भ्रष्टाचार को लेकर उठे कदमों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बीमारी की संज्ञा दी। उन्होंने कहा, 'मैं स्पष्ट मानता हूं, सामाजिक जीवन में बदलाव होना चाहिए, उसके साथ साथ व्यवस्थाओं को चलाने वाले लोगों के दिलो-दिमाग में भी बदलाव बहुत अनिवार्य होता है। तभी जाकर हम इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं।'

ईज ऑफ लिविंग मेरा मकसद : देश में कारोबार करने की सहूलियतों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में हमने अच्छी छलांग लगाई है। अब शीर्ष 50 देशों की सूची में पहुंचने का सपना है। देश में कई गैरजरूरी कानूनों को खत्म किया गया है। उन्होंने कहा 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो एक पड़ाव है। मेरी मंजिल तो 'ईज ऑफ लिविंग' है। हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं।'

मंदी पर बैठक, जल्द कुछ घोषणाओं की आस

▶ मंदी का प्रकार और लंबी अवधि में उसके संभावित प्रभावों के आकलन के लिए गुरुवार को हुई बैठक

▶ पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय की बैठकों के बाद प्रधानमंत्री की यह बैठक बेहद अहम

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले कुछ समय से अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती की थाह लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का मुख्य मकसद यह समझना था कि अर्थव्यवस्था इस वक्त जिस मंदी से गुजर रही है उसका प्रकार क्या है और लंबी अवधि में विभिन्न सेक्टरों पर इसके क्या असर दिख सकते हैं।

अर्थव्यवस्था अभी जिस तेजी से मंदी की ओर जा रही है कई सेक्टर में नौकरियों पर छंटनी की तलवार लटक रही है, उसे देखते हुए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कई सेक्टरों के लिए सरकार जल्द राहत के कुछ कदमों की घोषणा कर सकती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिला पर झंडोत्तोलन के बाद प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अर्थव्यवस्था के हालात का जायजा लिया। गौरतलब है कि बीते वित्त वर्ष (2018-19) में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर घटकर 6.8 फीसद रह गई, जो वित्त वर्ष 2014-15 के बाद का निचला स्तर है। वर्तमान में ग्राहकों का भरोसा डगमगाया हुआ है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआइ) लगातार पूंजी बाजारों से रकम निकाल रहे हैं और ट्रेड वार के चलते कारोबारी भौगोलिक गणित बदल रहे हैं।

हालांकि सीतारमण और मंत्रालय के अधिकारियों ने पिछले पूरे सप्ताह महत्वपूर्ण सेक्टरों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं समझने का प्रयास किया। लेकिन अर्थव्यवस्था को इस हालत से निकालने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है, इस पर वित्त मंत्रालय ने अब तक चुप्पी साध रखी है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने इसी महीने कहा था कि वर्तमान सुस्ती संरचनात्मक नहीं, बल्कि चक्रीय प्रकृति का है और चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2020) से यह एक बार फिर उछाल की अवस्था में आ जाएगा। आरबीआइ ने मंदी को संतोषजनक स्थिति में देखते हुए ही लगातार चौथी बार रेपो रेट में कटौती की। यह भी उल्लेखनीय है कि इसी महीने की शुरुआत में हुई कटौती 25 आधार अंकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा (35 आधार अंकों) की थी।

गहरी सुस्ती के संकेत

हालांकि कई सेक्टर ऐसे संकेत दे रहे हैं कि सुस्ती कहीं ज्यादा गहरी है। ऑटो सेक्टर बिक्री के मोर्चे पर पिछले करीब दो दशकों के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स सेक्टर में हजारों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी अनबिके घरों की तादाद लगातार बढ़ रही है। तेजी से बिकने वाले रोजमर्रा के सामानों (एफएमसीजी) के सेक्टर में भी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल–जून, 2019) में वॉल्यूम ग्रोथ गिरी है। प्रत्यक्ष कर संग्रह भी इस दौरान महज 1.4 फीसद की दर से बढ़ा है और जुलाई तक जीएसटी संग्रह 18 फीसद की बजट उम्मीदों के मुकाबले सिर्फ नौ फीसद रहा है।

इफको का तोहफा, खादों के घटाए दाम

▶ डीएपी और एनपीके उर्वरकों की कीमत में 50 रुपये प्रति बोरी की कटौती

▶ किसानों की उत्पादन लागत में कमी लाना इसका मुख्य मकसद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खाद उत्पादक अग्रणी को-ऑपरेटिव इफको ने किसानों को उर्वरकों की कीमत में कमी का तोहफा दिया है। इफको ने डीएपी और एनपीके खादों के दाम 50 रुपये प्रति बोरी घटा दिए हैं। घटी हुई कीमतें गुरुवार से ही लागू हो गई हैं।

इफको के एमडी यूएस अवस्थी ने एक ट्वीट के माध्यम से कीमतों में कटौती का एलान किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इससे मदद मिलेगी, क्योंकि कीमतों में कमी किसानों की उत्पादन लागत को घटाएगी।' इसके अतिरिक्त इफको ने अपने एक बयान में कहा है कि वह किसानों के हित में अपनी खादों के दाम में निरंतर कटौती करता आया है। ताजा कटौती के बाद डीएपी के दाम प्रति बोरी 1,250 रुपये और एनपीके-1 (नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटाशियम) की कीमत प्रति बोरी 1,200 रुपये हो गई है।

दो महीने पहले ही इफको ने डीएपी की कीमत को प्रति बोरी 1,400 रुपये से घटाकर 1,300 रुपये करने का एलान किया था। साथ ही एनपीके-1 के दाम को 1,365 रुपये से घटाकर 1,250 रुपये प्रति बोरी किया गया था। अन्य उर्वरकों में एनपीके-2 का दाम पहले 1,375 रुपये से घटाकर 1,260 रुपये प्रति बोरी किया गया, जिसे अब 50 रुपये और घटाकर 1,210 रुपये प्रति बोरी किया गया है। इसी तरह एनपी (नाइट्रोजन फॉस्फेट) का दाम भी 1,065 रुपये से घटाकर दो महीने पहले 1,000 रुपये प्रति बोरी किया गया था, जिसे अब 950 रुपये प्रति बोरी कर दिया गया है। उर्वरक की एक बोरी 50 किलोग्राम की होती है। इफको करीब 35,000 सहकारी समितियों के जरिये पांच करोड़ किसानों तक खाद से लेकर अन्य कृषि सेवाएं पहुंचाती है। साल 2018-19 में इफको का राजस्व 27,852 करोड़ रुपये रहा था। इसके पांच उत्पादन संयंत्र हैं और यह 81.49 लाख टन उर्वरक का उत्पादन करती है।

दो महीने पहले ही इफको ने इन उर्वरकों के दाम में की थी कटौती, नई कटौती से दाम और घटे। फाइल

सहारा क्यू शॉप पर चलेगा दिवालिया मामला

▶ एनक्लैट ने एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ एक याचिका की खारिज

▶ एनसीएलटी ने दिसंबर, 2017 में दी थी दिवालिया प्रक्रिया की इजाजत

नई दिल्ली, प्रेट्र : सहारा ग्रुप की सहायक शाखा सहारा क्यू शॉप युनीक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चलनी निश्चित हो गई है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने एनसीएलटी के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें उसने कंपनी के खिलाफ दिवालिया याचिका की अर्जी स्वीकार कर ली थी।

एनक्लैट के चेयरमैन एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के फैसले के खिलाफ सहारा क्यू शॉप की याचिका खारिज की। एनसीएलटी ने 15 दिसंबर, 2017 को कंपनी के एक परिचालन कर्जदाता की याचिका पर उसके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दे दी थी।

एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ सहारा क्यू शॉप के एक शेयरधारक रोमी दत्ता ने एनक्लैट की शरण गही थी। अपनी याचिका में शेयरधारक ने दलील दी कि कंपनी ने किसी भुगतान पर डिफॉल्ट नहीं किया था। उसने कर्जदाताओं को भुगतान सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना प्रक्रिया के दौरान ग्रुप की सभी कंपनियों को कोई भी भुगतान करने से रोका हुआ था।

एनक्लैट ने कंपनी के तर्कों को अस्पष्ट बताकर खारिज कर दिया। फाइल

दत्ता की यह दलील खारिज करते हुए एनक्लैट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर चल रहा था, और कोर्ट ने सहारा क्यू शॉप को कोई भी भुगतान नहीं करने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया था। इसके अलावा एनक्लैट ने कहा कि अवमानना प्रक्रिया के दौरान ही सहारा ग्रुप की एक अन्य कंपनी सहारा हॉस्पिटेलिटी ने एनसीएलटी के समक्ष 20 करोड़ रुपये का भुगतान कर एक मामले में सुलह किया था। इन तथ्यों के मद्देनजर एनक्लैट ने सहारा के शेयरधारक की दलील को अस्पष्ट तथ्य बताते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 21 दिसंबर को सरकार ने सूचित किया कि गंभीर अपराध जांच कार्यालय (एसएफआइओ) सहारा क्यू शॉप के खिलाफ हासिल 744 आवेदनों की जांच कर रहा है।

घटनाक्रम

▶ सहारा क्यू शॉप के तत्कालीन असिस्टेंट जनरल मैनेजर एस गुरुमूर्ति ने कंपनी पर वेतन मद का 46.57 लाख रुपये बकाया भुगतान नहीं करने के आरोप के साथ एनसीएलटी की मुंबई पीठ में दिवालिया याचिका लगाई थी

▶ एनसीएलटी ने 15 दिसंबर, 2017 को दिवालिया प्रक्रिया को मंजूरी दे दी, इस दौरान कंपनी ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा

▶ कंपनी के एक शेयरधारक रोमी दत्ता ने एनसीएलटी के इस फैसले के खिलाफ एनक्लैट में याचिका दी

▶ एनक्लैट ने एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखा

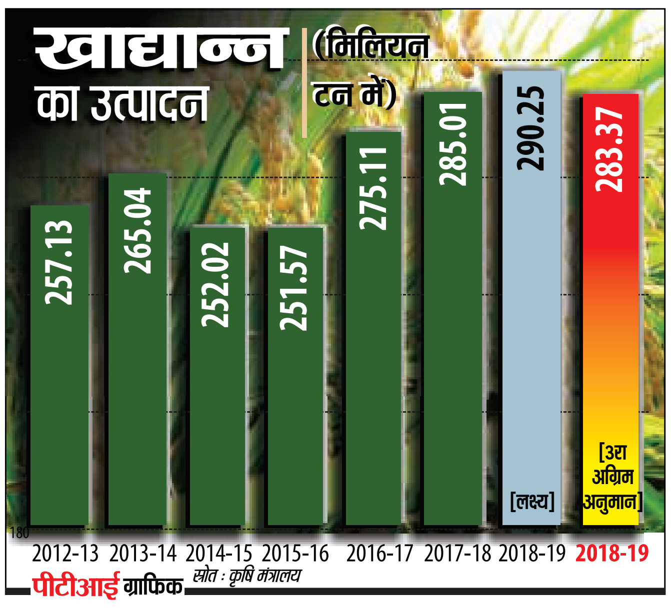

तीन कंपनियां करेंगी पीएफ की पूंजी का प्रबंधन

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पूंजी का प्रबंधन अगले तीन वर्षों के लिए तीन असेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को दिए जाने की संभावना है। इनमें एचएसबीसी एएमसी, यूटीआइ एएमसी और एसबीआइ म्यूचुअल फंड शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि ईपीएफओ की वित्त, ऑडिट और निवेश समिति (एफएआइसी) ने कंपनियों के नाम निर्धारण और अनुशंसा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब ईपीएफओ का केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) 21 अगस्त को प्रस्तावित बैठक में इन नामों के अनुमोदन पर विचार करेगा। बोर्ड के अनुमोदन के बाद ये तीन कंपनियां इस वर्ष पहली अक्टूबर से ईपीएफओ की पूंजी का प्रबंधन करेंगी।

जीएसटी संग्रह में पूर्वोत्तर ने अग्रणी मैन्यूफैक्चरर राज्यों को भी पछाड़ा

▶ चालू वित्त वर्ष में अप्रैल–जुलाई के दौरान दर्ज की गई वृद्धि

▶ पूर्वोत्तर राज्यों में नगालैंड ने सबसे अधिक 39 फीसद की वृद्धि दर्ज की

नई दिल्ली, प्रेट्र : चालू वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीनों में पूर्वोत्तर राज्यों ने जीएसटी संग्रह में तीस फीसद से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि मैन्यूफैक्चरिंग में अग्रणी बड़े राज्यों से काफी ज्यादा है। पूर्वोत्तर के सात राज्यों का जीएसटी संग्रह नौ फीसद के राष्ट्रीय औसत से तीन गुना से अधिक रहा है।

चालू वित्त वर्ष में अब तक अप्रैल-जुलाई के दौरान कुल टैक्स संग्रह 3.56 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में नगालैंड ने सबसे अधिक 39 फीसद की वृद्धि दर्ज की है और अप्रैल-जुलाई के दौरान कुल संग्रह 393 करोड़ रुपये रहा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जीएसटी संग्रह में 35 फीसद बढ़ोतरी हुई और यह 514 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, 32 फीसद बढ़ोतरी के साथ सिक्किम का संग्रह 370 करोड़ रुपये हो गया। मेघालय ने 30 फीसद बढ़ोतरी के साथ संग्रह 680 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

पूर्वोत्तर के सबसे पिछड़े राज्यों का भी प्रदर्शन सुधरा : मिजोरम का जीएसटी संग्रह 27 फीसद वृद्धि के साथ 350 करोड़ रुपये रहा। इस मामले में सबसे पिछड़े राज्य त्रिपुरा और मणिपुर ने भी 16 फीसद के साथ महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों से दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की है।

सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली के जीएसटी संग्रह में दो, लक्षद्वीप में 17 और पुडुचेरी में आठ फीसद की कमी दर्ज की गई है। दिल्ली का जीएसटी संग्रह अप्रैल-जुलाई 2019 के दौरान पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13,000 करोड़ रुपये से घटकर 12,700 करोड़ ही रह गया।

बड़े राज्य 11 फीसद तक ही अटके : महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों ने जीएसटी संग्रह में छह फीसद की वृद्धि दर्ज की, जबकि पंजाब ने सात और हरियाणा ने नौ फीसद की वृद्धि दर्ज की। तमिलनाडु और कर्नाटक ने क्रमशः 10 और 11 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की। जीएसटी संग्रह में बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने दहाई के आंकड़ों में वृद्धि दर्ज कर औद्योगिक राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

सबसे पिछड़े राज्यों का प्रदर्शन भी महाराष्ट्र, गुजरात से बेहतर रहा। प्रतीकात्मक

भारत के लिए सऊदी अरब फिर होगा तेल का सबसे बड़ा स्रोत

▶ दो वित्त वर्षों से इराक था भारत को ऑयल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता

▶ अरैमको से सौदे के बाद रिलायंस को मिलने लगेगा करीब दोगुना कच्चा तेल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सऊदी अरब एक बार फिर भारत के लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने जा रहा है। सऊदी अरैमको द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के पेट्रोकेमिकल्स कारोबार में 20 फीसद हिस्सेदारी खरीदने के बाद यह सूरत बन रही है। कुछ समय पहले तक सऊदी अरब ही भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत था। लेकिन पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान इराक भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला देश बन गया था।

इस वर्ष मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान इराक ने भारत को 4.66 करोड़ टन कच्चे तेल की आपूर्ति की। उसके मुकाबले सऊदी अरब द्वारा भारत को की गई आपूर्ति 4.03 करोड़ टन की रही, जो इराक के मुकाबले 15 फीसद ज्यादा है। रिलायंस के सौदे के बाद सऊदी अरब एक बार फिर भारत के लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन जाएगा।

आरआइएल ने इसी सप्ताह घोषणा की थी कि सऊदी अरैमको ने उसके पेट्रोलियम और केमिकल कारोबार में 20 फीसद हिस्सेदारी खरीदी है। अब रिलायंस को अरैमको से रोजाना पांच लाख बैरल या सालाना 2.5 करोड़ टन कच्चा तेल मिलेगा। वुड मैकेंजी में रिफाइनिंग और केमिकल्स के वाइस प्रेसिडेंट एलन गेल्डर ने कहा कि पांच लाख बैरल रोजाना तेल आपूर्ति का मतलब यह है कि रिलायंस की सालाना कच्चा तेल जरूरत का 40 फीसद हिस्सा अरैमको से आएगा। यह मात्रा सऊदी अरैमको को मिली हिस्सेदारी के अनुपात में बहुत बहुत ज्यादा है। अरैमको अतीत में रिलायंस की 20 फीसद जरूरत की आपूर्ति करती रही है। गेल्डर का कहना था कि भारतीय बाजार में अरैमको की दिलचस्पी पिछले कुछ समय से बरकरार है, और बढ़ ही रही है।

रिलायंस के ऑयल और केमिकल कारोबार में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स शाखाओं के अलावा ऑयल मार्केटिंग शाखा में 51 फीसद हिस्सेदारी शामिल हैं। ऑयल मार्केटिंग शाखा की बाकी 49 फीसद हिस्सेदारी रिलायंस ने ब्रिटेन की दिग्गज ऑयल कंपनी बीपी पीएलसी के हाथों 7,000 करोड़ रुपये में बेच ली है।

सांसत

एनबीएफसी को और कर्ज देने से बैंकिंग सेक्टर के लिए जोखिम बढ़ने का अंदेशा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी रिपोर्ट में दी चेतावनी दी

एनबीएफसी को कर्ज देने की हालत में नहीं बैंक

मुंबई, प्रेट्र : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और खुदरा कर्जदारों को कर्ज बढ़ाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने से बैंकिंग सेक्टर पर दबाव खासा बढ़ने की आशंका है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी एक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है।

इस महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने नकदी संकट से जूझ रही एनबीएफसी को बैंकों की तरफ से और कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर तीन बड़े कदम उठाए। इनमें बैंकों को किसी एक एनबीएफसी के लिए कर्ज की सीमा टियर-1 पूंजी (शेयर पूंजी और बची हुई कमाई) के मौजूदा 15 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद करना, कृषि, छोटी इकाइयों तथा मकान खरीदारों के लिए कर्ज को लेकर एनबीएफआइ को कर्ज प्राथमिक श्रेणी में रखना शामिल हैं। साथ ही उपभोक्ता कर्ज (क्रेडिट कार्ड को छोड़कर) के लिए जोखिम भारांश 125 फीसद से कम कर 100 फीसद किया गया है।

वैश्विक चलन के विपरीत : रिपोर्ट के अनुसार, एनबीएफसी को अधिक कर्ज देने के लिए बैंकों को बार-बार प्रेरित करना वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत है। इसके जरिये बैंकों तथा एनबीएफसी के बीच जो एक जुड़ाव है, प्राधिकरण उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे वर्तमान में एनबीएफसी में जो जोखिम है, उसका बैंकों पर सीधा असर पड़ने का खतरा है। एनबीएफसी सेक्टर पर नकदी का बड़ा संकट है, क्योंकि निवेशक फिलहाल इस सेक्टर से दूर रहना ही पसंद कर रहे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) ने पिछले वर्ष से और दीवान हाउजिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) ने इस वर्ष से कर्जदाताओं को भुगतान करने में जिस तरह की अक्षमता दिखानी शुरू की है, उसे देखते हुए निवेशक इस सेक्टर में पूंजी लगाने से परहेज कर रहे हैं।

फिच के अनुसार एनबीएफसी की तरफ से कर्ज वितरण घटने से खपत पर प्रभाव पड़ा है। इसी कारण से जुलाई में वाहनों की बिक्री में पिछले करीब दो दशकों की सबसे बड़ी गिरावट आई। एजेंसी ने कहा, 'अगर बैंक उन्हें और कर्ज देना शुरूकरते हैं, तो इससे एनबीएफआइ (गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों) पर दबाव कम होगा। लेकिन इससे ज्यादा लाभ मजबूत इकाई को मिलने की उम्मीद है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने सरकार को किया आगाह। प्रतीकात्मक

ऐसे बढ़ सकता है जोखिम

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने बुधवार को कहा कि सुस्ती के संकेतों के बीच अर्थव्यवस्था में कर्ज प्रवाह बनाए रखने के इरादे से ये पहल किए गए हैं। एजेंसी ने कहा, 'नरमी में कमी से कर्जदारों को मदद मिलेगी और वित्तीय व्यवस्था में स्थिरता आएगी। लेकिन इन कदमों से बैंकों पर फंसे कर्ज (एनपीए) का जोखिम बहुत बढ़ सकता है।

ढाई लाख फ्लैट्स आठ साल बाद भी अधूरे

▶ 1.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक है ऐसे फ्लैट्स की कीमत

▶ 2011 और उससे पहले बनने शुरू हुए थे यह फ्लैट्स

▶ दिल्ली–एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनियां सबसे बड़ी डिफॉल्टर

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के सात बड़े शहरों में वर्षों पहले बनने शुरू हुए दो लाख बीस हजार से अधिक फ्लैट्स अभी भी अधूरे पड़े हैं। इनकी कुल कीमत 1.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। प्रॉपर्टी कंसलटेंट जेएलएल इंडिया के अनुसार इन घरों का निर्माण कार्य अभी रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा पूरा किया जाना बाकी है।

जेएलएल के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनियां इस मामले में सबसे बड़ी डिफॉल्टर साबित हुई हैं। अधूरे पड़े घरों में इनकी हिस्सेदारी करीब 71 फीसद है। वैल्यू के मामले में यह करीब 56 फीसद होती है। सात शहरों दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में 2,18,367 हाउसिंग यूनिट्स निर्माण के विभिन्न चरणों में अधूरे पड़े हुए हैं। इनकी कुल कीमत 1,55,804 करोड़ रुपये है।

जेएलएल की रिपोर्ट के अनुसार करीब दो लाख बीस हजार घरों में से तीस हजार यूनिट्स को तो खत्म ही कर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में 86,824 करोड़ रुपये मूल्य की 1.54 लाख घरों का निर्माण पूरा होने में विलंब हो रहा है। मुंबई में 56,435 करोड़ रुपये लागत वाले 43,449 घर अधूरे पड़े हैं। जेएलएल की रिपोर्ट के अनुसार अकेले एनसीआर और मुंबई में अधूरे पड़े घरों की संख्या 91 फीसद है।

चेन्नई में अधूरे घरों की संख्या 8,131 है, जिनकी कीमत 4,474 करोड़ रुपये है, जबकि बेंगलुरु में 2,768 करोड़ रुपये कीमत के 5,468 घर तथा पुणे में 3,718 करोड़ रुपये कीमत के 4,765 घरों का निर्माण अधूरा पड़ा है। हैदराबाद में 2,095 घरों का निर्माण अधूरा है, जिनकी कीमत करीब 1,297 करोड़ रुपये है। कोलकता में सबसे कम 384 घरों का निर्माण अधूरा है, जिनकी कीमत 288 करोड़ रुपये है।

इस वर्ष अप्रैल में प्रॉपर्टी कंसलटेंट एनारॉक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया थ कि वर्ष 2013 और उससे पूर्व इन सात शहरों में 4.5 करोड़ रुपये की कीमत से शुरू किये गए 5.60 लाख घर अपना तय डिलिवरी के समय से पीछे चल रहे हैं। घर खरीदारों को उनके अपार्टमेंट का कब्जा दिए जाने में विलंब एक मुख्य कारण हॉउसिंग क्षेत्र में मांग की कमी है। लाखों की संख्या में घर खरीदार जेपी, आम्रपाली और यूनिटेक जैसे डेवलपर्स के आवासीय परियोजनाओं में फंसे हुए हैं।

मांग के मुकाबले आपूर्ति अधिक होने से ही अभी कीमतें स्थिर हैं। फाइल

21 लोग घायल हुए और एक की मौत हो गई जापान में क्रोसा तूफान के कारण। इस तूफान ने जापान के दक्षिणी इलाके हिरोशिमा में जमकर तबाही मचाई। तेज बारिश के अलावा 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के कारण सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे टूट गए।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 16 अगस्त 2019

दुनिया भर में भारतीयों ने पूरे उत्साह के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस

बीजिंग, प्रेट्र : दुनिया भर में लाखों भारतीयों ने गुरुवार को पूरे उत्साह और उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर चीन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यूएई, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाइलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ओमान, सिंगापुर, इजरायल, इंडोनेशिया एवं अन्य देशों में भारतीयों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशभक्ति के गीत गाए।

राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशभक्ति के गीत गाए

बीजिंग में भारतीय दूतावास में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी शामिल हुए। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिसरी ने इंडिया हाउस में तिरंगा फहराया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राष्ट्र के नाम संबोधन को पढ़ा।

आस्ट्रेलिया में, कैनबरा में भारतीय उच्चायोग और मेलबर्न, सिडनी और पर्थ में वाणिज्य दूतावास भवनों में आयोजित समारोहों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों ने भाग लिया। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि भारतीय समुदाय आधुनिक, बहुसांस्कृतिक ऑस्ट्रेलिया का एक समृद्ध और जीवंत हिस्सा बन गया है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने पूरे उत्साह से दिवस मनाया। प्रभारी उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रपति का संबोधन पढ़कर सुनाया।

नेपाल में भारतीय दूतावास ने स्थानीय अस्पतालों और विभिन्न चैरिटेबल संस्थाओं को 30 एंबुलेंस सौंपे। भारतीय राजदूत मानजीव सिंह पुरी ने 40 पुस्तकालयों और शैक्षणिक संस्थानों को उपहार में किताबें दीं। उन्होंने तीन वीर नारियों, पांच विधवाओं और दिवंगत जवानों के छह बच्चों को सम्मानित भी किया।

दो दशकों में भारत-अमेरिका मैत्री सामरिक साझेदारी बनी : पोंपियो

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने भारत की जनता को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई दी और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मित्रता दो दशकों में सामरिक साझेदारी में तब्दील हुई है। रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं।

लंदन में गुरुवार को भारतीयों ने देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर शानदार जश्न मनाया। इस मौके पर लोगों ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर तिरंगा लहराते हुए खुशी का इजहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को जमकर सराहा। वहीं, पाकिस्थान स्थित भारतीय उच्चायोग में भी तिरंगा फहराया गया। रायटर

दुनिया भर के नेताओं ने प्रधानमंत्री को दीं शुभकामनाएं

नई दिल्ली : दुनिया भर के नेताओं ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दीं। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मुहम्मद सोलिह, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, भूटान के प्रधानमंत्री लोटय त्शेरिंग सबसे पहले शुभकामना देने वालों में शामिल हैं। मोदी ने सभी को धन्यवाद दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्विटर पर मोदी के साथ मुलाकात की वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है मेरे मित्र मोदी और भारत की जनता। नमस्ते! स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना देते हुए कहा है कि देश ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

बाज नहीं आया पाकिस्तान : कश्मीर पर भारत सरकार के कदम से बौखलाए पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी बाज नहीं आया। गुरुवार को देश ने इसके विरोध में काला दिवस मनाया।

म्यांमार के सैन्य इलाके में हमले में 14 लोगों की जान गई

यंगून, एएफपी : म्यांमार में मांडले शहर के पास प्यीन अू ल्वीन स्थित सैन्य इलाके में गुरुवार को सशस्त्र विद्रोहियों के हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है।

विद्रोही संगठन के लड़ाकों द्वारा सेना के प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाकर नजदीक की पहाड़ी से किए गए हमले में सेना के नौ जवान सहित चार पुलिसकर्मी मारे गए। म्यांमार की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल जॉ मिन टुन ने बताया कि विद्रोहियों के हमले में एक आम नागरिक की मौत भी हुई है। उन्होंने बताया कि लड़ाई अभी भी जारी है। लड़ाकों ने हमले में रॉकेट भी दागे हैं। सुरक्षाकर्मियों पर हमले के पीछे म्यांमार में हाल ही में भारी मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है।

हमले की जिम्मेदारी लेते हुए विद्रोही संगठन ताउंग नेशनल लिबरेशन आर्मी (टीएलएनए) ने कहा कि उन्होंने यह हमला सेना की कार्रवाई के बदले में किया है। टीएलएनए के प्रवक्ता ने बताया कि इसे अन्य विद्रोही गुट एमएनडीएए और आराकन आर्मी के साथ मिलकर अंजाम दिया गया।

हांगकांग प्रदर्शन पर चीन ने दी धमकी

हालात ▶ ब्रिटेन में चीन के राजदूत ने कहा, अगर स्थिति और बिगड़ी तो चुप नहीं बैठेंगे

अमेरिका सहित कई देशों ने संयम बरतने की अपील की

▶ चीन ने हांगकांग में दस हफ्तों से जारी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को लेकर दखल के दिए संकेत

▶ हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी क्रम में एयरपोर्ट भी कर दिया था ठप

लंदन, एएफपी : ब्रिटेन में चीन के राजदूत ने कहा कि हांगकांग में स्थिति यदि नियंत्रण से बाहर हुई तो चीन चुप बैठकर देखता नहीं रहेगा। बीजिंग तेजी से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। गुरुवार को हांगकांग में प्रदर्शन और तेज हो गया। खराब होती जा रही स्थिति को देखते हुए अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की सरकारों ने संयम बरतने की अपील की है।

हांगकांग में प्रमुख विपक्षी नेता बेनी ताइ को गुरुवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अस्थिरता पैदा करने के आरोप में वह जेल में बंद थे। हांगकांग सरकार ने आंदोलन पर काबू पाने के प्रयास में यह कदम उठाया है। दस हफ्तों से जारी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सहित प्रमुख वित्तीय संस्थान इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। इसी सप्ताह हवाई अड्डे पर प्रदर्शनकारियों के कब्जा करने से करीब 1000 विमानों की उड़ान रद करनी पड़ी।

टेलीवाइज्ड प्रेस कांफ्रेंस में चीन के राजदूत लिउ शिओमिंग ने कहा, 'यदि स्थिति और बिगड़ी और एसएआर (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) सरकार के नियंत्रण से बाहर रही तो केंद्र सरकार चुप बैठकर देखती नहीं रहेगी। अशांति पर नियंत्रण पाने के लिए हमारे पास पर्याप्त समाधान और पर्याप्त शक्ति है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उचित तरीके से समाधान हो जाएगा। इस बीच हम खराब स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।'

उन्होंने हांगकांग में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध भी किया और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जान्सन सरकार से अत्यंत सतर्कता के साथ मुद्दे का समाधान करने का आग्रह किया। चीन के राजदूत ने कहा, 'मेरा मानना है कि इस देश में कुछ राजनेता अभी भी हांगकांग को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा मानते हैं।'

हांगकांग की सीमा के करीब चीन के सैनिकों ने की परेड: हांगकांग की सीमा से महज सात किलोमीटर की दूरी पर स्थित शेनझेन शहर के एक बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम में गुरुवार को हजारों चीनी सैनिकों ने परेड की। आतंकी हमलों से निपटने के लिए गठित चीन के विशेष सुरक्षा बल पीपुल्स आर्म्ड पुलिस (पीएपी) के जवानों के साथ कई बख्तरबंद वाहन भी इस परेड में देखे गए। माना जा रहा है कि प्रदर्शनों को थामने के लिए चीन सेना का प्रयोग कर सकता है। इससे पहले भी चीन थ्येनआनमन चौक पर इसी तरह सेना का प्रयोग करके लोकतंत्र के समर्थन को दबा चुका है।

हांगकांग की सीमा से सटे शेनझेन शहर में स्पोर्ट्स स्टेडियम के समीप परेड में शामिल चीन की पीपुल्स आर्मी के जवान। रायटर

तुरंत ही मानवीय तरीके से गतिरोध खत्म कर सकते हैं शी : ट्रंप

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शी चिनफिंग हांगकांग में प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक गतिरोध को तुरंत ही मानवीय तरीके से खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति शी समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं। उन्होंने ट्वीट में निजी मुलाकात? लिखा है जिससे लगता है कि वह शी को सीधे मदद देने वाला उपाय बता सकते हैं। ट्रंप ने हांगकांग में चीन के सैनिक हस्तक्षेप की आशंका व्यक्त की है। अमेरिकी खुफिया तंत्र से मिली सूचना के आधार पर ट्रंप ने मंगलवार को कहा था, 'मुझे जानकारी मिली है कि चीन अपनी सेना कभी भी हांगकांग की ओर रवाना कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि सबकुछ शांतिपूर्ण रहेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा और न ही किसी की मौत होगी।'

जिब्राल्टर ने ईरानी तेल टैंकर को मुक्त किया, 24 भारतीय भी हुए रिहा

▶ भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारतीयों के रिहा होने की पुष्टि की है

▶ अमेरिका के हस्तक्षेप के बावजूद जिब्राल्टर की कोर्ट ने सुनाया फैसला

मैड्रिड, एपी/रायटर/प्रेट्र : अमेरिका की आपत्ति को अमान्य करते हुए जिब्राल्टर की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार देर शाम ईरानी सुपर टैंकर ग्रेस वन को छोड़ने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश ईरान के उस शपथ पत्र के दाखिल करने के बाद दिया जिसमें कहा गया था कि टैंकर में भरा तेल सीरिया नहीं भेजा जा रहा था। टैंकर में तैनात कैप्टन समेत सभी 24 भारतीय भी रिहा हो गए हैं। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सभी भारतीयों के रिहा होने की पुष्टि की है। चार और विदेशी कर्मचारी भी रिहा हुए हैं।

इस टैंकर को ब्रिटिश नौसेना के कमांडो ने चार जुलाई को अपने उपनिवेश जिब्राल्टर के करीब कब्जे में लिया था। यह टैंकर कच्चा तेल लेकर सीरिया के रास्ते पर था। सीरिया से कारोबार पर लगे प्रतिबंधों के चलते इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना गया था। गुरुवार को दिन में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उसे छोड़े जाने का आदेश दे दिया था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने कहा, यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को तोड़ने का मामला है इसलिए जिब्राल्टर ईरानी टैंकर को न छोड़े। सीरिया को तेल आपूर्ति करने पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगा रखा है तो ईरान के तेल की खरीद-बिक्री पर अमेरिका ने रोक लगा रखी है।

इसके बाद जिब्राल्टर की सुप्रीम कोर्ट ने शाम को एक बार फिर मामले की सुनवाई की। इस दौरान अमेरिका की ओर से टैंकर को न छोड़े जाने के लिए कोई लिखित दलील प्रस्तुत नहीं हुई, इसलिए कोर्ट ने टैंकर को छोड़ने का अपना पूर्व फैसला बरकरार रखा। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद जिब्राल्टर की पुलिस ने ग्रेस वन और उस पर मौजूद सभी लोगों को मुक्त कर दिया।

इस टैंकर में 21 लाख बैरल कच्चा तेल भरा हुआ है। ग्रेस वन को पकड़े जाने के जवाब में 19 जुलाई को ईरान ने ब्रिटिश झंडे वाले मालवाही जहाज स्टेना इंपेरो को होर्मुज स्ट्रेट में कब्जे में ले लिया। माना जा रहा है कि ग्रेस वन को छोड़े जाने के बाद स्टेना इंपेरो को ईरान छोड़ देगा।

जिब्राल्टर के समुद्र में खड़ा ईरान का जब्त तेल टैंकर। अब इसे रिहा किया जा चुका है। एपी

पुलिस ने कहा, सभी भारतीय आरोप मुक्त

ग्रेस वन के भारतीय कैप्टन ने बयान जारी कर सभी साथियों सहित अपनी रिहाई में सहयोग देने वालों का आभार जताया। जिब्राल्टर सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि टैंकर के चालक दल के भारतीय व अन्य देशों सदस्यों के खिलाफ पुलिस प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। पनामा के झंडे वाले इस ईरानी टैंकर पर भारत के अतिरिक्त रूस, फिलीपींस और लातविया के नागरिक भी कार्यरत हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध में समर्पण की 74वीं वर्षगांठ

द्वितीय विश्वयुद्ध में जापानी सेना के समर्पण की 74 वीं वर्षगांठ पर राजधानी टोक्यो में मेमोरियल सर्विस सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान पर श्रद्धांजलि देते जापान के सम्राट नारुहितो और महारानी मसाको। रायटर

रूस में पायलट ने खेत में विमान उतार बचाईं 233 जानें

▶ पक्षियों का झुंड टकराने से फेल हो गया विमान का इंजन, साहस और समझदारी दिखाने वाले पायलट की हर तरफ सराहना

मास्को, रायटर : रूस के विमान में सवार यात्रियों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके विमान से उड़ान भरते ही पक्षियों का झुंड टकरा गया। विमान के दोनों इंजन में खराबी आ गई। विमान को आगे ले जाना संभव नहीं था। पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। आनन-फानन में विमान को पायलट ने साहस के साथ मक्के के खेत में ही उतार दिया। पायलट ने इतनी समझदारी से इस पूरे काम को अंजाम दिया कि किसी भी तरह की दुर्घटना की स्थिति नहीं पैदा हुई। पायलट की हर तरफ सराहना हो रही है। उसे हीरो बताया जा रहा है। रूसी सरकार ने उसे सम्मानित करने का फैसला किया है। विमान में 226 यात्री और चालक दल के सात सदस्य सवार थे।

रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक विमान में सवार 17 बच्चे समेत 55 लोगों को मामलू चोट आई थी। लेकिन किसी भी यात्री की मौत की खबर नहीं है। घायल यात्रियों में से भी एक को छोड़कर सभी को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यूराल एयरलाइंस के विमान एयरबस 321 ने मॉस्को झुकोवस्की इंटरनैशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी।

रूस के सरकारी टेलिविजन ने भी इस घटना को चमत्कार बताया है। रूस की मीडिया ने पायलट दामिर युसुपोव को 'हीरो' बताते हुए कहा है कि उन्होंने 233 जिंदगियों को बचा लिया। रूस के एक अखबार ने लिखा, 'इंजन फेल होने की स्थिति में पायलट ने मक्के के खेत में विमान को सूझबूझ से उतारा।'

इस घटना की तुलना लोग 2009 में अमेरिका के एक विमान की आपातकालीन लैंडिंग से कर रहे हैं। तब विमान से पक्षियों के टकराने के चलते हडसन नदी के किनारे ही पायलट ने विमान को उतार दिया था। इस हादसे पर 'सूली' नामक फिल्म भी बनी थी, जिसमें टॉम हाक ने मूख्य भूमिका निभाई थी।

रूसी उड्डयन मंत्रालय की प्रवक्ता एलेना मिखेयेवा ने कहा कि इंजन बंद हो गया था और फिर उसके बाद पायलट ने किसी तरह से इमरजेंसी लैंडिंग को अंजाम दिया।

पक्षियों से टकराने के बाद रूस की एयरलाइंस के ए 321 विमान की मक्के के खेत में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। इस विमान में 226 यात्री समेत चालक दल के सात सदस्य सवार थे। एपी

उड़ान भरते ही हिचकोले लेने लगा था विमान

एक यात्री ने नाम उजागर न करते हुए बताया कि टेक ऑफ करने के बाद से ही विमान बुरी तरह से हिचकोले लेने लगा था। इसके पांच सेकेंड बाद ही विमान में दाहिनी तरफ की लाइटें जलने-बुझने लगी। जलने की दुर्गंध भी आने लगी और उसके तुरंत बाद विमान रूक गया और आपात दरवाजे से सभी लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया।

पायलट ने बंद कर दिया था इंजन

एयरलाइन के मुताबिक विमान में 16 टन ईंधन भरा था। मुश्किल से पांच सौ लीटर ईंधन ही जला था। ऐसे में विमान में आग लगने की आशंका थी, लेकिन पायलट ने समझदारी दिखाते हुए विमान के दोनों इंजन बंद कर दिए, ताकि आग की घटना को टाला जा सके।

अमेरिका के फिलाडेल्फिया में गोलीबारी में छह पुलिसकर्मी घायल

वॉशिंगटन, प्रेट्र : उत्तरी फिलाडेल्फिया में गोलीबारी की घटना में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि हमलावर अब भी एक मकान में छिपा हुआ है और वहीं से गोलियां चला रहा है।

व्हाइट हाउस की प्रधान उप प्रेस सचिव होगन गिडले ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालात पर नजर रखे हुए हैं। यह घटना अल पासो और डेटन में 24 घंटे के भीतर हुई गोलीबारी की घटनाओं के बाद हुई है, जिनमें 30 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।

फिलाडेल्फिया पुलिस विभाग (पीपीडी) के प्रवक्ता एरिक ग्रीप ने बताया कि छह पीपीडी अधिकारियों को अस्पताल इलाके में गोली मारी गई। हालांकि, सभी खतरे से बाहर हैं। अधिकारी हमलावर को आत्मसमर्पण के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह काम बिना हिंसा की हो जाएगी।

पुलिस आयुक्त रिचर्ड रोस ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमलावर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मालूम हो कि अमेरिका में गन कल्चर से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर साल इसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।

भारत के साथ द्विपक्षीय तरीके से विवाद सुलझाए पाक : रूस

मास्को, एएनआइ : रूस ने पाकिस्तान को साफ तौर पर बता दिया है कि भारत के साथ राजनीतिक व कूटनीतिक माध्यम से द्विपक्षीय बातचीत के जरिए कश्मीर मसले को सुलझाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से फोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों के बीच बातचीत में दक्षिण एशिया के हालात पर चर्चा हुई। रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने पर जोर दिया। लावरोव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों आपसी विवादों का द्विपक्षीय बातचीत से समाधान करें। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान दुनिया के देशों से संपर्क साध रहा है। उसी कड़ी में कुरैशी ने अपने रूसी समकक्ष को बुधवार को फोन किया था। इससे पहले, रूस ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को भारत के संविधान के ढांचे में बताया था।

ब्रिटेन ने भारत को सौंपीं चोरी हुई मूर्तियां

लंदन, प्रेट्र : भारत से वर्षों पहले चोरी हुई दो प्राचीन कलाकृतियों को अमेरिका-ब्रिटेन की एक संयुक्त टीम ने खोज निकाला। खुशी का मौका उस समय आया जब लंदन में भारतीय उच्चायोग में 73वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। दोनों कलाकृतियां भारत को सौंप दी गई हैं।

इन कलाकृतियों में से एक आंध्र प्रदेश की है और यह चूनापत्थर से बनी हुई ईसा पूर्व से एक शताब्दी पहले या एक शताब्दी बाद की हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु की कांसे की कलाकृति 'नवनीत कृष्ण' है। यह 17वीं शताब्दी की है। इन दोनों कलाकृतियों को ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त रुची घनश्याम को सौंप दिया गया। घनश्याम ने कहा, 'चूनापत्थर वाली कलाकृति करीब 2,000 साल पुरानी है और कृष्ण की कांसे की प्रतिमा 300 साल पुरानी है। हम इन कलाकृतियों की कीमत नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह अमूल्य है।

इन कलाकृतियों को भारत सौंपा जाना ब्रिटेन और अमेरिकी एजेंसियों का दोस्ताना व्यवहार है।' दुनिया के सबसे बदनाम तस्कर सुभाष कपूर ने कलाकृतियां तस्करी की थीं। न्यूयार्क में हाल ही में अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा जांच अभियान के तहत कपूर को आरोपित किया गया है। ब्रिटेन के एक आदमी ने जांच दल को कलाकृतियां सौंपने की इच्छा जताई थी। अधिकारियों ने उसका नाम जाहिर नहीं किया है।

भारत की आजादी की 73वीं वर्षगांठ के मौके पर ब्रिटेन ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को वर्षों पहले भारत से चुराई गईं दो प्राचीन कलाकृतियां सौंपीं। प्रेट्र

भारत ने चीन को बताया आंतरिक मामला

▶ प्रथम पृष्ठ का शेष

विदेश मंत्री एस जयशंकर फाइल

बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात में स्पष्ट किया था कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का फैसला भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा था कि यह बदलाव बेहतर प्रशासन और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए है एवं फैसले का असर भारत की सीमाओं और चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर नहीं पड़ेगा।

मलेशिया में भड़काऊ बयान पर जाकिर नाइक को नोटिस

▶ मलेशिया के अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में की थी टिप्पणी

▶ भारत में नफरत फैलाने और मनी लांड्रिंग करने का आरोपित है जाकिर

क्वालालंपुर, रायटर : मलेशिया के प्रशासन ने भारतीय इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को उनके देश के बारे में भड़काऊ बयानबाजी करने पर पूछताछ के लिए समन भेजा है।

मलेशिया सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के कुछ मंत्रियों ने विगत बुधवार को नाइक को बर्खास्त करने की मांग की थी। दरअसल भारत में नफरत फैलाने और मनी लांड्रिंग करने के आरोपित जाकिर नाइक ने मलेशिया में भी कहा कि मलेशिया के हिंदुओं के पास भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों से सौ गुना अधिक अधिकार हैं। पिछले तीन साल से मलेशिया में रह रहे नाइक ने नफरत फैलाने वाला भाषण देकर मलेशियाई सरकार को भी नाराज कर दिया है। मलेशिया मुस्लिम बहुल देश है।

मलेशिया के गृह मंत्री मुहिद्दीन यासिन ने बताया कि पुलिस नाइक और कुछ और लोगों से इस संबंध में पूछताछ करेगी। उन पर लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए झूठी खबरें प्रचारित करने का आरोप है। मुहिद्दीन ने कहा कि हम गैर नागरिकों समेत देश के सभी राजनीतिक दलों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि जन सद्भावना और शांति को भंग करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि धर्म के मुद्दे मलेशिया में संवेदनशील माने जाते हैं। यहां मलय मुसलमान कुल आबादी का साठ फीसद हैं।

जाकिर नाइक। फाइल फोटो

कोहली के शतक की बदौलत जीती सीरीज

अय्यर ने लगाया सीरीज में दूसरा अर्धशतक, टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज को 2–0 से हराया

पोर्ट ऑफ स्पेन, प्रेट्र : कप्तान विराट कोहली (नाबाद 114) और श्रेयस अय्यर (65) की पारियों के दम पर भारत ने बुधवार देर रात खेले गए बारिश से बाधित तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को छह विकेट से मात दे तीन मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। बारिश के कारण मैच 35-35 ओवर का कर दिया गया था। विंडीज ने 35 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाए। भारत को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 255 रनों का लक्ष्य मिला। इस लक्ष्य को भारत ने 32.3 ओवरों में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। शतकवीर विराट को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

भारत ने लगातार 9वीं बार जीती वनडे सीरीज : यह नौवां मौका है, जब भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार वनडे सीरीज अपने नाम की है। भारत के खिलाफ आखिरी बार विंडीज 2006 में जीता था। उसके बाद से लगातार उसे हार ही मिलती आ रही है। कोहली का यह इस सीरीज में लगातार दूसरा शतक है। उन्होंने दूसरे मैच में भी शतक जमाया था। पहला मैच बारिश के कारण रद हो गया था और दूसरे मैच में भारत को जीत मिली थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत ने अपना पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में 25 के कुल स्कोर पर खोया। रोहित 10 रन बनाकर रन आउट हो गए। शिखर धवन ने 36 रनों की पारी खेली और कप्तान के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी की। 91 के कुल स्कोर पर धवन को फेबियान एलेन ने आउट किया। रिषभ पंत अगली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद कोहली और अय्यर ने चौथे विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। केमार रोच ने 212 के कुल स्कोर पर अय्यर की 41 गेंदों की पारी को समाप्त किया, लेकिन तब तक अय्यर अपना काम कर चुके थे। केदार जाधव ने नाबाद 19 रन बनाए कोहली के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई। कोहली ने अपनी पारी में 99 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौके लगाए।

इससे पहले, विंडीज ने क्रिस गेल के 72 और बाकी के बल्लेबाजों के संयुक्त प्रदर्शन से एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। गेल ने 41 गेंदों पर आठ चौके और पांच छक्कों की मदद से अर्धशतकीय पारी खेली। उनके अलावा इविन लुइस विंडीज के दूसरे सर्वोच्च स्कोरर रहे। लुइस ने 43 रन बनाए। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े। युजवेंद्रा सिंह चहल ने लुइस और खलील अहमद ने गेल को आउट कर भारत को लगातार अंतराल पर दो सफलताएं दिलाईं। 22 ओवर का खेल ही हुआ था कि बारिश आ गई जो काफी देर बाद रुकी और अंपायरों ने इसी कारण मैच के ओवर घटा मैच को 35 ओवर प्रति पारी कर दिया। यहां से विंडीज के लिए शिमरोन हेटमायर ने 25, शाई होप ने 24, पूरन ने 30, कप्तान होल्डर ने 14 और कार्लोस ब्रेथवेट ने 16 रन बना विंडीज को 240 का स्कोर दिया।भारत के लिए खलील ने तीन विकेट लिए। शमी को दो सफलताएं मिलीं।

किसी एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक

खिलाड़ी	शतक	बनाम	पारी
सचिन तेंदुलकर	9	ऑस्ट्रेलिया	70
विराट कोहली	9	वेस्टइंडीज	35
विराट कोहली	8	ऑस्ट्रेलिया	35
विराट कोहली	8	श्रीलंका	46
सचिन तेंदुलकर	8	श्रीलंका	80

कप्तान के तौर पर सर्वाधिक शतक

शतक	खिलाड़ी	देश	पारी
22	रिकी पोंटिंग	ऑस्ट्रेलिया	220
21	विराट कोहली	भारत	76
13	एबी डिविलियर्स	द. अफ्रीका	98
11	सौरव गांगुली	भारत	143

भारत के खिलाफ किसी कैरेबियन के वनडे में सबसे ज्यादा रन

खिलाड़ी	रन
डेसमंड हेंस	1357
क्रिस गेल	1334
शिव नारायण चंद्रपॉल	1319

गेल का विंडीज के लिए रिकॉर्ड

- सबसे ज्यादा 301 वनडे
- सबसे ज्यादा 10480 रन
- सबसे ज्यादा 25 शतक
- सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर (215)
- सबसे ज्यादा 331 छक्के
- सबसे ज्यादा शून्य स्कोर (25)

नोट : गेल के अलावा किसी अन्य देश के खिलाड़ी ने अपने देश के लिए यह रिकॉर्ड नहीं बनाया है

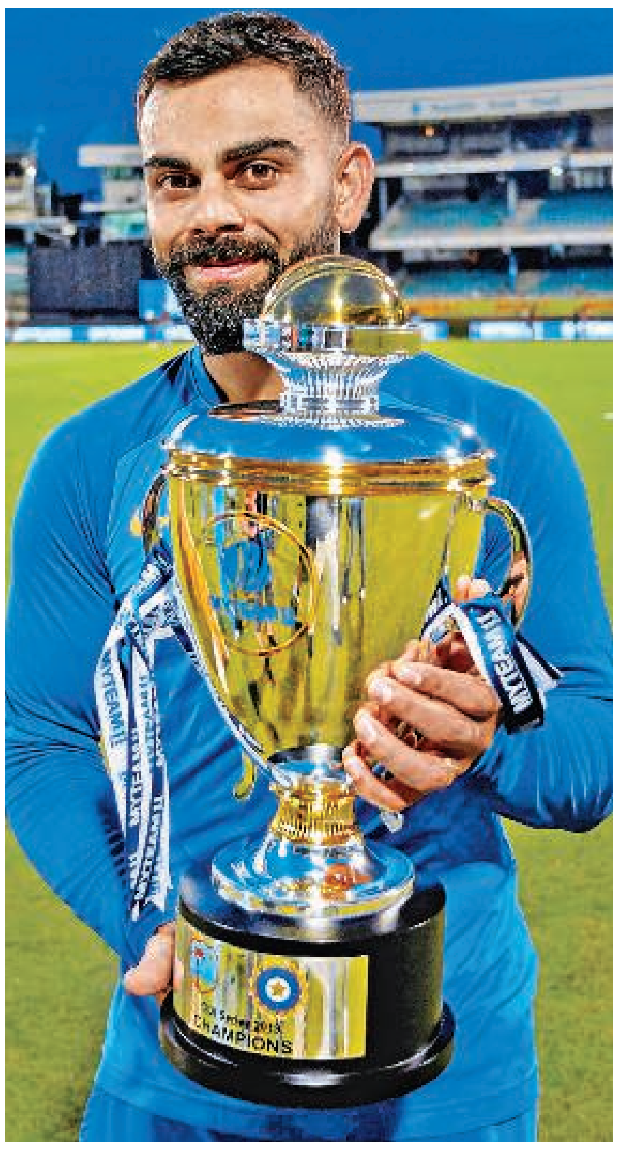

विजेता ट्रॉफी के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली ● एएफपी

एक दशक में 20000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट

नई दिल्ली : भारतीय कप्तान विराट कोहली 10 वर्षों में 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। एक दशक में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में कोहली के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (18,962) का नंबर आता है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस 16,777 रनों के साथ इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं। इसके बाद क्रमश : महेला जयवर्धने (16,304), कुमार संगकारा (15,999), सचिन तेंदुलकर (15,962), राहुल द्रविड़ (15,853) और हाशिम आमला (15,185) का नंबर आता है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार नौवीं वनडे सीरीज भारत ने जीती

विजय	कहां	वर्ष
3–1	भारत में	2006/07
2–1	वेस्टइंडीज में	2009
3–2	वेस्टइंडीज में	2011
4–1	भारत में	2011/12
2–1	भारत में	2013/14
2–1	भारत में	2014/15
3–1	वेस्टइंडीज में	2017
3–1	भारत में	2018/19
2–0	वेस्टइंडीज में	2019

एक वर्ष में वनडे में सर्वाधिक छक्के

खिलाड़ी	वर्ष	छक्के
एबी डिविलियर्स	2015	58
क्रिस गेल	2019	56
शाहिद अफरीदी	2002	48

04 शतक विराट ने कैरेबियाई धरती पर लगाए। वह ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन, दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला और इंग्लैंड के जो रूट को पीछे छोड़ दिया। इन तीनों बल्लेबाजों के नाम 3-3 शतक दर्ज हैं

43 शतक वनडे में भारतीय कप्तान विराट कोहली के पूरे हो गए। वह वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में सचिन से सिर्फ छह शतक पीछे हैं। सचिन के नाम वनडे में 49 शतक हैं

2007 में भारतीय टीम पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क स्टेडियम में श्रीलंकाई टीम के खिलाफ पिछला मैच हारी थी, जबकि वेस्टइंडीज की टीम 2008 में श्रीलंकाई टीम के खिलाफ यहां पिछला वनडे जीती थी

भारतीय क्रिकेटरों ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेटरों ने गुरुवार को देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बीसीसीआइ ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें विराट कोहली, रोहित, जाधव, जडेजा, अय्यर, खलील, चहल, कुलदीप और कोच रवि शास्त्री भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते दिख रहे हैं। कोहली ने कहा कि यह दिन हमारे देश के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित दिन है।

मैंने संन्यास लेने की घोषणा नहीं की : गेल

पोर्ट ऑफ सेन, प्रेट्र : वेस्टइंडीज के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद कहा कि उन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा नहीं की है।

गेल ने मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया। गेल ने कहा कि मैं संन्यास लेने की घोषणा नहीं की है। अगली घोषणा तक मैं टीम के साथ ही बना रहूंगा। मेजबान टीम के कप्तान जेसन होल्डर ने कहा कि मेरे जानकारी के मुताबिक उन्होंने संन्यास नहीं लिया है लेकिन आज उन्होंने जो पारी खेली वह उनके करियर का उदाहरण था, उन्होंने दमदार पारी खेलते हुए हमें शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने हमारा मनोरंजन किया और लोगों ने पिछले कई वर्षों से गेल से यही उम्मीद की है।

कोहली बोले, अय्यर ने दबाव में बेहतरीन बल्लेबाजी की : वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 24 वर्षीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ की। पिछले दो मैचों में मेजबान टीम के खिलाफ 120 और 114 (नाबाद) रन बनाने वाले कोहली को दो बार अय्यर का साथ मिला। उन्होंने अय्यर के साथ 125 और 120 रनों की साझेदारी की। सीरीज जीतने के बाद कोहली ने कहा कि वह इन स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने की कीमत जानते हैं। कोहली ने कहा कि इससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। मैं जब टीम में आया था तो ऐसा ही था, मुझे जो मौके मिलते थे मैं टीम के लिए मैच जीतना चाहता था और स्थिति के अनुसार खेलना चाहता था, आपको जोखिम उठाने पड़ते हैं। उन्होंने दबाव में हिम्मत दिखाई, खुद को पहचानने के लिए आपको अपने खेल को दिखाना पड़ता है। अय्यर ने दो मैचों में 71 और 65 रनों की पारी खेली।

अपनी चोट पर कोहली ने बताया कि वह चोटिल नहीं हुए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में कोहली को हाथ के अंगूठे पर गेंद लगी थी। भारतीय कप्तान को केमार रोच की बाउंसर लगी। उस समय वह काफी दर्द में थे और टीम के फिजियो भी मैदान पर आए। मैच के बाद कोहली ने कहा कि मै नहीं समझता हूं कि मुझे फ्रैक्चर हुआ है क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं अपनी बल्लेबाजी जारी नहीं रख पाता। बस मेरा नाखून थोड़ा कट गया। कोहली ने कहा कि सौभाग्य से यह टूटा नहीं है। जब मुझे चोट लगी थी तब मुझे लगा था कि यह बहुत बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

क्रिस गेल ● एपी

मुश्किल हालात में बल्लेबाजी करना पसंद : अय्यर

पोर्ट ऑफ स्पेन : भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कहा कि उन्हें मुश्किल हालात में बल्लेबाजी करना पसंद है, खास तौर पर उस समय जब सब ड्रेसिंग रूम में 'नर्वस' होते हैं। बुधवार को तीसरे वनडे के बाद अय्यर ने कहा कि मैं बेहद खुश हूं। मैं इस तरह की मुश्किल स्थिति में ही बल्लेबाजी के लिए आना चाहता था जब ड्रेसिंग रूम में सभी नर्वस हों। मुझे यह पसंद है क्योंकि मैच बदल सकता है और टीम की स्थिति में कोई भी बदलाव आ सकता है।' अय्यर ने मजाकिया लहजे में कहा, 'मुझे हमारे गेंदबाज के खिलाफ रन बनाने का बदला लेना था। वह (पूरन) अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन चहल के खिलाफ रन बनाने से मैं गुस्से में था और इसलिए मुझे बदला लेना था।'

पटेल ने कराई न्यूजीलैंड की वापसी

गॉल, रायटर : न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने यहां गुरुवार को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन श्रीलंका के शीर्ष क्रम को झकझोरते हुए ना सिर्फ पांच विकेट झटके, बल्कि मेहमान टीम की मुकाबले में भी वापसी कराई। दिन के पहले सत्र में कीवी टीम 249 रन पर सिमट गई थी, लेकिन पटेल के स्पैल की बदौलत श्रीलंकाई टीम संघर्ष करने पर मजबूर हो गई और दिन का खेल समाप्त होने तक उसने सात विकेट पर 227 रन बनाए थे और वह अभी भी न्यूजीलैंड से पहली पारी के आधार पर 22 रन पीछे है।

स्पिन के अनुकूल हालात में पटेल के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आने से पहले सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने (39) और लाहिरु थिरिमाने (10) ने ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी के तेज गेंदबाजी आक्रमण का धैर्य के साथ सामना किया। 76 रन देकर पांच विकेट लेने वाले भारत में जन्मे बायें हाथ के स्पिनर पटेल ने अपने पहले ही ओवर में थिरिमाने को स्टंप आउट कराया। उनका अगला शिकार करुणारत्ने बने जो उसी तरह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, जिससे स्कोर दो विकेट पर 66 रन हो गया। कुशल मेंडिस (53) और एंजेलो मैथ्यूज (50) ने तीसरे विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी की। चायकाल से ठीक पहले मेंडिस ने अपना 10वां अर्धशतक पूरा किया, लेकिन पटेल की अगली ही गेंद पर वह विकेट गंवा बैठे।

श्रीलंका का मध्य क्रम लड़खड़ा गया और इस दौरान उसके तीन बल्लेबाज सिर्फ छह रन जोड़कर चलते बने। इसके बाद विकेटकीपर निरोशन डिकवेला (नाबाद 39) और सुरंगा लकमल (नाबाद 28) ने आठवें विकेट के लिए 66 रन की अटूट साझेदारी कर अपनी टीम की वापसी कराने की कोशिश की।

इससे पहले बुधवार को 86 रन पर नाबाद लौटने वाले रॉस टेलर गुरुवार को अपनी पहली ही गेंद पर विकेट गंवा बैठे। तेज गेंदबाज लकमल ने उनका विकेट लेकर उन्हें 19वें शतक से वंचित कर दिया। पहले दिन अकिला धनंजय ने पांच विकेट झटके थे, लेकिन दूसरे दिन लकमल (4/29) ने निचले क्रम को ध्वस्त करने में देर नहीं लगाई।

विकेट लेने के बाद खुश एजाज पटेल ● एपी

पहला टेस्ट

- एजाज पटेल ने 76 रन देकर पांच विकेट हासिल किए
- श्रीलंका ने 227 रन पर गंवा दिए सात विकेट

संक्षिप्त स्कोर

न्यूजीलैंड (पहली पारी) : 249
रॉस टेलर : 86
अकिला धनंजय : (5/80)
श्रीलंका (पहली पारी) : 227/7
कुशल मेंडिस : 53
एजाज पटेल : 5/76

युवराज अपवाद, किसी और को नहीं मिलेगी एनओसी

नई दिल्ली, आइएएनएस : बीसीसीआइ ने कनाडा में खेली गई ग्लोबल टी-20 लीग के लिए पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे दिया था। इस मामले को देखकर कई पूर्व खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली थी और उन्हें उम्मीद थी कि अन्य देशों में खेली जा रही लीगों के लिए बोर्ड उन्हें भी एनओसी दे देगा, लेकिन प्रशासकों की समिति (सीओए) का कहना है कि युवराज का मामला अपवाद था और वह किसी और को इस तरह की एनओसी नहीं देगा। सीओए के एक सदस्य ने इस बात की पुष्टि भी की है।

सीओए सदस्य ने कहा कि युवराज का मामला अलग मामला है। वह अपवाद है। हम किसी अन्य खिलाड़ी को विदेशी लीग में खेलने के लिए एनओसी नहीं देंगे। हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है और फैसला लिया है कि इस पर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। सीओए के इस फैसले ने बीसीसीआइ के अधिकारियों को हैरान कर दिया है और कहा है कि फैसलों में निरंतरता होना जरूरी है और एक खिलाड़ी को एनओसी देने के बाद नीति नहीं बदलनी चाहिए। बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि निरंतरता नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन यह इस समय बोर्ड में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऐसा नहीं है। जब खिलाड़ियों और उनके करियर की बात आती है तो मनमाना रवैया नहीं चल सकता। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि वे बोर्ड की नीति में नहीं हैं और ऐसे खिलाड़ी अब संन्यास के बारे में सोच रहे होंगे, ताकि वे विदेशी लीगों में खेल सकें। यह अचानक से लिया गया यू-टर्न उनके लिए बेईमानी है। बीसीसीआइ संन्यास ले चुके अपने पूर्व खिलाड़ियों को विदेशी लीगों में खेलने की अनुमति देने के लिए कभी राजी नहीं होती है, लेकिन सीओए ने युवराज के मामले में उसने एनओसी दे दी, जो एक अपवाद है।

सीओए ने कहा, अब कोई पूर्व क्रिकेटर नहीं ले पाएगा विदेशी लीग में हिस्सा

युवराज सिंह ● फाइल फोटो, ट्विटर

किर्गियोस ने मैच के दौरान तोड़े अपने दो रैकेट

सिनसिनाटी, एएफपी : ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस ने सिनसिनाटी मास्टर्स में दूसरे दौर के मैच के दौरान अपने गुस्से में आकर बदतमीजी की सारी हदें पार कर दीं। किर्गियोस ने मैच के दौरान दो रैकेट तोड़ डाले, अपने जूतों को दर्शकों की ओर फेंका और चेयर अंपायर फर्गस मर्फी के ऊपर थूक भी दिया।

विश्व के 27वें नंबर के खिलाड़ी किर्गियोस को रूस के कारेन खचानोव ने 6-7, 7-6, 6-2 से शिकस्त दी। तीसरे दौर में खचानोव का सामना फ्रांस के लुकास पोइली से होगा। किर्गियोस ने दो सप्ताह पहले ही वाशिंगटन में अपने करियर का छठा एटीपी सिंगल्स खिताब जीता था। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें किर्गियोस चेयर अंपायर से बाथरूम ब्रेक लेकर चले गए। जब वह बाथरूम में पहुंचे तो उन्होंने अपने दोनों रैकेट जमीन पर पटक कर तोड़ दिए। फिर वह वापस कोर्ट पर आ गए। बाथरूम ब्रेक लेने के लिए किर्गियोस ने अंपायर से बहस भी की, जबकि अंपायर ने उन्हें कहा कि तुम अब बाथरूम ब्रेक नहीं मांग सकते। इसके अलावा किर्गियोस दूसरे सेट में तीसरा गेम हारकर अपनी कुर्सी पर बैठने गए तो उसी दौरान उन्होंने अंपायर पर थूक दिया। फिर कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने एक पानी की बोतल उनकी कुर्सी पर तेजी से फेंक दी। इससे पहले किर्गियोस ने कहा था कि वह अपने गुस्से को कम करेंगे और ऐसी चीजें नहीं करेंगे। हालांकि, उन्होंने मैच खत्म होने के बाद अपने एक टूटे हुए रैकेट को एक प्रशंसक को दे दिया। मैच के बाद खचानोव ने कहा, 'वह अच्छा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, लेकिन उसका दिमाग कभी-कभी सही जगह काम नहीं करता है। यह मेरे लिए कड़ा मुकाबला रहा। मेरे लिए ही नहीं, हर किसी के लिए किर्गियोस के खिलाफ खेलना काफी मुश्किल होता है।'

अन्य पुरुष सिंगल्स के मुकाबलों में नौवीं वरीय डेनिल मेदवेदेव ने दूसरे दौर के मुकाबले में फ्रांस के बेनोइट पेरे को 7-6, 6-1 से हरा दिया। वहीं, सर्बिया के मिओमिर केमौनोविक ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को तीन सेट तक चले मुकाबले में 6-7, 6-2, 6-4 से मात दी। इसके अलावा विश्व के पांचवें नंबर के खिलाड़ी जापान के केई निशिकोरी दूसरे दौर के मैच में हमवतन क्वालीफायर योशिहितो निशियोका से सीधे सेटों में 6-7, 4-6 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

निक किर्गियोस ● एएफपी

सिनसिनाटी मास्टर्स

- किर्गियोस ने दर्शकों की ओर फेंका जूता, चेयर अंपायर पर थूका
- निक को खचानोव ने 6–7, 7–6, 6–2 से शिकस्त दी

फुटबॉल लिवरपूल ने फाइनल मुकाबले में चेल्सी को पेनाल्टी शूटआउट में 5–4 से दी शिकस्त

लिवरपूल ने जीता सुपर कप का खिताब

इस्तांबुल (तुर्की), एएफपी : चैंपियंस लीग विजेता लिवरपूल ने पेनाल्टी शूटआउट तक गए मुकाबले में चेल्सी को 5-4 से मात देकर सुपर कप का खिताब अपने नाम किया। दो इंग्लिश क्लबों के बीच यह मैच निर्धारित समय तक 2-2 से बराबर रहा और इसके बाद अतिरिक्त समय भी दोनों टीमों के बीच यही स्कोर रहा। मैच का नतीजा निकालने के लिए पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया, जहां लिवरपूल की टीम ने बाजी मारी।

लिवरपूल ने अपने इतिहास में चौथी बार सुपर का खिताब जीता है, जबकि चेल्सी को लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में हार झेलनी पड़ी। केवल बार्सिलोना (05) और एसी मिलान (05) ने ही लिवरपूल से अधिक सुपर कप खिताब जीते हैं। चेल्सी को इससे पहले साल 2012 और 2013 में सुपर कप के फाइनल में हार झेलनी पड़ी थी।

लिवरपूल के खिलाफ पहला हाफ चेल्सी के नाम रहा। यूरोपा लीग विजेता ने चैंपियंस लीग विजेता को पहले हाफ में लगातार परेशान किया। चोट के बाद वापसी कर रहे मिडफील्डर एंगोलो कांते ने दमदार प्रदर्शन किया और मिडफील्ड में चेल्सी का पलड़ा भारी रहा। मैच के 36वें मिनट में क्रिस्टियन पुलिसिक ने 18 यार्ड बॉक्स में शानदार पास दिया और स्ट्राइकर ओलिवर गिरोड ने गोल करते हुए चेल्सी को बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही लिवरपूल की टीम वापसी करने में कामयाब रही। 48वें मिनट में सादियो माने ने गोल करते हुए अपनी टीम को बराबरी दिला दी। हालांकि, इसके बाद चेल्सी ने मैच पर दोबारा अपना दबदबा बना लिया। बीच-बीच में लिवरपूल को भी गोल करने के मौके मिले, लेकिन टीम कामयाब नहीं हो पाई। अतिरिक्त समय में लिवरपूल का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आया। 95वें मिनट में माने ने बॉक्स में से शानदार गोल करते हुए टीम को आगे कर दिया। इसके बाद जल्द ही लिवरपूल के खिलाड़ी गलती कर बैठे और चेल्सी को पेनाल्टी मिल गई। चेल्सी ने 101वें मिनट में वापसी की। जॉर्जिनियो ने पेनाल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 2-2 कर दिया।

एड्रियन ने बचाया गोल : पेनाल्टी शूटआउट में लिवरपूल के पांचों खिलाड़ियों ने गेंद को गोल पोस्ट में डाला, जबकि चेल्सी की ओर से स्ट्राइकर टेमी अब्राहम गोल करने से चूक गए। उन्होंने दायें पैर से गेंद पर किक लगाई और लिवरपूल के गोलकीपर एड्रियन सैन मिगुएल ने इस पेनाल्टी का बचाव करके लिवरपूल को जीत दिलाई। स्पेनिश गोलकीपर एड्रियन के लिए यह यादगार पल है क्योंकि वह नौ दिन पहले ही क्लब से जुड़े हैं। उन्हें नियमित गोलकीपर एलिसन बेकर की जगह शामिल किया गया था, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैच में चोटिल हो गए थे। एड्रियन वेस्ट हम क्लब से लिवरपूल के साथ जुड़े हैं।

खिताब जीतने के बाद जश्न मनाते लिवरपूल के खिलाड़ी ● रायटर

महिला रेफरी फ्रापार्ट की हुई तारीफ

इस्तांबुल, एएफपी : स्टेफनी फ्रापार्ट सुपर कप मुकाबले में रेफरी बनीं और मैच के बाद उनके काम की खूब प्रशंसा हुई। फ्रापार्ट पुरुषों के किसी प्रमुख यूरापीय मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला हैं। मैच के दौरान उन्होंने कुल तीन यलो कार्ड दिखाए और मुकाबले को बीच–बीच में ज्यादा नहीं रोका। फ्रापार्ट के साथ इटली की मैनुएला निकोलोसी और आयरलैंड की मिशेल ओ नील भी मैच अधिकारी थीं। चेल्सी के पूर्व खिलाड़ी जोए कोल ने फ्रापार्ट की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं समझता हूं कि उनके लिए यह मैच शानदार रहा। एक मुश्किल मैच में उन्होंने शानदार तरीके से अपना काम किया। फ्रापार्ट ने शानदार काम किया। उन्होंने मैच को अधिक रोका नहीं और उनके अधिकतर निर्णय सही रहे।'

मुझे लगता है कि टीम और भी अच्छा कर सकती थी। हमें अपने खेल में सुधार करने की जरूरत है। हार हमेशा से टीम को निराश करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चेल्सी का प्रदर्शन पूरे सत्र में ऐसा ही रहेगा। हम आगे इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
फ्रैंक लैंपार्ड, मैनेजर, चेल्सी

मैं टीम के लिए खुश हूं। यह बहुत लंबा मैच रहा, लेकिन आखिरकार नतीजा हमारे पक्ष में आया।
एड्रियन सैन मिगुएल, गोलकीपर, लिवरपूल

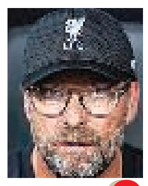

यह मैच दोनों टीमों के लिए काफी मुश्किल रहा, लेकिन मेरी टीम ने ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पेनाल्टी शूटआउट में हमेशा किस्मत का भी साथ चाहिए और पूरे मैच में टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा। एड्रियन ने शूटआउट में गोल का अच्छा बचाव किया।
जुर्जेन क्लोप, मैनेजर, लिवरपूल

ओसाका जीतीं, शारापोवा बाहर

हार के बाद निराश मारिया शारापोवा ● एएफपी

सिनसिनाटी : विश्व की नंबर एक जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने सिनसिनाटी मास्टर्स में बेलारूस की अलेक्सांद्रा सस्नोविक को महिला सिंगल्स के दूसरे दौर के मुकाबले में 7-6, 2-6, 6-2 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने दूसरे दौर में सीधे सेटों में रूसी सुंदरी मारिया शारापोवा को 6-4, 6-1 से आसानी से हरा दिया। अन्य महिला सिंगल्स के मुकाबलों में हालेप ने एकटरीना अजेक्जेंड्रोवा को तीन सेट तक चले मुकाबले में 3-6, 7-5, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। कैरोलिना प्लिस्कोवा ने दूसरे दौर के मैच में चीन की वांग याफान को 6-1, 6-3 से हराया।

साउंड के साथ पहली कलर कार्टून फिल्म रिलीज हुई

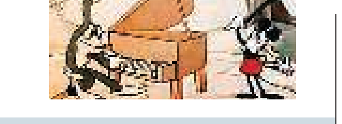

1930 में आज ही रिलीज हुई इस फिल्म का नाम 'फिडलस्टिक्स' था। यह फिल्म 6 मिनट और 12 सेकंड अवधि की थी। इसे अमेरिकी कार्टूनिस्ट यूबी इवेर्क्स ने डायरेक्ट किया था। इवेर्क्स ने वर्ल्ड डिज्नी के साथ मिलकर 1928 में मिक्की माउस की भी रचना की थी।

सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली ने सफलता के गाड़े झंडे

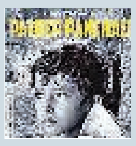

1958 में आज ही प्रसिद्ध बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्म 'पाथेर पांचाली' ने वैंकूवर फिल्म फेस्टिवल में टॉप पांच अवार्ड हासिल कर इतिहास रच दिया। 1.5 लाख रुपये बजट वाली यह फिल्म बिभूतिभूषण बंधोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित थी।

वीर रस की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्मदिन

इनका जन्म 1904 में आज ही इलाहाबाद में हुआ। इनकी दो कविता संग्रह और तीन कथा संग्रह प्रकाशित हुए। 'झांसी की रानी' कविता ने इन्हें प्रसिद्धि के नए मुकाम पर पहुंचाया। 1921 में इन्होंने अपने पति के साथ महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नागपुर की कोर्ट से गिरफ्तार होने वाली ये पहली महिला सत्याग्रही थीं। 1923 और 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते दो बार जेल गईं। 'वीरों का कैसा हो वसंत', 'राखी की चुनौती' और 'वेदा' इनकी प्रमुख कविताएं हैं। 'बिखरे मोती' इनका पहला कहानी संग्रह है। 15 फरवरी, 1948 को 43 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं।

इधर-उधर की

सो कर नहीं उठा पोता तो पुलिस को बुलाया

बैंकॉक, एजेंसी: आमतौर पर लोग पुलिस को किसी घटना या हादसा होने पर बुलाते हैं, लेकिन थाईलैंड में परीक्षा देने के लिए पोता सो कर नहीं उठा तो इससे परेशान होकर दादी ने पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने लड़के को जगाया और पढ़ाई के बारे में समझाया। फिर दादी ने दादी ने पोते को परीक्षा के लिए तैयार किया। साथ में नया पेन भी दिया। पुलिसकर्मी ने लड़के को अपने स्कूटर पर बिठाया और उसे स्कूल तक छोड़ने गया। इस घटना को थाईलैंड पुलिस ने फेसबुक पेज पर शेयर किया है।

नई खोज ▸ आइआइटी, एनआइटी के शोधकर्ताओं ने विकसित की प्रक्रिया

अब अंडे के छिलके से जुड़ेंगी हड्डियां

ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट को बनाने का प्राकृतिकस्रोत है अंडे का छिलका

हैदराबाद, प्रेट्र : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आइआइटी) हैदराबाद और डॉ. बीआर आंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआइटी) जालंधर के शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने अंडे के छिलके से हड्डी का इंप्लांट बनाने की प्रक्रिया विकसित की है। शोधार्थियों ने बताया कि वे हड्डी की सब्स्टीट्यूट सामग्री जैसे कि ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट (टीसीपी) को बिना किसी जहरीले रसायन का प्रयोग किए प्राकृतिक स्रोत से बनाना चाहते थे।

शोधकर्ताओं ने बताया कि उनकी नजर में सामग्री बनाने के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत अंडे के छिलका था। अंडे के छिलके में अधिकतर कैल्शियम से युक्त मिनरल (95.1 प्रतिशत) होते हैं। इसके साथ ही प्रोटीन और पानी भी होता है।

अंडे के छिलके में 95 फीसद कैल्शियम युक्त मिनरल होते हैं। प्रतीकात्मक

आधुनिक चिकित्सा में हड्डी के टूटने पर या उसे हटाए जाने पर या तो किसी दाता से उसे लिया जाता है या फिर कृत्रिम सामग्री का उपयोग करके बनाया जाता है। कृत्रिम सामग्री जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम फास्फेट आदि हैं।

शोधकर्ताओं के अनुसार अंडे के छिलके से बने बॉयो सेरेमिक में अन्य सेंथेटिक पाउडर के मुकाबले स्वाभाविक रूप से ज्यादा जैव अनुकूलता होती है। अंडे के छिलके में जैव सक्रिय आयन तत्व पाए जाते हैं।

शोधकर्ताओं ने अंडे के छिलकों से ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट (टीसीपी) नैनोपाउडर तैयार किया है। सक्रिय कैल्शियम फॉस्फेट पाउडर के उत्पादन के लिए उन्होंने एक मिलिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जिसे बॉल मिलिंग कहा जाता है। उन्होंने बताया कि अंडे के खोल के कचरे से बनी सामग्री व्यावसायिक रूप से उपलब्ध टीसीपी का स्थान ले सकती है।

▸ इस विधि से हड्डी का इंप्लांट बिना किसी जहरीले रसायन के बनाया जा सकेगा

▸ इससे बने बॉयो सेरेमिक में अन्य सेंथेटिक पाउडर के मुकाबले ज्यादा जैव अनुकूलता होती है

भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया मजबूत पकड़ वाला रोबोट

चेन्नई, आइएएनएस: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आइआइटी) मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक नया मल्टीमोडल रोबोटिक सिस्टम तैयार किया है, जिसमें मजबूत पकड़, ज्यादा हरकत करने की क्षमता और ज्यादा लचीलापन है। आइआइटी मद्रास की ओर से कहा गया कि इसका उपयोग कई तरह के क्षेत्रों में किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने इस रोबोटिक सिस्टम को 'ग्रैस्पमैन' नाम दिया है। इसमें एक जोड़ी ग्रैस्पर (पकड़ने वाला यंत्र) लगाए गए हैं। जिसके माध्यम से रोबोट किसी भी ऑब्जेक्ट (वस्तु) को आसानी से पकड़ सकेगा। यह ग्रैस्पर रोबोट में बिल्कुल किसी मनुष्य के हाथ की तरह काम करते हैं। इस शोध का नेतृत्व आइआइटी मद्रास के रोबोटिक्स लेबोरेटरी के प्रोफेसर असोकन थोंडियथ ने किया।

फिल्म रिव्यू

★★★★

बाटला हाउस

निर्देशन: निखिल आडवाणी
प्रमुख कलाकार: जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, मनीष चौधरी
अवधि: 2 घंटे 26 मिनट

पर्दे पर पुलिसकर्मियों की मनोदशा

निखिल आडवाणी निर्देशित फिल्म बाटला हाउस विवादास्पद बाटला हाउस एनकाउंटर पर आधारित है। 19 सितंबर, 2008 को दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में मकान संख्या एल-18 के प्रथम तल पर बने फ्लैट में इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम वहां पहुंची थी। दोनों तरफ से चली गोलियों में एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गए थे, जो इलाज के दौरान शहीद हो गए। उस घटना में दो आतंकी मारे गए थे। पुलिस ने अन्य दो को दबोच लिया और एक फरार हो गया। उस वक्त कुछ राजनेताओं ने एनकाउंटर को फर्जी बताकर विवाद को जन्म दिया था। एनकाउंटर के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसी घटनाक्रम से प्रेरित फिल्म 'बाटला हाउस' में छात्रों और दिल्ली पुलिस के पक्षों को आमने-सामने लाने का प्रयास सराहनीय है। यह एनकाउंटर डीसीपी संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया था। फिल्म में उनकी भूमिका जॉन अब्राहम ने निभाई है। हालांकि फिल्म में किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। जॉन के किरदार का नाम संजय कुमार है।

फिल्म में संजय कुमार की पेशेवर जिंदगी की कठिनाइयों के साथ व्यक्तिगत जीवन में चल रही उथल-पुथल को भी दिखाया गया है। एनकाउंटर के बाद सरकारी दबाव, लोगों की नाराजगी और नकारात्मक मीडिया रिपोर्टों को लेकर उनकी मनोदशा का चित्रण झकझोरता है। लेखक रितेश शाह और निखिल आडवाणी की जोड़ी इससे पहले जासूसी थ्रिलर 'डी डे' की सौगात दे चुकी है। बाटला हाउस में इस जोड़ी ने दोनों पक्षों की दलीलों को तर्कसंगत तरीके से पेश किया है। आतंकियों की मानसिकता को भी सामने लाने का प्रयास हुआ है। फिल्म के एक दृश्य में जॉन पवित्र कुरान की आयतों को पढ़ते हुए उसका अर्थ बताते हैं। घटनाक्रम को विश्वसनीय बनाने के लिए सलमान खुर्शीद, अरविंद केजरीवाल, अमर सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा बाटला प्रकरण पर की गई टिप्पणियों को क्लीपिंग द्वारा दर्शाया गया है। कहानी में रोमांच और थ्रिल बनाए रखने में निखिल-रितेश ने लय कायम रखी है। घटनाक्रम के बाद संजीव कुमार को मानसिक बीमारी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसआर्डर (पीटीएसडी) से पीड़ित होने के बारे में बताया गया है।

सिनेमैटोग्राफर सौमिक मुखर्जी ने एक्शन दृश्यों को सिल्वर स्क्रीन पर समुचित तरीके से उतारा है। उन्होंने भीड़ के बीच फंसने और संकरी गलियों में भागते दृश्यों को पर्दे पर सही तरीके से उतारा है।

देशप्रेम और सत्य घटनाओं से प्रेरित फिल्म 'परमाणुः द स्टोरी ऑफ पोखरण' व 'रोमियो अकबर वाल्टर' की सफलता ने जॉन अब्राहम को ऐसी विषयों पर फिल्म बनाने और अदाकारी दिखाने के अवसर दिए हैं। बाटला हाउस में भी संजय कुमार की जिंदगी के द्वंद्व को उन्होंने बखूबी जिया है। उनका किरदार कम शब्दों और भावों की मदद से अपनी बात कहता है। कहानी के अंत में राह भटके लड़कों और आतंक की पीड़ा को लेकर उनका वक्तव्य याद रह जाता है। मृणाल ठाकुर ने अपनी संक्षिप्त भूमिका के साथ न्याय किया है।

जॉन के बॉस के किरदार में मनीष चौधरी का अंदाज प्रभावित करता है। संक्षिप्त भूमिका में रवि किशन ने शानदार अभिनय किया है। 2004 में आई फिल्म 'मुसाफिर' के गाने 'साकी साकी' के रीमेक में नोरा फतेही पहले ही वाहवाही लूट चुकी हैं। बचाव पक्ष के वकील की भूमिका में राजेश शर्मा थोड़े नाटकीय हो गए हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म सही एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों की मनोदशा का चित्रण करती है, जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

शोध अनुसंधान

वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर की नई दवा तैयार की

वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक (अग्नाशय) कैंसर के इलाज की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने इसकी नई दवा ईजाद की है और शुरुआती प्रयोगों में इसे काफी कारगर पाया गया है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी के जरिये अग्नाशय के कैंसर का इलाज किया जाता है। दोनों ही तरीकों में कैंसर के डीएनए को नुकसान पहुंचाया जाता है। हालांकि अग्नाशय के कैंसर में इस नुकसान को सही करने की क्षमता भी होती है। इस कारण से इलाज का असर सीमित हो जाता है। अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि दवा एजेडडी1775 की मदद से डीएनए की मरम्मत करने की कैंसर की क्षमता को खत्म किया जा सकता है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साथ मरीजों को यह दवा देने से इलाज का असर बढ़ जाता है। आमतौर पर अग्नाशय के कैंसर का शिकार होने के बाद महज नौ प्रतिशत मरीज ही पांच साल से ज्यादा जीवित रह पाते हैं। - एएनआइ

टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बनाता है

टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सप्लीमेंट व्यक्ति को नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। हालिया शोध में यह बात सामने आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस हार्मोन से व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत जटिल है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के वैज्ञानिकों ने इस संबंध में शोध को अंजाम दिया है। शोधकर्ता बरट्रेम गेरोंस्की ने कहा, 'अध्ययन के लिहाज से यह महत्वपूर्ण विषय है कि हार्मोन दिमाग की गतिविधियों में बदलाव करते हुए कैसे भावनाओं को प्रभावित करते हैं।' प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने 100 प्रतिभागियों को टेस्टोस्टेरोन का सप्लीमेंट दिया, जबकि 100 अन्य को प्लेसबो (दवा के नाम पर कोई सामान्य पदार्थ) दिया। इस दौरान आश्चर्यजनक बात यह भी देखी गई कि हार्मोन का सप्लीमेंट लेने वाले लोग ज्यादा संवेदनशील देखे गए। वहीं जिन लोगों में प्राकृतिक तरीके से इस हार्मोन का स्तर ज्यादा होता है, उनमें नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशीलता कम देखी गई। -आइएएनएस

फेसबुक लीक कर रहा आपकी मैसेंजर चैट

सैनफ्रांसिस्को, आइएएनएस : गूगल, एप्पल और अमेजन के बाद अब फेसबुक वह दिग्गज टेक कंपनी है, जो अपने मैसेंजर एप से की गई आपकी बातचीत को सुनने और उसकी पहचान करने के लिए थर्ड-पार्टी कांटैक्टर्स को भुगतान कर रही थी। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने सीएनईटी को बताया, एप्पल और गूगल की तरह ही हमने ऑडियो के समीक्षा को एक हफ्ते पहले ही रोक दिया है। इससे पहले, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में बताया फेसबुक के ऐसे कार्यक्रम के बारे में पहले ही जानकारी दी गई थी। कांट्रैक्टर्स को हालांकि, यह जानकारी नहीं होती है कि उन ऑडियो को कहां रिकॉर्ड किया गया और उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया।

साल 2015 से ही फेसबुक मैसेंजर ने वीडियो क्लिप्स को टेक्ट्स में ट्रांसक्रिब करने के फीचर की पेशकश कर रही थी, हालांकि, यह फीचर बंद भी होता है। रिपोर्ट में कहा गया, 'फेसबुक के प्रभावित यूजर्स ने अपने मैसेंजर सेटिंग्स में अपने वॉयस चैट को ट्रांसक्रिब करने की मंजूरी देने का विकल्प चुना था।' एप्पल, गूगल और अमेजन ने हाल में ही यूजर के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की मनुष्य द्वारा की जाने वाली समीक्षा को रोक दिया है, जब ऐसी रिपोर्टें सामने आईं कि ये कंपनियां यूजर्स की वॉयस रिकॉर्डिंग्स थर्ड पार्टी कांट्रैक्टर्स को सुना रही है। विवादों का सामना करने के बाद गूगल और एप्पल ने भी बातचीत की जासूसी बंद कर दी।

स्पेक्ट्रम

▸ गूगल, एप्पल और अमेजन भी वॉयस रिकॉर्डिंग को थर्ड पार्टी को सुनाती रही हैं

प्रतीकात्मक

फेसबुक में मूवी के विज्ञापनों में अब टिकट वितरण, शोटाइम भी दिखेगा : सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक अब जल्द ही दो नए एड यूनिट शुरू करने जा रही है, जिसमें से एक 'मूवी रिमाइंडर एड' और एक 'मूवी शोटाइम एड' है। इन एड के माध्यम से फेसबुक यह बताएगा कि किसी मूवी का शोटाइम क्या है और उसकी रिलीज डेट क्या है। बताया गया कि लोग अक्सर अपनी पसंदीदा फिल्म की रिलीज के लिए बहुत पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में फेसबुक उन्हें रिमाइंड करेगा।

कीबोर्ड की आवाज से हो सकती है हैकिंग

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : शोधकर्ताओं ने आगाह किया है कि हैकर्स केवल एक स्मार्टफोन से यह पता लगा सकते हैं कि आपने अपने कंप्यूटर में क्या टाइप किया। डलास स्थित सार्दर्न मेथॉडिस्ट यूनिवर्सिटी (एसएमयू) के शोधकर्ताओं ने बताया कि आपके कीबोर्ड की आवाज से हैकर सटीकता से यह पता लगा सकते हैं कि आपने क्या टाइप किया। एसएमयू की टीम ने पाया कि जब हम कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो ध्वनिक संकेत या ध्वनि तरंगे को आसानी से हैकर्स स्मार्टफोन के जरिए पहचान लेते हैं। फोन द्वारा कीबोर्ड की आवाज को एक कुशल हैकर इस तरह से इंटरसेप्ट कर सकता है कि वह यह बता सकता है कि कब कौन सी बटन को दबाया गया। एसएमयू में सहायक प्रोफेसर एरिक सी लार्सन ने बताया कि हैकरों को कीबोर्ड की आवाज का पहचान करने में मात्र कुछ सेकेंड का ही समय लगता है। वे इतने कुशल होते हैं कि शोर भरे वातावरण या किसी ऑफिस में अन्य कीबोर्ड की आवाजों के बीच भी वे अपने लक्ष्य की आवाज को आसानी से पहचान कर गुप्त जानकारी निकाल सकते हैं।

इबोला अब नहीं रहा लाइलाज बीमारी

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली : इबोला को अब लाइलाज बीमारी नहीं कहा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस वायरस से प्रभावित देश कांगो में दो नई दवाओं के परीक्षण के बाद मृत्युदर में बहुत कमी पाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शस डिसीज' की ओर से कहा गया कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित जगहों जैसे- सिएरा लियोन, लाइबेरिया और गुएना में एक बायोफार्मासिटिकल दवा जेडमैप को एंटीवायरल दवा रेमेडिसविर के साथ मिलाकर दिया गया। इसके पहले मरीजों में वायरस को ब्लॉक करने के लिए टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई। इसके बाद पाया गया कि इन दवाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आए।

इन परिणामों के सामने आने के बाद से कांगो में नवंबर से शुरू हुए सभी अन्य परीक्षणों को रोक दिया गया है। अब सभी इबोला उपचार की यूनिट टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करेंगे। कांगो में नेशनल डी रिसर्च बॉयोमेडिकल इंस्टीट्यूट के महानिदेशक प्रो. जीन जैक्स मुइंबे ने कहा, 'अब से हम यह नहीं कह सकेंगे कि इबोला लाइलाज है।' कांगो में अब तक इबोला से संबंधित 2800 मामले सामने आ चुके हैं और यह दुनिया में दूसरा सबसे प्रभावित देश है।

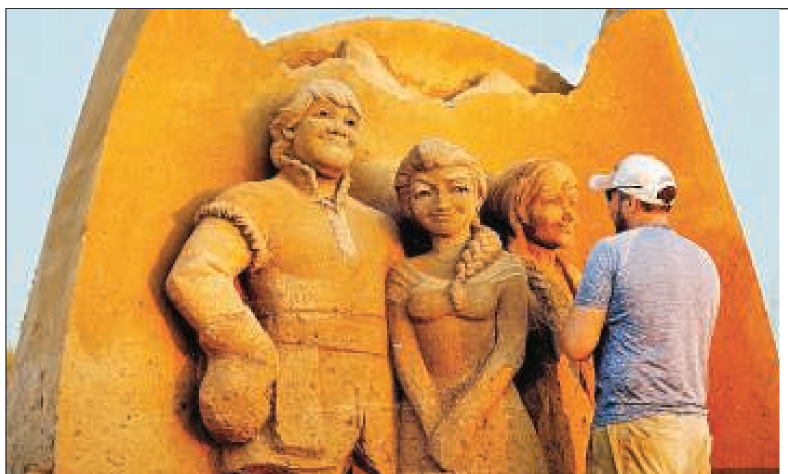

सबसे बड़ा सैंड आर्ट का उत्सव

इजरायल के एस्केलॉन में इंटरनेशनल सैंड स्क्ल्पचर फेस्टिवल पर दुनियाभर के सैंड आर्टिस्ट अपने हुनर का कमाल दिखाते हैं। सैंड आर्ट दुनिया में तेजी से लोकप्रिय होता सशक्त कला का माध्यम है, जिसमें आर्टिस्ट रेत पर एक से बढ़कर एक मूर्त कलाकृतियां तैयार करते हैं। फेस्टिवल में शामिल होने आए रूस के आर्टिस्ट इल्या अपनी कलाकृति को अंतिम रूप दे रहे हैं। रायटर

तिब्बती जीवन शैली का अभिन्न अंग है घुड़दौड़

उत्तर पश्चिम चीन के गासु प्रांत की स्वायत्त गन्नान तिब्बती काउंटी में 12 वीं गेसर हार्स रेसिंग के उद्घाटन अवसर पर करतब दिखाते घुड़सवार। 900 घोड़ों के साथ कुल 52 टीमें छह दिवसीय इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। घुड़दौड़ तिब्बती संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इस काउंटी में 90 प्रतिशत मूलनिवासी तिब्बती हैं जिनकी अब भी पांरपरिक खानाबदोश जीवन शैली है। तिब्बती परंपरा में पूरे वर्ष विभिन्न अवसरों पर घुड़दौड़ उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इनमें नववर्ष का जश्न भी शामिल है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

सुहाना ने शुरू की बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी

सुपरस्टार पिता शाह रुख खान के खास दिशा-निर्देश में सुहाना खान ने बॉलीवुड में अपने पदार्पण की तैयारी शुरू कर दी है। अगर सब कुछ सामान्य और सकारात्मक रहा तो अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर और सारा अली खान के बाद सुहाना भी बॉलीवुड डेब्यू करने वाली स्टार किड्स की सूची में शामिल हो जाएंगी। हाल ही में एक लघु फिल्म में सुहाना के पोस्टर की चर्चा हुई थी। पर, अब वह हिंदी सिनेमा में सक्रिय हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि अपनी तैयारी के तहत सुहाना अपने पिता की फिल्मोग्राफी पर ध्यान दे रही हैं। वह उनकी हर एक फिल्म को गौर से देख रही हैं। हाल ही में एक खबर भी आई थी कि सुहाना 'मन्नत' में स्थित थियेटर में अपने पिता की सारी फिल्में देख रही हैं। इसमें शाह रुख की डेब्यू फिल्म भी शामिल है। गौरतलब है कि शाह रुख खान ने कई वर्षों तक बॉलीवुड पर राज किया है और अब उनकी बेटी भी उनके नक्शेकदम पर चल कर दर्शकों का दिल जीतना चाहती हैं।

कश्मीरी हिंदुओं की अनकही कहानी दिखाएंगे विवेक अग्निहोत्री

फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री आजकल शोध आधारित फिल्मों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पिछले दिनों आई फिल्म 'द ताशकंद फाइल्स' उनकी ऐसी ही एक फिल्म थी। अब वह अपनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' लेकर आए हैं। उनके अनुसार, इस फिल्म का विषय कश्मीरी हिंदुओं पर आधारित है, जिन्हें मारा गया। जिनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें बेघर कर दिया गया।

विवेक की मानें तो इस फिल्म में कश्मीरी हिंदुओं की वह कहानी बताई जाएगी, जो अभी तक अनकही है। इस बारे में विवेक अग्निहोत्री ने बताया, 'मेरा मानना है कि कलाकारों को समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, जहां उनका काम देखा जाता है। यह विश्वास नहीं होता है कि कश्मीर पर फिल्में तो कई बनाई गईं, लेकिन किसी भी फिल्म में वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों के दर्द और नुकसान को नहीं दिखाया गया। 'द कश्मीर फाइल्स' कश्मीरियों के नरसंहार पर आधारित है, जो अगले साल अगस्त में रिलीज होगी।'

'धारा 375' के जरिये बहस कराना चाहते हैं अक्षय खन्ना

लंबे अरसे के बाद अक्षय खन्ना बॉलीवुड फिल्म में नजर आने वाले हैं। वह निर्देशक अजय बहल की फिल्म 'धारा 375' में ऋचा चड्ढा के साथ दिखेंगे। फिल्म की कहानी भारतीय दंड संहिता कानून की धारा 375 पर आधारित है। फिल्म में ऋचा चड्ढा और अक्षय खन्ना दोनों वकील के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी एक दुष्कर्म पीड़िता विदेशी महिला की है, जिसका एक फिल्ममेकर पर आरोप है कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। ऋचा जहां फिल्म में पीड़िता की ओर से केस लड़ेंगी, वहीं अक्षय खन्ना फिल्ममेकर की ओर से वकील की भूमिका में होंगे। फिल्म को लेकर अक्षय ने कहा, 'इस फिल्म की कहानी काफी प्रासंगिक है, क्योंकि आप किस वर्ष में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बचाव पक्ष के हैं या अभियोग पक्ष के, आप न्यायाधीश हैं या आम इंसान, जो भी इंसान टीवी पर इस तरह की खबरों को देखता है और समाचार पत्रों में पढ़ता है, वह इस फिल्म से जुड़ेगा।' अभिनेता ने कहा कि इस फिल्म के जरिये हम लोगों को इस मुद्दे पर बहस कराना चाहते हैं। फिल्म अगले महीने की 13 तारीख को रिलीज होगी।

सितारों ने मनाया रक्षाबंधन

गुरुवार को रक्षाबंधन के अवसर पर कई सितारों ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। अभिषेक बच्चन ने बहन श्वेता और नैना बच्चन के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'ये दोनों बहनें हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं। ये हमेशा मेरे सपोर्ट में रहती हैं।' दूसरी ओर, संजय दत्त ने पत्नी मान्यता और दोनों बच्चों के साथ अपनी फोटो साझा करते हुए लिखा- 'प्यार का बंधन रक्षाबंधन।

वेबसीरीज रिलीज के लिए भी अहम है हॉलीडे

सार्वजनिक अवकाश और त्योहार पर फिल्म रिलीज को लेकर निर्माता पहले ही तारीख घाषित कर देते हैं। छुट्टियों पर रिलीज फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग मिलती है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की नजरें भी छुट्टियों की ओर हैं। हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न तो शुक्रवार की रिलीज का दबाव होता है और न ही बॉक्सऑफिस कलेक्शन का डर, फिर भी छुट्टी के दिन रिलीज को वहां भी बेहतर माना रहा है। दरअसल, भारतीय शो 'सेक्रेड गेम्स' के दूसरे सीजन को 15 अगस्त को रिलीज किया गया है। इस दिन स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की छुट्टी थी। शो रनर विक्रमादित्य मोटवाणी बताते हैं, 'सार्वजनिक छुट्टियों में ज्यादातर लोग घर में आराम करना पसंद करते हैं। ऐसे में उनके लिए वेब पर शो रिलीज करना फायदेमंद होता है। इसके अलावा, दूसरे सीजन में कहानी अममून दिलचस्प मोड़ पर खत्म होती हैं और पिछले भाग के कई सवालों के जवाब मिलने वाले होते हैं, उसे लेकर लोगों में जिज्ञासा बनी रहती है। कई ऐसे लोग हैं, जो सबसे पहले शो देखना चाहते हैं। ऐसे में अगर छुट्टी वाले दिन ज्यादा लोग देख पाते हैं।' विक्रमादित्य के मुताबिक, 'डिजिटल पर बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं है।

उत्साहजनक

स्पैरोथेका वंश की इस प्रजाति का नाम प्राचीन भारतीय राज्य 'मगध' के नाम पर 'स्पैरोथेका मगध' रखा गया है

झारखंड में मिली बिल खोदने वाले मेंढक की प्रजाति

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू: भारतीय शोधकर्ताओं को झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में स्थलीय मेंढक की बिल खोदने वाली प्रजाति मिली है। यह स्पैरोथेका वंश की मेंढक प्रजाति है, जिसे पूर्वी भारत में (नेपाल की दो प्रजातियों को छोड़कर) पाया गया है। स्पैरोथेका वंश के बिल खोदने वाले मेंढकों की 10 प्रजातियां दक्षिण एशिया में फैली हुई हैं। झारखंड में कोडरमा जिले के नवाडीह और जौनगी गांवों में कृषि क्षेत्रों के आसपास जैव विविधता की खोज से जुड़े अभियानों के दौरान वैज्ञानिकों को मेंढक की यह प्रजाति मिली है।

यह मेंढक स्पैरोथेका वंश का सबसे छोटा सदस्य है, जिसके थूथन की लंबाई लगभग 34 मिलीमीटर है। दक्षिणी बिहार के प्राचीन भारतीय राज्य 'मगध' के नाम पर वैज्ञानिकों ने मेंढक की इस प्रजाति को 'स्पैरोथेका मगध' नाम दिया है। इस मेंढक का सामान्य नाम बिलकारी (बिल खोदने वाला) मगध मेंढक रखा गया है।

इस मेंढक की संबंधित प्रजातियों में से कुछ नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाई जाती हैं। बिल खोदने वाले मेंढक समूह के वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में अस्पष्टता होने के कारण शोधकर्ताओं ने नई प्रजातियों का वर्णन करने के लिए 'एकीकृत वर्गीकरण प्रणाली' का उपयोग किया है, जिसमें रूपात्मक, वर्गानुवांशिक और भौगोलिक अध्ययन शामिल हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान (देहरादून), भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (पुणे), भारतीय विज्ञान संस्थान (बेंगलुरु), बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड कंजर्वेशन फाउंडेशन (सतारा) और बालासाहेब देसाई कॉलेज (पाटन, महाराष्ट्र) के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया यह अध्ययन शोध पत्रिका रिकॉर्ड्स ऑफ द जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया है।

स्पैरोथेका मगध आइएसडब्ल्यू

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक डॉ. केपी दिनेश ने बताया कि उभयचर जीवों से जुड़े अधिकांश अध्ययन वन क्षेत्रों में किए जाते हैं और शहरी उभयचर विविधता की ओर कम ध्यान दिया जाता है। उभयचर जीव पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले बदलावों के संकेतक के तौर पर जाने जाते हैं। किसी आबादी वाले क्षेत्र में उभयचरों की जैव विविधता से स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र में हुए बदलावों का अंदाजा लगाया जा सकता है। समय रहते इन उभयचर प्रजातियों का अध्ययन नहीं किया गया तो कई प्रजातियां जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण लुप्त हो सकती हैं।

शोधकर्ताओं का कहना है कि पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर में किए जाने वाले अधिकतर उभयचर अनुसंधानों के विपरीत, इस मेंढक प्रजाति की खोज मध्य भारत में भी जैविक अंवेषणों के महत्व को दर्शाती है।

डॉ. दिनेश ने बताया कि नई प्रजातियों के लिस्टिंग में जीवों का वर्गीकरण करने वाले प्रशिक्षित विशेषज्ञों की भूमिका अहम हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पैरा टैक्सोनोमिस्ट्स को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ अच्छी पहल की गई हैं, जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का ग्रीन स्किल डेवेलपमेंट प्रोग्राम और भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर कार्तिक शंकर द्वारा शुरू किया गया ओपन टैक्सोनोमिक इनिशिएटिव शामिल है।